SHORT DURATION DISCUSSION

Deficient reainfall, prevailing drought canditrions and plight of farmers in various parts of the country

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत महत्वपूर्ण इश्यु पर मुझे चर्चा प्रारम्भ करने का अवसर प्रदान किया है। देश में और खास तौर से उत्तर भारत में, नॉर्थ-वेस्ट में और पूरे मध्य भारत में सूखे के वजह से स्थिति बहुत विषम हो चली है। खास तौर से उन इलाकों में जहाँ धान ज्यादा पैदा होता है, वहां का किसान उसकी नर्सरी तैयार करने की स्थिति में भी नहीं है। महोदय, जब-जब सूखा पड़ता है, तो उसका असर न केवल मौजूदा फसल पड़ता है बल्कि उसके बाद वाली फसल पर उससे भी ज्यादा असर पड़ता है।

महोदय, हम लोग संसद के इस सदन में लगभग हर वर्ष कभी सूखे और कभी बाढ़ पर चर्चा करते हैं। यह स्थिति हर साल आती है। यहां सदन में बहुत अच्छी चर्चा होती है, सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन उन सुझावों पर कभी अमल नहीं हो पाता है क्योंकि यह कहा जा सकता है कि हमारे यहां खेती ज्यादातर मानसून पर निर्भर है, आकाश पर निर्भर है कि कब पानी बरसे, कब न बरसे, लेकिन फिर भी हम कुछ लॉग टर्म व शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स से किसानों को तात्कालिक राहत मिल सकती है और लॉग टर्म अरेंजमेंट्स के तहत सूखे की स्थिति से निपटने के लिए भी हमारे पास पानी के साधन होने चाहिए।

महोदय, अभी मौसम विभाग ने कहा है कि औसत से लगभग 45 प्रतिशत कम पानी बरसा है, लेकिन उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में यह कमी 55 और 61 प्रतिशत तक है। इसका परिणाम यह होगा कि न केवल यहां के रहने वाले लोगों और खास तौर से गरीब लोगों को बल्कि जानवरों तक के लिए पीने के पानी का संकट सामने आ जाएगा। इस देश के कई हिस्से ऐसे हैं, जहाँ इस का बहुत खराब असर पड़ रहा है। महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है और इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाता है। इस में पीने की दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि हमें इस स्थिति से निपटने के लिए कारगर उपाय करने होंगे। अभी हमारी नई गवर्नमेंट है और हमारे कैबिनेट व राज्य मंत्री दोनों किसान परिवारों से संबंधित हैं। वे बेहतर जानते हैं कि सूखे से किसान को किस तरह की दिक्कत पैदा होती है। महोदय, इस स्थिति में जल-स्तर इतनी तेजी से गिरता है कि ट्यूबवेल्स भी फेल हो जाते हैं, पीने के पानी के हैंड पंप पानी देना बंद कर देते हैं। इसलिए किसी भी गवर्नमेंट को पहला उपाय जल-संचय का करना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी आपदा आए, तो हम उस पानी का उपयोग कर सकें। इस तरह से पानी को रोककर पानी को रिचार्ज कर सकें और जब सूखे की स्थिति में जल-स्तर नीचे जाए, तो उस वाटर लेवल को नीचे जाने से रोका जा सके।

मुझे याद है, एक बार चिदम्बरम साहब ने बजट में प्रोवीजन किया था और कहा था कि हम रूपए दे रहे हैं जिससे तालाब खोदे जाएंगे... और पानी का संचयन किया जाएगा, जिससे जब कभी सूखा हो, तो उस पानी का उपयोग फसल के लिए, पीने के लिए किया जा सके और जमीन को रीचार्ज भी किया जा सके, ताकि वाटर लेवल नीचे न जाए और ट्यूबवेल्स, हैंडपंप्स जो खराब हो जाते हैं, वे खराब न हों, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। इसके लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहां से जो पैसा तालाबों के लिए दिया गया, तालाब जहाँ खोदे जाने चाहिए थे, नेचुरली जहाँ पानी इकट्ठा होने के लिए ढाल होता है, वहां कहीं तालाब खोदे नहीं गए। उस पैसे को यों ही बर्बाद कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि उसकी मॉनीटरिंग की भी व्यवस्था होनी

चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक फैसला दिया है, आपको मालूम होगा। जब इस देश का जलस्तर नीचे जाने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सन 1950 के बाद जहाँ तालाब थे, अगर उनके पट्टों को निरस्त किया जता है। कई जगह जब लोगों ने अपनी दरख्वास्तें जिलाधिकारियों के पास दीं, तो उन्होंने कहा कि तालाब जहाँ जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार कर दिया जाना चाहिए, बना दिया जाना चाहिए। मुझे मालूम है, कई जगहों पर बड़े-बड़े शहर बने, जहाँ बड़े-बड़े तालाब थे, उन पर बीस-बीस, तीस-तीस मंजिल की बिल्डिंग्ज़ बनीं, बिल्डर्स ने वहां पट्टे खरीद लिए, अपने नाम करवा लिए, गाँव में सब पट्टे हो गए, जो तालाब अभी बचे हुए हैं उनमें से नाले खोद कर पानी नदी में डाल दिया गया, यानी बारिश का पानी कहीं रोकने की व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी, जब तक जल संचयन की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक चेकडैम नहीं बनेंगे या जो बड़े-बड़े तालाब हैं उनमें पानी रोका नहीं जाएगा, बल्कि पानी नालों के जरिए नदी में डाल दिया जाएगा और नदी से समुद्र में चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति पैदा होगी कि जब सूखा होगा, तो आपके पास एक बूंद पानी नहीं होगा, जो आप खेती के लिए दे सकें या जानवरों के पीने के लिए दे सकें। हम देखते हैं कि हमारे यहां बुंदेलखंड में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। दस-दस किलोमीटर दूर से लोगों को पीने का पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिससे निपटने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

उपसभापति जी, दूसरा, इससे जुड़ा हुआ वनों का मामला है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहां पेड़-पौधे हैं, वहां सूखा नहीं पड़ता। अगर आप देहरादून चले जाएं, तो वहां पानी बरस जाता है। आज इतने बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई है, पेड़ों की कटाई हुई है और इसकी वजह से भी एक बड़ा जबर्दस्त एडवर्स असर पड़ा है। पूरे देश में जो विभिन्न जोन हैं, उनमें जो क्लाइमेट चेंजेज हुए हैं, उनकी वजह से भी असर हुआ है। तो वनों का काटना रूकना चाहिए, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होना चाहिए, तालाबों-जलाशयों को फिर से रेस्टोर किया जाना चाहिए, पानी को रोकने के लिए चैक डैम की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो सूखा पड़ेगा। अभी पानी नहीं बरस रहा है, इससे आपकी रबी की फसल को और ज्यादा दिक्कत होगी। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, ट्यूबवेल्स फेल हो रहे हैं। इससे यह फसल तो बर्बाद हो ही रही है, अगली फसल को और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि याद रखिएगा कि बाढ़ से तो मौजूदा फसल को नुकसान होता है और अगली फसल बेहतर हो जाती है, लेकिन सूखे से दोनों फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इस समय सारे देश में कहीं पानी बरस रहा है, कुछ जगह बरसा है, लेकिन पूरे उत्तर भारत में, पश्चिमी उत्तर भारत में मध्य भारत में पानी न बरसने से सूखे की स्थिति है, उस सूखे से निपटने के लिए आप किसानों के लिए किस तरह से क्या राहत दे सकते हैं, इस पर यह सदन विचार करेगा, सुझाव देगा, लेकिन मैं इसके लॉंग टर्म अरेंजमेंट की बात करूंगा। इसका निराकरण कैसे हो? इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेण्ट है कि जल संचयन कैसे किया जाए। किस तरह से पानी को रोका जाए, किस तरह से तालाबों के जरिये जल संचयन किया जाए। आपने देखा होगा कि राजेन्द्र सिंह ने राजस्थान में पानी को रोककर,एक चैक डैम बनाकर उस इलाके में जहाँ पानी नहीं होता था, ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अब वहां पानी की कोई कमी नहीं होती और फसल होने लगी। तो अगर आप पानी रोकने की व्यवस्था कर देंगे, बारिश का पानी जो हो, वह सीधा समुद्र में न जाए, ज़मीन रीचार्ज हो, वाटर टेबल नीचे न जाए, यह सबसे ज़रूरी है इस बात के लिए कि अगर सूखे जैसी आपदा आए तो उससे पर्याप्त पानी हो। इसके लिए जो संभव हो सके, वह गवर्नमेंट को करना चाहिए और सूखे से जो फसल का नुकसान हो रहा है, उसके लिए आदरणीय चेयर के माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि अब एन.पी.ए.बढ़ गया, 4 परसेंट हो गया और बड़े-

[प्रो. राम गोपाल यादव]

बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स का बहुत पैसा आप राइट ऑफ कर देते हैं, तो जो किसान पीड़ित हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, आप उनका कर्ज़ माफ न करें, लेकिन उसका ब्याज माफ कर दें, जो कर्ज है, उसके ब्याज को अगर आप माफ कर देगें तभी उनको कुछ राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको बहुत धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो एक-दो सुझाव मैंने दिए हैं, उन पर वे अमल करें ताकि आने वाले वक्त में सूखे की स्थितिमेंहमारेपासपर्याप्तपानीउपलब्धहो,किसानकोकोईदिक्कतनहोऔरआदमियोंकोकिसी तरह की कोई दिक्कत न हो, धन्यवाद।

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh) : Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I am fortunate that both the Agriculture Minister and the former Agriculture Minister are present when this Short Duration Discussion is taking place. Sir, the long period average for the Indian monsoon between July and September is about 89 cms of rainfall. Up to the 7th of July, which is the day before yesterday, the normal rainfall should have been about 22 cms. The actual rainfall is about 13 cms. So, there is 42 per cent deficiency as compared to the normal as of the 7th of July, 2014, Sir, this is the all-India figure. When you break down the all-India figure, you find that in Central India which is Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, parts of UP, parts of Jharkhand, the deficiency is as high as 64 per cent. The deficiency in the southern penisula is about 40 per cent; the deficiency in east and north east is much lower, at about 20 per cent, and the deficiency in north-west India which is Punjab, Haryana, Rajasthan, and Delhi is about 42 per cent. So, on an average, as of the 17th of July, the monsoon deficiency is 42 per cent. This is the all-India figure. Now if you look at the last 50 years, the bulk of the monsoon rainfall occurs between the 20th of July and the 30th of August. So, we are entering a danger zone. Today, we are on the 9th of July. We have about ten days. If this situation continues till the 20th of July, then we are in a very serious situation. So, what is needed to be done? In 2012, we had a similar situaton. That is why I am glad that Sharad Pawarji is present here today. In 2012, the Government of India, the UPA Government set up an Empowered Gorup of Ministers on Drought Management. I know that this Government is allergic to Group of Ministers and Empowered Group of Ministers. But the institution of the Empowered Group of Ministers under sharad Pawarji's chairmanship and comprising various Ministers took a large number of decisions which are relevant for managing this year's drought also. I would like to bring to the hon. Agriculture Minister's attention three important decisions which, I think, can be taken between now and the 20th of July so that when we are in the critical zone, we are better prepared to manage the drought. Sir, the first and the most important thing is the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. This is an Act that the Parliament passed in 2005. It guarantees 100 days of employment. But what was decided in 20 and continued thereafter, is that in all the draught-notified taluks and blocks, the guaranteed employment will not be 100 days but 150 days, and, in fact,

many States-Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh-took full advantage of this relaxation in the Mahatma Gandhi NREGA norms whch allowed for 150 days and the additional expenditure over and above 100 days was borne by the Central Government. This is very important. this was not shared with the State Government. The entire 50 days' additional employment came from the Central Government.

Sir, unfortunately, in the last one month, there has been a lot of uncertainty on Mahatma Gandhi NREGA. We read in the newspapers that the Rajasthan Chief Minister has written to the Central Government asking for Mahatma Gandhi NREGA to be scrapped. But in todauy's newspaper, interestingly, I read that the very same Rajasthan Chief Minister has told her officials to lobby with the Central Government for greater funds under Mahatma Gandhi NREGA for managing drought in her State. I would request the hon. Agriculture Minister to please end this uncertainty over Mahatma Gandhi NREGA. It is very unfortunate. Shri Gopinath Munde is not with us, but I know how committed he was to Mahatma Gandhi NREGA. Subsequently, unfortunately, after his most tragic demise, there is a big question mark on the future of Mahatma Gandhi NREGA. I think, this is the one policy, one programme, one instrument that the Central Government has in order to manage the drought more effectively. I request the hon. Agriculture Minister to impress upon his own Government that in all drought-notified taluks and blocks--these notifications are done by the respective State Governments--guaranteed employment in public works will be for 150 days and not 100 days and the cost of the additional 50 days would be borne by the Central Government. So, the money is not very large.

श्री विजय गोयल (राजस्थान)ः वसुंधरा जी ने स्क्रैप करने के लिए नहीं कहा।

श्री जयराम रमेश: अखबार में कई खबरें आयी हैं। राजस्थान की मुख्य मंत्री का खत आया है। ये सब खबरें छप चुकी हैं, गोयाल जी यह सब छप चुका है। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय गोयलः स्क्रैप करने के लिए नहीं कहा। ...**(व्यवधान)**... उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ऐक्ट के थ्रू ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: मै इस सरकार की नीतियों को सिर्फ ट्वीट और अखबारों के माध्यम से पढ़ता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय गोयलः उन्होंने स्क्रैप करने के लिए नहीं कहा। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: राजस्थान के मुख्य मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्री को खत लिखा है कि महात्मा गांधी नरेगा कानून को बंद कराया जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री वी.पी. सिंह बदनौर (राजस्थान)ः यह बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री भुपेन्द्र यादव (राजस्थान)ः आप गलत बात कह रहे हैं।

श्री जयराम रमेश: अगर आप उसका खंडन कर रहे हैं तो ठीक है। ...**(व्यवधान)**...

श्री वी.पी. सिंह बदनौरः यह सही नहीं है। किसी पेपर में नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि इसको ...**(व्यवधान)**... रीमॉडल करने की बात कही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: ठीक है। ...**(व्यवधान)**... Sir, can I continue?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, please. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: I am not making any allegation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is only referring to a newspaper report.

SHRI JAIRAM RAMESH: I am only going by the tweet which is the only means of knowing what the Government is thinking nowadays. So, I am not making any allegation.

श्री भुपेन्द्र यादवः किसी पेपर में नहीं है।

श्री जयराम रमेश: ठीक है।

श्री वी.पी. सिंह बदनौरः उन्होंने इसको रीमॉडल करने की बात कही है। ...**(व्यवधान)**... आप रीमॉडल को स्क्रैप ...**(व्यवधान)**... उन्होंने यह कहा है कि रीमॉडल किया जाए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : When your chance comes, you can speak. He is not yielding.

श्री भुपेन्द्र यादवः यह गलत है। यह सही नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

SHRI V.P. SINGH BADNORE: It is not a question of yielding. He cannot say something out of the blue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. V.P. Singh, you can reply when your chance comes. I will give you a chance.

श्री वी.पी. सिंह बदनौरः आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते। ...**(व्यवधान)**...

श्री भुपेन्द्र यादवः सर, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: सर, अगर राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह खत नहीं लिखा है तो ठीक है, आप उसका स्पष्टीकरण दीजिए।

श्री भुपेन्द्र यादवः खत लिखा है लेकिन आपकी इंटरप्रेटेशन गलत है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: मैं अखबारों में जो न्यूज़ छपी है, उसके आधार पर कह रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री वी.पी. सिंह बदनौरः आपने खत देखा है क्या? ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: आप इसका खंडन नहीं कर सकते हैं कि खत नहीं लिखा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री वी.पी. सिंह बदनौरः आपने खत देखा है क्या? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can reply later.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I am glad that the hon. Members from Rajasthan are getting very agitated. I am glad that they are very forceful in their advocacy of Mahatma Gandhi NREGA. I hope that the same advocacy will be done by their Chief Minister also. Sir, my first suggestion to the Agriculture Minister is that in the drought-notified *talukas* and blocks, 150 days of guaranteed employment be provided by the State Government and the cost of 50 days be borne by the Central Government. Sir, the second decision which was taken in September, 2012 by the Empowered Group of Ministers was on pasture land. This is very important because in a drought year, fodder shortage becomes very critical and it is particularly true of States like Rajasthan. So, what was done in 2012 was that the development of gauchar lands, development of pasture lands was taken up as a priority under MGNREGA and an advisory was issued to all the Starte Governments. Some State Governments actually startedd this work, and, I want to mention here a couple of examples like Karnataka, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. I think, this proved to be very useful in managing the fodder situation in 2013.

Similarly, I believe, in 2014, an advisory must go from the Central Government, particularly, from the Ministry of Rural Development, that the development of common grazing lands, development of pasture lands should be taken up so that fodder shortage does not become a casualty.

Sir, my third suggestion relates to drinking water. The Central Government has a programme called the National Rural Drinking Water Programme. Fifty per cent of the assistance comes from the Centre and fifty per cent is given by the States. I remember, in August-September, 2012, Sharad Pawar *ji* and I went to Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Haryana and Gujarat, and, we met the then Chief Minister of Gujarat as well, to discuss as to how the State could be helped by the Centre for managing the drought. This was the pro-active approach, not limited to just writing letters, sending circulars and issuing statements in the media. Actually, two Ministers went to six or seven States, met the respective Chief Ministers and took instantaneous decisions. One of the decisions which were taken was that the entitlement of the State Government under the National Rural Drinking Water Programme would be fast forwarded Normally, Sir, the assistance to the States is given in two instalments. Mr. Sharad Pawar and the Chief Ministers, including the then Chief Minister of Gujarat, believed that since drinking water is going to be a crucial element in managing drought, the Centre must give the assistance in one go, and, therefore, all norms were relaxed by the Empowered Group of Ministers and assistance was given to the State Government under the National Rural Drinking Water Programme. I request the hon. Agriculture Minister to follow a similar approach and ensure that the allocations meant for the States, particularly, the drought affected States, do not go in instalments but go immediately so that the works can be executed and drinking water can be provided to the affeted communities.

[Shri Jairam Ramesh]

Coming to my fourth suggestion, I would like to take forward what Ram Gopal Yadav *Ji* mentioned about revival of water conservation structures like check dams, dug wells, percolation tanks, water harvesting structures. These are all traditional water conservation bodies and this is one of the priority items under MGNREGA. In addition, as he mentioned, the former Finance Minister had announced a programme for revival and rejuvenation of traditional water harvesting bodies, and, I think, Sir, today, the immediate priority should be to do whatever can be done to ensure that the works relating to check dams, stop dams, percolation tanks or dug wells should be taken up in a very large way for managing the drought.

I want to give one example from Jharkhand. In Jharkhand, in the last two years, under the MGNREGA programme, almost 90,000 dug wells have been constructed, and, these are not paper dug wells, these are dug welll s on the ground. Full information is available in the public domain, and, each of the dug wells irrigates a command area of 1½ to 2 hectares and a one-crop farmer, in many instances, has become a two-crop farmer. So, I think, Sir, to summarise, give the fact that today, on the 9th of July, we have at the national level a 40 per cent deficiency in the rainfall. It is a very significant deficiency. We still have about 10 days to plan because the critical zone, as I mentioned, starts somewhere on the 20th of July. So, in the next ten days, if the Government of India were to move in these four directions that I have enumerated, increasing Mahatma Gandhi NREGA from 100 days to 150 days, accelerating the flow of funds to the State Governments under the National Rural Drinking Water Programme, revival of water conservation structures under Mahatma Gandhi NREGA and giving priority to pasture lands and grazing lands so that fodder does not become an immediate casualty, I think, we will be able to manage the drought much more effectively, as we did in 2012.

Sir, I want to make one final comment. The Indian monsoon is changed. We must recognize that the Indian monsoon today is not the Indian monsoon of ten years ago or twenty years ago. The overall rainfall has not changed. It still remains 89 centimetres. But the pattern of distribution of rainfall in response to climate change has changed. In fact, Sir, today-- when we were all growing up, when you were growing up, all your history books taught you, geography books taught you that Cherrapunji is the wettest place in India-- Cherrapunji is no longer the wettest place in India. So, climate change is changing the pattern of India monsoon. Dry days are increasing, days in which you get heavy rainfall are increasing and extreme events are increasing. We must recognize the realty of climate change and agricultural planning and agricultural crop planning must reflect the impacts of climate change. Shorter duration varieties, better agro-met services to farmes through modern techniques like SMS are the techniques that we have to adopt. And, I think, in the long run we must recognise that the Indian monsoon, like many things in India, has not remained the same. We must be in a better position to

predict the Indian monsoon. We must be in a better position to respond to the uncertainties of the Indian monsoon. I think, if these factors are kept in mind, Sir, we will be able to manage the drought. And I hope that by the 20th of July, rain gods will be kinder to us. But if they are not kind, the Government of the day, accompanied and associated by the State Governments, will have to take steps across the various directions that I have mentioned, and perhaps we can re-visit the situation once again. Sir, on the 9th of June this year, the Indian Meteorological Department issued a long range forecast. So, we cannot say we were caught by surprise. On the 9th June this year, we knew that we were going to face a 40 per cent deficiency in July, So, this is not something that is uncertain; this is not something that we were caught unaware. We knew on the 9th of June that we were going to have a deficiency, and I think it is the duty of the Government to respond to the information that becomes available on a real time basis. Thank you, Sir.

श्री भुपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, इस समय सदन में सूखे पर चर्चा हो रही है। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि देश के मानसून विभाग ने जिस प्रकार की संभावनाओं को व्यक्त किया है, उनको देखते हुए सरकार ने इस विषय पर काफी त्वरित कदम उठाए हैं। देश में मानसून के बदलाव के कारण बड़े पैमाने पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए इसको देखते हुए सरकार ने विभिन्न राज्यों के साथ संवाद की शुरूआत करके कंटिंजेंसी प्लान पर कार्य शुरू किया है। जैसा कि अभी माननीय राम गोपाल जी ने भी कहा कि जिस प्रकार अनिश्चितताओं से भरा हुआ मानसूनी व्यवहार हमारे देश के अंदर रहता है, उससे निपटने के लिए सरकार को दोनों प्रकार के विषयों, तात्कालिक और दीर्घकालिक पर कार्यवाही करनी चाहिए। जहाँ तक मानसून के देरी से आने की संभावना है, उसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के लिए चारा परिवहन,गौशाला, पशु शिविर का संचालन और पेयजल परिवहन आदि जो मूल समस्याएं हैं, जिनसे पूरा ग्रामीण क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित होता है, इन पर ध्यान देना चाहिए। यदि इन विषयों पर त्वरित कार्यवाही में थोड़ी देरी होती है, तो वह उचित नहीं है। यह आवश्यक है कि इन चीज़ों की उपलब्धता में किसी प्रकार का व्यवधान न आए और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी सहज उपलब्धता बनी रहे। सामान्यतः हम कभी-कभी बड़ी बातें करने लगते हैं, लेकिन आम आदमी, जो गाँव में बसा हुआ है, अगर उसके पशु के लिए चारे की उपलब्धता रहेगी, पेयजल परिवहन की व्यवस्था सुचारु रूप से बनी रहेगी और पशु संचालन की व्यवस्था बनी रहेगी, तो मुझे लगता है कि इस समस्या के जो तात्कालिक परिणाम हैं, जो तात्कालिक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, हम उनके निवारण हेतु एक अच्छे कंटीन्जेंसी प्लान के साथ खड़े रहेंगे।

जो दूसरा विषय है, वह यह है कि देश में "डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट, 2005" आया है। उसके बाद 2013 में इसकी गाइडलाइन्स भी इश्यू हुई हैं। राजस्थान जैसे क्षेत्र में पशु शिविर और जल परिवहन के लिए कई बातें हुई हैं। सूखे के बाद बारिश होने के बाद-चूंकि वह गंभीर सूखा नहीं होता है, इसलिए केवल 90 दिन तक ही प्लान रहता है। वास्तव में, मेरा यह मानना है कि यह जो पश्चिमी भारत का पशु आधारित क्षेत्र है, वहां पर रिलेक्सेशन देकर जल परिवहन और पशु चारे के लिए 90 दिन की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस पर तुरंत कोई निर्देश जारी करेंगे। आप कम से कम उन प्रदेशों में, जहां पर व्यक्ति के रोजगार के साथ-साथ पशु का रहना बहुत आवश्यक है, वहां पर इसका लाभ देकर भविष्य में आने वाली समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकेंगे।

[श्री भुपेन्द्र यादव]

अभी मनरेगा को लेकर एक प्रश्न उठाया गया था। मेरा यह कहना है और निवेदन भी है कि माननीय जयराम जी सदन के काफी सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन यह सच है कि इस संसद की पिछली स्थायी समिति की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मनरेगा कार्य काफी भ्रष्टाचारों के साथ चल रहा है।

(उपसभाध्यक्ष (डा.ई.एम.सुदर्शन नाच्चीयप्पन) पीठासीन हुए)

आपने भी अपने बयान में यह कहा था। यह कह देना कि 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है, काफी नहीं है। इसकी वास्तविकता यह है कि इस देश में, मनरेगा के अंतर्गत कभी भी औसत 50 दिनों से ज्यादा का रोजगार नहीं मिला। आपने जो राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री के पत्र को इस सदन में रखा है, अगर आपने उसकी मूल भावना को समझा होता, तो शायद यह विषय नहीं रखा होता। यह राजस्थान की परम्परा में रहा है कि राजस्थान का ऊपर का, गंगानगर, बीकानेर का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पर आज से सौ साल पहले, जब अकाल की स्थिति आई थी, तो वहां के स्थानीय शासक ने स्थायी रूप से एक निर्माण कार्य कराया था। यह कार्य आज गंग नहर, राजस्थान कैनाल के माध्यम से उस क्षेत्र को सर्वदा के लिए हरियाली दे रहा है। मनरेगा के कार्य में केवल मिट्टी को इधर से उधर कर देने या केवल मिट्टी के आधार पर जॉब कार्ड बना देने से हम देश में केवल कुछ लोगों को त्वरित रूप से लाभ दे सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर मनरेगा जैसे कार्य को चलाना है, यद्यपि उन्होंने अपने पत्र में यह नहीं लिखा कि आप इसको बदल दीजिए, परंतु वास्तविकता यह है कि जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया था, उस दिन उन्होंने अनुच्छेद 21 में केवल एक लाइन लिखी थी कि इस देश के सभी लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार होगा, आपको इस पर ध्यान देना होगा। वह अधिकार इन साठ सालों में दिया जाना चाहिए था, अधिकार के नाम पर नये-नये अधिकार नहीं बनाने चाहिए थे। हमें इस बात का विश्लेषण करना होगा कि हम क्यों अनुच्छेद 21 में लिखित सब के साथ सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार को पूरा नहीं कर पाए? हम क्यों इन साठ सालों में उन दीर्घकालिक विषयों को पूरा नहीं कर पाए, जिन दीर्घकालिक विषयों के अंतर्गत अभी तक स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण हो जाना चाहिए था? अभी माननीय राम गोपाल जी बहुत सही कह रहे थे कि जो तालाब हैं, पोखर हैं, वहां पर बड़े-बड़े बिल्डर्स ने अभी से कई प्रकार की बिल्डिंग्स बना दी हैं।

गुड़गाँव के जितने भी सेक्टर्स बसे हुए हैं,उन सबमें कभी तालाब हुआ करते थे। इस देश में ऐसा कानून पास होना चाहिए कि जो जल के स्वतः बहने के क्षेत्र हैं, वहां इस प्रकार की स्थाई परिसम्पत्तियों को निर्मित नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, तो अपने तालाब, पोखर और अपने देश की जल क्षमता को बचा कर रख सकेंगे। इस देश में सूखे से निबटने के लिए सरकार के द्वारा नदियों को जोड़ने का संकल्प किया जा रहा है। नदियों को जोड़ने से मानसून पर तो नियंत्रण नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इस प्रकार के संकट हमारे देश के अन्दर आते हैं, तो नदियों को जोड़ने से भविष्य में सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए कम-से-कम जल की उपलब्धता जरूर बनी रहेगी। मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इस समस्या को काफी त्वरित तरीके से पहचाना। उन्होंने अपने विभिन्न अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ संवाद करने के लिए भेजा है। इस देश में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में, बांदा में, चित्रकूट में मानसून के आने के बाद भी अभी तक स्थाई रूप से उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि जो ऐसे विशेष क्षेत्र हैं, राजस्थान भी उस विशेष क्षेत्र के अन्तर्गत

आता है, वहां पर स्थाई रूप से वर्ष भर जल परिवहन करने के प्रावधानों को एसडीआरएफ के अन्दर समाहित किया जाना चाहिए, जिससे वहां पर पीने के पानी की जो समस्या है, उसका स्थाई रूप से समाधान हो सके। इसलिए हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो तात्कालिक विषय है, जिसके लिए सरकार ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड बनाने की पहल की है, यह एक बहुत बड़ी पहल है, लेकिन इस पहल में स्थाई विषयों को भी सम्मिलित किया जाए और स्थाई रूप से समस्याओं का समाधान किया जाए। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि यह सदन एक बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहा है। इस विषय के कारण पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस विषय के माध्यम से आने वाले समय के संकटों को हम दूर कर सकें, तो अच्छी बात होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसका पूरा आश्वासन देंगे। धन्यवाद।

श्री ब्रजेश पाठक (उत्तर प्रदेश): महोदय, आज आपने मुझे देश के एक बहुत ही गम्भीर विषय पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है। सूखे जैसी विकराल समस्या हमारे देश में लगभग हर दूसरे-चौथे साल आ जाती है और इस देश में इससे प्रभावित होने वाला वर्ग लगभग 75 प्रतिशत है। खेती-किसानी के आधार पर आज भी हम भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं, लेकिन मानसून न आने के कारण, पर्याप्त बरसात न होने के कारण पूरे देश में समय-समय पर चिंताएं व्यक्त की गईं। इस वर्ष भी मानसून लेट आया। हमारे पूर्व वक्ताओं, जयराम रमेश जी, भुपेन्द्र जी और प्रोफेसर साहब ने बहुत ही विस्तृत रूप से मानसून के बारे में अपनी बातें रखीं, लेकिन मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस सूखे से, बरसात न होने से प्रभावित होने वाला जो वर्ग है, इस देश का जो कमेरा समाज है, जो अपने खून-पसीने की कमाई पूरे देश को खिलाने का काम करता है, सर्वाधिक प्रभावित वही होता है और उसके सपने टूटते हैं, लेकिन खेती-किसानी और सूखे पर चर्चा करने के बाद पिछले दिनों जब भी चर्चा हुई हम कभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि उस किसान के लिए हमने क्या किया। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, किसी विचारधारा से सम्बन्धित विषय नहीं है। मैं अपने भाई, भुपेन्द्र यादव जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का उल्लेख किया। जब बाबा साहेब ने हिन्दुस्तान की आजादी के बाद संविधान की संरचना की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा था कि सबको सम्मानपूर्वक बराबरी से जीने का हक होगा, लेकिन आज भी यह हक हम उन वंचित परिवारों को, उन दलितों को, उन पिछड़ों को, उन किसानों को नहीं दे पाए हैं, जो उन्हें मिलना चहिए। आज भी अगर कहीं चर्चा होती है, तो इकोनॉमिक जोन की होती है, सिंगल विंडो काउंटर सिस्टम की होती है। उन लोगों के बारे में कानून बनाने के लिए हमें बहुत तेजी रहती है, जो लोग इस देश में उद्योगपति कहे जाते हैं। उनके लिए हम सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, बिजली की समस्याएँ, जमीन देने की समस्याएँ, सारी समस्याएँ एक खिड़की के द्वारा सॉल्व करने का काम करते हैं। हमारे सदन में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय पवार साहब, जिनका बहुत लम्बा अनुभव है। हम सबको इस विषय में चिन्ता करके सोचना चाहिए कि अगर किसान ने हड़ताल कर दी, एक वर्ष के लिए उसने अन्न उपजाना बन्द कर दिया, तो इस देश की आर्थिक व्यवस्था का क्या होगा, फिर भले ही हमारा सेंसेक्स कहीं चला जाए, भले ही हमारी शेयर मार्किट कहीं चली जाए। अगर देश का किसान एक बार टूट जाएगा, तो देश बहुत ही चिन्तनीय हालत में पहुंच जाएगा। हमें इस विषय पर जरूर ध्यान देना चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने गाँव के दिनों को याद करते हुए एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं पढ़ता था, तो दोपहर में कभी-कभी हमको ट्यूबवेल पर खाना ले करके जाना होता था, जो लोग खेत में काम कर रहे होते थे, उनके लिए आज भी हालत वही है, जो 20 साल पहले थी।

[श्री ब्रजेश पाठक]

जब बरसात नहीं होगी, सूखे की स्थिति होगी, तो हमें डीज़ल पम्प का सहारा लेना पड़ेगा अथवा बिजली के ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ेगा। डीज़ल का आलम यह है कि उसका दाम आज 60 रुपये से भी अधिक हो गया है और एक घंटे में डीज़ल पम्प एक लीटर से भी अधिक डीज़ल ले लेता है। बिजली का आलम क्या है, यह सभी जानते हैं, क्षेत्र चाहे जो भी हो। अभी पिछले हफ्ते बिजली मंत्री पूरे देश के लिए परेशान थे कि बिजली नहीं है। उत्तर भारत में खास तौर पर बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में किसान को बिजली की समस्या से हमेशा दो-चार होना पड़ता है। जब देश में सूखा होगा तो बिजली की समस्या आएगी ही। बिजली की समस्या के सम्बन्ध में मैं आपको एक चश्मदीद के रूप में बताना चाहता हूँ, जाड़े के दिन थे, किसान का एक हाथ स्टार्टार पर था,उसकी पत्नी पानी की नाली में थी और बेटा फावड़ा लेकर नाली की मरम्मत कर रहा था। जितनी बार पानी स्टार्ट हो करके नाली तक पहुंचता था, उतनी बार बिजली चली जाती थी।

सर, आप किसान की हालत देखेंगे तो यह मालूम होगा कि शायद यह अपने देश का नागरिक नहीं है, सोमालिया जैसे किसी अत्यंत गरीब देश से जुड़ा नागरिक है, जहां पर लोग भूखे और नंगे रहते हैं। यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है।

सर, सूखे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों को कोई न कोई ऐसा निर्णय लेना होगा ताकि प्रभावित वर्ग को हम स्थायी रूप से कुछ समाधान दे पाएं। हमारे प्रदेश में बुन्देलखंड और महाराष्ट्र में विदर्भ जैसे क्षेत्र ऐसे हैं, जहां आज भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। पिछली सरकार ने बुन्देलखंड के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा बुन्देलखंड में आता है, वहां उसमें से लगभग 59% धनराशि खर्च की गई थी और जो हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है, वहां लगभग 80% धनराशि खर्च की गई थी। आज भी वहां की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बुन्देलखंड के लोग अपनी खेतीबाड़ी और घरों को छोड़-छोड़ कर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए आज भी हम आजीविका कोई उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं करा सके हैं। उनको हम स्वच्छ पेयजल तक उपलब्ध नहीं करवा सके हैं।

सर, मैं कई वर्षों से इस सम्बन्ध में चर्चा सुनता आया हूँ कि जल संरक्षण के लिए अगर नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो हम सूखे जैसी विकराल समस्या से निपट सकते हैं। अभी तक यह कार्य योजना केवल फाइलों तक ही सीमित है और हम किसी अन्तिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके हैं। मेरा सुझाव है कि अगर नदियों को आपस में जोड़ने की कोई ठोस योजना धरातल पर फली भूत हो सके, तो उससे किसान को जरूर फायदा हो सकता है।

सर, आज छोटी-छोटी बहुत सी ऐसी नदियां हैं, जो विलुप्त होती जा रही हैं। पिछले दिनों मैं किसी काम से जयपुर गया था। रास्ते में मैंने एक बहुत बड़ा सा पुल देखा, लेकिन पुल देखने के बाद मैंने यह देखा कि उसमें एक बूंद पानी भी नहीं हैं। कुछ देर के लिए मैं वहां रुका और मैंने उसके बारे में पूछताछ की। मुझे पता चला कि यह पुल बना जरूर था, लेकिन दस साल से इसमें एक बूंद पानी भी नहीं आया है, चूंकि नदी गायब हो चुकी है। इस तरह की कई नदियां हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें एक बूंद पानी भी नहीं है। वहां पुल बने हुए हैं, लेकिन नदी गायब हो चुकी है। रिवाड़ी में भी इस तरह का एक पुल है। अब छोटी-छोटी नदियों में बरसात का जल नहीं जाता है। ऐसी नदियों को हमें संरक्षित करना होगा और वैज्ञानिक रूप से उनको मैनेज करना होगा।

आज झीलें गायब होती चली जा रही हैं। तालाब पाटे जा रहे हैं। जिस ढंग से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, उसके लिए बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, बड़े-बड़े मकान बन रहे हैं और

फार्म हाउसेज़ बन रहे हैं। शहरों या गाँवों के आसपास कोई तालाब अब आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। जिसकी सरकार होती है, उसके संरक्षण में लोग ट्रकों को ले-ले करके, वहां कूड़ा डलवा देते हैं अथवा किसी अन्य तरीके से उसको पाट देते हैं और फिर प्लाटिंग करके उसको बेचने का काम कर देते हैं। हमें कोई ऐसा क़ानून बनाना होगा कि अभिलेखों में जो तालाब दर्ज हैं अथवा जो दर्ज नहीं हैं, उनकी जांच करवा कर उचित कार्यवाही की जाए। जहां तालाब है, अगर वह कागज़ों में दर्ज नहीं है, तो उसका बहाना ले लिया जाता है कि तालाब दर्ज नहीं है। तालाब तो पुरातन काल से, 200 साल पहले से चला आ रहा है, लेकिन उस तालाब को पाट करके भूमाफिया लोग उसे बेचने का काम कर रहें हैं। सर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि उन तालाबों को बचाने के लिए हमें कोई न कोई पहल करनी होगी।

सर, कुएँ तो आज बचे ही नहीं हैं। कुआँ तो एक सपने की बात हो गई है। त्यागी साहब, आगे हमारे जो बच्चे आएँगे, अगर हम उन्हें यह बताएंगे कि हम कुएँ से पानी निकाला करते थे, तो वे कहेंगे कि हमें क्यों मूर्ख बना रहे हो। क्या कोई हमारी इस बात को मानेगा कि कभी कुएँ भी हुआ करते थे? कुएँ के संरक्षण के बारे में कोई योजना हमारे पास आज तक नहीं आई है। कुएँ गायब हो गये। यह कहानी की बात हो गई कि कुआँ भी होता था। हमें जल संरक्षण के लिए विशेष रूप से कुओं का, झीलों का, तालाबों का और पोखरों का संरक्षण करना होगा।

सर, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके लिए आर्थिक पैकेज के लिए भी विशेष रूप से इंतजाम करना होगा। हम सब को उबारने का काम करते हैं। अगर कोई फैक्ट्री सिक हो जाती है, तो हम उसको स्पेशल पैकेज देते हैं कि चलो, अपनी फैक्ट्री को रिवाइव करो। सर, उसी तरह से किसानों के लिए भी हमें अलग से आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी होगी, कुछ मैनेज करना होगा और उनके लिए अलग से इंतजाम करने होंगे। किसान भाई जो ऋण लेते हैं, तो किसानों का सर्वाधिक ऋण उनकी फसल पर आधारित होता है। वे सोचते हैं कि जब फसल आएगी तो उसे बेचकर हम कर्जा अदा कर देंगे। लेकिन, जब फसल आती है, उससे पहले साहूकार खलिहान में डंडा लेकर पहुंच जाता है। किसान कभी-कभी गेहूँ का एक दाना भी अपने घर नहीं ले जा पाता। हमारे ढेर सारे साथी किसानी से जुड़े हैं, गाँवों से जुड़े हैं। उनको पता है कि छोटे-छोटे सीमांत कृषक होते हैं, जिनके पास एक, दो, तीन या चार बीघा जमीन होती है। अगर 10 बोरा गेहूँ हुआ, तो साहूकार पहले आ जाएगा। अगर साहूकार नहीं आया और उसने अगर सहकारी बैंक से लोन लिया है, तो आर.सी. की तलवार उसके सिर पर लटकती रहती है। तो उसके लिए ऋण माफी के बारे में भी सोचना होगा। सर, सहकारी बैंक के साथ-साथ हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, वहां से भी किसानों ने अगर सिंचाई के लिए, खाद के लिए या अपनी घरेलू जरूरतों के लिए लोन ले रखा है, तो हमें उनकी ऋण माफी के बारे में भी सोचना होगा।

महोदय, इसके साथ-साथ मान लीजिए कि एक फसल चली गई, तो जो आने वाली फसल है, उसके लिए हमें उन्हें उन्नत बीज देना होगा, खाद देनी होगी, बिजली देनी होगी, सस्ता डीज़ल देना होगा। सब्सिडी का डीज़ल तो किसानों को मिलना चाहिए। किसानों के पास खेती के साथ-साथ पशु भी रहते हैं। बैल, गाय, भैंस आदि के लिए हमें चारे का भी इंतजाम करना होगा।

सर, मैंने किसानों की ढेर सारी समस्याओं को आपके समक्ष रखा। मेरे बोलने का टाइम पूरा हो गया है, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सरकार से उम्मीद करता हूँ वह जरूर किसानों के लिए अलग से आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। इसके साथ ही, मैं अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस समय मैं यह सवाल उठा रहा हूँ, किसान आन्दोलन के दो बड़े नेता श्री शरद पवार जी और श्री राजनाथ सिंह जी सदन में मौजूद हैं। कृषि मंत्री जी जिस जिले से आते हैं, वहां महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में, चम्पारण में हुआ था। वहां नील के किसानों की जो तकलीफें थीं, उनका कुछ साया राधा मोहन जी के दिल और दिमाग में होगा, ऐसा कहकर मैं अपनी बात प्रारम्भ करना चाहता हूँ।

महोदय, पिछले सप्ताह का एक समाचार पत्र मेरे हाथ में है। इसमें लिखा है कि 'कृषि मंत्री ने सूखे की आशंका जताई: मौसम विभाग असहमत'। अब मंत्री महोदय का वक्तव्य है, चूंकि वे एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, इसलिए मैं उनकी बात को ज्यादा तरजीह देना चाहता हूँ। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि लगभग पांच सौ जिलों के सूखे से प्रभावित होने की आशंका है। मैं एक पुरानी रिपोर्ट देख रहा था, जिसमें श्री शरद पवार जी और श्री जयराम रमेश जी, इस सरकार से पहले वाली सरकार के अंतिम दिनों में उन सम्भावित जिलों और राज्यों का दौरा कर रहे थे, जहां पर सूखा पड़ने की संम्भावना हो सकती है।

अभी सूखे के बारे में हमारे दाएं-बाएं के कई साथियों ने बोला। एक बात तो यह है कि यह कोई राजनीतिक समस्या नहीं है। यह गांव के लोगों की, जो असली भारत है, उनकी सबसे बड़ी समस्या है। आजकल सूखे से जमीन में जो दरारें आई हैं, और पानी के इंतजार में जो किसान हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां आई हैं, उनकी शक्ल कम-से-कम एक जैसी है और निदान भी एक ही जैसा है। मैंने आज एक समाचार पत्र में देखा कि एक किसान आसमान की तरफ देख रहा है और जमीन चारों तरफ से फटी हुई है। तो फटी हुई जमीन का अक्स उस किसान के चेहरे पर झुर्रियों के रूप में आ गया है। लेकिन दुनिया इतनी बदल गई है कि कनॉट प्लेस में 24 घंटे यानी 24x7 फव्वारे चलते हैं और जिन इलाकों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, वहां पर इतनी गंभीर समस्या पैदा हो गई है, लेकिन जो सरकारी अफसर हैं, उनको मंत्री के आदेश को इम्प्लीमेंट करते हुए ऐसा लगता है कि उनके घर से कुछ खर्च हो रहा है। राधा मोहन जी एफर्ट करना चाह रहे होंगे, लेकिन जो मौसम विभाग है, जो विभाग के मंत्री हैं...। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय 43 परसेंट बारिश कम हुई है और जो बुआई है, राम गोपाल जी ठीक कह रहे थे, इसका बुआई से बहुत करीब का रिश्ता है, अब बुआई भी जून के महीने तक 35 परसेंट कम हुई है, जिससे हमारी अगली फसल तैयार होने का सिलसिला शुरू होता है। पेयजल के स्रोत समाप्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, मैं गृह मंत्री महोदय और कृषि मत्री महोदय, दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ, भुपेन्द्र जी भी अभी बैठे हुए थे, कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो पोखर,जो जोहड़, जो तालाब जिस स्थिति में थे, उनको status quo ante किया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप इसको इम्प्लीमेंट कराइए। इधर से लेकर उधर तक शायद ही कोई होगा, जो इसका विरोध करे। साहब, तालब जो थे, वे तो सूख ही गए। पाठक जी ठीक कह रहे हैं, तालाब कोई मामूली काम नहीं करते थे, यह हमारी जो ग्रामीण संस्कृति थी, जो भारतीय संस्कृति थी, जो हमारा असली भारत था,उसमें चार-पांच महीने पशुओं के पानी पीने की और रहने की एक मात्र जगह वही थी। आज सब पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने, ग्राम प्रधानों ने या उनके लठैतों ने कब्जा कर लिया है। यह पूरे देश की स्थिति है। हमारे मित्र गोयल जी यहां बैठे हुए हैं, दिल्ली देहात में हमारा जाना-आना होता है, वहां के सारे तालाबों पर कब्जा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए।

अब तक 60 से लेकर 99 परसेंट तक बारिश कम हुई है, तो आपके अधिकारी अब तक घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वे नहीं कर रहे हैं, तो आप आदेश दीजिए। वी.पी. सिंह जी, सूखे का

सबसे ज्यादा असर आपके प्रदेश पर है, बुंदेलखण्ड में है, विदर्भ में है और कर्नाटक के हमारे मित्र दाएं-बाएं बैठे होंगे, मैं अभी वहां की रिपोर्ट देख रहा हूँ, वहां बहुत बुरा हाल है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है कि drought situation is already existing in some parts on the national... अभी तक यह घोषणा नहीं हुई। चूंकि दो महान नेता, शरद पवार जी और राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आज आप यह घोषणा करें कि हमने देश के फलां-फलां डिस्ट्रिक्ट ड्राउट वाले घोषित कर दिए हैं। जब ये जिले ड्राउट वाले घोषित हो जाएंगे, तो वहां राहत कार्य शुरू हो जाएगा। उस पर भी मैं अभी आता हूँ।

राम गोपाल जी धान की बुआई का जिक्र कर रहे थे। धान की फसल उनके यहां भी होती है और हमारे यहां भी होती है। उसकी बुआई का वक्त निकल रहा है और मौसम विभाग सूखे की घोषणा करने को तैयार नहीं है। जो किसान परिवार में पैदा हुए हैं या जो गलती से गांव में भी पैदा हो गए हैं, वे जानते हैं कि सबसे ज्यादा पानी धान की खेती को चाहिए। लेकिन, ये चीनी मिल मालिकों को 11 हजार करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं। मेरा यह दुखता हुआ विषय है। ये भी दे रहे थे और आप भी दे रहे हैं और वह भी इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं। पांच लाख करोड़ रुपए का जो रिज़र्व है, उसको इनकी सरकार बड़े पूंजीपतियों को राहत पैकेज के नाम पर दे चुकी है। अगर ऐसा है, तो किसानों की मदद करने में क्या दिक्कत है? मुझे इस बात का कष्ट है कि जब दलितों का सवाल उठता है, तो हम साथ रहते हैं, माइनॉरिटी का सवाल उठता है, तो हम साथ रहते हैं, लेकिन जब किसानों का सवाल उठता है, तो दाएं-बाएं से उतनी मजबूत अवाज़ नहीं आती है, जितनी आवाज़े उन सवालों पर आती हैं।

श्री विजय गोयल: त्यागी जी, यह तो हम किसानों के लिए ही दे रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री के.सी. त्यागी: आपका यह इंटरवेंशन मुझे अच्छा नहीं लगा। **...(व्यवधान)...**

श्री राजपाल सिंह सैनी (उत्तर प्रदेश): क्या किसानों की पेमेंट हो पा रही है? **...(व्यवधान)...**

श्री के.सी. त्यागी: मैं भी वही कह रहा हूँ। **...(व्यवधान)...** लेकिन गोयल जी, आपको क्यों दर्द हो रहा है, मैं तो अपनी तकलीफ सुना रहा हूँ। यह कोई एंटी-बीजेपी बात नहीं है। ***...(व्यवधान)...***

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN) : Kindly address me, and your time is over.

श्री के.सी. त्यागी : आपको पता है कि गांव की क्या तकलीफ है ? **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN) : Your time is over.

श्री के.सी. त्यागी : गोयल जी, अगर आपको अप्रिय लग रहा है, तो मैं बैठ जाता हूँ। **...(व्यवधान)...**

3.00 P.M.

हमने तो आपके साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तब तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि बैठ जाओ। जे.एस. सन्धू साहब कृषि आयुक्त हैं, वे कह रहे हैं कि 15 जुलाई तक इंतजार करो, यानी कि धान भी न बोया जाए और अन्य फसलें भी बरबाद हो जाएं। आप जानते ही हैं कि इससे भाव कैसे बढ़ते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Tyagiji, your time is over. Please try to conclude it quickly. ...*(Interruptions)*... Yes, it is very important but we have to confine ourselves within the time-limit.

श्री के.सी. त्यागी: मुझे पता है कि यह विषय कुछ लोगों के लिए अप्रिय है, तो मैं अपनी बात कम कर देता हूँ। बुंदेलखंड, गुजरात, विदर्भ, महाराष्ट्र, सीमान्ध्र, तेलंगाना, ओडिशा, यूपी के कुछ हिस्से **...(व्यवधान)...**

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र)ः त्यागी जी, विदभ और महाराष्ट्र एक ही है। **...(व्यवधान)...**

श्री के.सी. त्यागी: अच्छा, ठीक है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN) : Please don't interrupt.

श्री के.सी. त्यागी : राजस्थान और देश के ऐसे कई हिस्से हैं, जहां पर पशुओं के चारे की समस्या भी पैदा हो गई है। पशुओं के चारे के कारण क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं? जब पशुओं का चारा तीन या चार गने रेट पर ब्लैक में मिलेगा, तो दूध की कीमत भी बढ़ेगी। ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। मैं इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के खिलाफ नहीं हूँ। फ्रैट कॉरिडोर बन रहे हैं, इसका बहुत स्वागत है। नया हिन्दुस्तान बने, इसका बहुत स्वागत है। हम 68 सालों में इस देश की सिर्फ 45 परसेंट जमीन को इरिगेटेड कर पाए हैं और 55 परसेंट राम भरोसे है। पानी बरसेगा तो वहां खेती-बाड़ी होगी, वरना नहीं होगी। इसलिए मेरा मंत्री महोदय, दूसरे बड़े मंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय से भी यह निवेदन है कि जिस तरह से आपने नेशनल हाइवेज़ वगैरह के कार्यक्रम बनाए हैं, उसी प्रकार आप एक नेशनल इरिगेशन कार्यक्रम भी बनवा दीजिए, आपको आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। कहीं भी पानी का इंतजाम नहीं है। कुल 45 परसेंट जमीन पिछले 68 सालों में सिंचित हो पाई है। हालांकि आज भी गेहूँ, चावल और चीनी के मामले में हम दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देश हैं, लेकिन कल्पना कीजिए, जब शत-प्रतिशत जमीन इरिगेटेड होगी तो भारत कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। यह कल्पना आप लोग भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): I am sorry, Mr. Tyagi, your time is already over.

श्री के.सी. त्यागी: बस, अब मैं समाप्त कर रहा हूँ, सर। मैं अपनी तीसरी बात पर आ गया हूँ। जब सूखा हो गया है, जिसकी घोषणा शायद आज आप अपने अधिकारियों की मर्जी के बावजूद भी करेंगे, तो मंत्री महोदय से मेरे दो-तीन निवेदन हैं कि एक तो आप कर्ज़ वसूली रुकवा दीजिए और अगर आप यह कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा। मैं सब किसानों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जिन किसानों के इलाकों में सूखा पड़ा है, उन सारे किसानों के कर्ज़े माफ कीजिए। आज मैं आन्ध्र प्रदेश की रिपोर्ट पढ़ रहा था। वहां के मुख्य मंत्री महोदय कई हजार करोड़ रुपये के कर्ज़े माफ करने की घोषणा कर रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay, thank you. I have to call the next person also.

श्री के.सी. त्यागी: मैं चाहता हूँ कि वैसे इलाकों के लिए आप भी ऐसा ही करें। आप सस्ते चारे की व्यवस्था कराइए। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि डीज़ल सस्ता मिले और यह ब्लैक न हो। पब्लिक

डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम, जो कि गरीब लोगों के लिए है, इसमें किसानों और non-agriculturalists के लिए भी व्यवस्था कराइए। मैंने तालाब के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में कहा, उसको इफेक्टिवली इम्प्लिमेंट करवाइए। अभी जयराम रमेश जी "मनरेगा" के बारे में बता रहे थे। यह लाइफलाइन है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। इस संबंध में सीएजी की रिपोर्ट है और मैं उसको गलत नहीं कहता। दो दिन काम हो रहा है और 100 दिनों के काम पर अंगूठा लगवाया जा रहा है। इसके लिए कोई effective implementing machinery नहीं है, यह मैं मानता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay, thank you.

श्री के.सी. त्यागी: अभी थैंक्यू में आधा मिनट और है, सर। इसी प्रकार, तालाब और जोहड़ के अलावा जल-संचयन का काम भी होना चाहिए।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह केवल इस साल का काम नहीं है बल्कि यह हर वर्ष का काम है। देश में जो भयंकर सूखे आए हैं, उनका इतिहास बताकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। वर्ष 1877, 1899, 1918, 1972, 1989 और 2002 में सूखे पड़े हैं। इस देश में ऐसा सूखा भी पड़ा है कि जब बंगाल के किसानों ने यह तय किया कि भूखे से रिस-रिस मरना है, बगैर भूख के मरना है या जो गोदाम हैं, उनको लूटकर खाकर मरना है तो उस जमाने में देश के जितने गोदम थे, उनको उन्होंने लूटकर अपनी जान देना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने भूखे से मरना स्वीकार नहीं किया। इसलिए ऐसे हालात न आएँ, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस संबंध में कुछ इफेक्टिव कदम उठाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI A.W. RABI BERNARD (Tamil Nadu): Hon. Vice-Chairman, Sir, I rise to share the concern of this august House about the terrible drought our country is facing and request the Government to take remedial measures on a war-footing and take long-term measures to mitigate this recurring national calamity.

Agriculture sector contributes 17 per cent to our GDP, employs about 60 per cent of the labour force and provides around 11 per cent of the total exports. And, we depend heavily on rainfall to feed 1.3 billion fellow citizens. Over 68 per cent of agriculture area in India is considered to vulneable to drought. Agriculture sector faces greater risk and uncertainty than any other sector of the economy due to highly unreliable climatic factors. Drought is one of those factors which adversely affected agriculture and livestock. This recurring climatic risk directly affects farmers and their incomes. As per the warnings of Inter-Governmental Panel on Climate Change, the El-Nino effect over the Indian Sub-Continent will be severe this year. And, this is nothing new to this ancient country. An analysis of 100 years of rainfall data reveals that the frequency of "below normal" rainfall in arid, semi-arid and sub-humid regions, which are mainly in the penisular and Western India, is 54-57 per cent while severe and rare droughts occur once in every 8-9 years in these areas of the country. We shall keep this fact in mind as we discuss ways to mitigate this year's drought. Economic data about the nation-wide drought in a typical draught-like situation should push us towards a permanent

[Shri A.W. Rabi Bernard]

arrangement to meet drought conditions. In a typical drought, the total loss in rural employment due to shrinkage of agriculture operations was estimated at 1,250 million man-days. the estimated loss of agricultural income was around ₹ 50,000 crores. We were producing 40 per cent of our electricity from hydro electric stations in the early 60s and now it is about 15 per cent in normal year due to non-availability of water. Deficit rainfall alone cannot be called as drought. It is generally classified into three kinds. The first one is meteorological drought, which is deficiency in rainfall when compared to average mean annual rainfall in an area. The second one is agricultural drought, which is insufficient soil moisture to meet the needs of a particular crop at a particular point in time. And, the third one is hydrological drought, which is deficiency in surface and sub-surface water supply. Slowly, India is facing all these three classifications of drought regularly and nation-wide, repeatedly. The principle cause of drought may be attributed to the erratic behaviour of monsoon. A host of other reasons, mostly manmade, aggravate drought. The rapid depletion of forest cover is also one of the reasons for water stress and drought. Natural clamities like drought should be dealt with in a comprehensive and holistic manner for ensuring economic security and livelihood of the people. A drought like situation add to the difficulties of the water starved States like my State Tamil Nadu. Hon. Madam Chief Minister, Amma Jayalalithaa, declared the State as drought-hit in 2012-13, and excluding Chennai, all other districts were provided with massive drought relief. Around 21.42 lakh farmers were given drought relief of ₹ 2,002 crores by hon. Amma. for the first time in the country, farmers were given drought relief of such a huge proportion. This year, 2014-15, Madam Chief Minister Amma's Government has sanctioned Rs. 681 crores for tackling drinking water problem alone. Amma has been conducting a series of review meetings to oversee drought relief programmes. Amma's Government has initiated a multi-pronged scheme to supply fodder. Government of India should come forward to enhance the drought relief programmes of hon. Amma's Government in Tamil Nadu.

Drought mitigation measures should be launched on a war footing, in a sustainable manner and not as a crisis management or a fire fighting short-term activity. Groundwater recharging should get top priority. Drought-resistant high-yielding crop varieties should be used. We can take some ideas from countries like Israel. Israel is more than two-thirds of desert. But Israel does not have water problem. They use technology to solve it in recycling, in desalination, in deep drip irrigation and so on. These technologies could be implemented at least in a few select States initially and the Centre should provide adequate funds for the States which are keen in adopting these technologies. Desalination on a major scale will provide big relief. Israel is also a leader in recycling water. Today, over 80 per cent of Israel's purified sewerage water goes back into agricultural use.

Considering the role livestock plays in the livelihood security of small and marginal farmers, the Government should create cattle conservation programme nation-wide. Our emphasis has to be more towards simple technologies to harness rainwater. Hon. Madam Chief Minister of Tamil Nadu launched a vigorous rain water harvesting programme in 2002. Recently, hon. Prime Minister of India acknowledged in Parliament the wisdom of such a unique programme.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mr. Rabi, plwase conclude.

SHRI A.W. RABI BERNARD: Every village in India can be rendered drought-proof and its water needs can be met if rain water is captured during good monsoon years and stored in tanks or used to recharge ground water. Through the traditional wisdom, through simple technologies, through the able guidance of hon. Amma, through a compassionate approach towards the humble farmer, let us together face this drought and save the nation. Thank you, Sir.

SHRI C.P. NARAYANAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I join my previous speakers in pointing out that the drought which is affecting us is very serious. But we have to note that in this century, this is the fourth time that we are having a drought. In 2002, 209, 2012 and now in 2014, we are having drought. Earlier, a 100-year data shows that we had cycles where droughts repeated in the course of 15 years, 25 years, 40 years, like that But, cutting across these cycles, we now have got shorter cycles where droughts are repeated. This is because of the climate change which already has come to affect us, as Dr. Pachouri has pointed out a few years back. I think, we have to intervene at micro as well as macro-levels. Rains are coming on the basis of macro changes or macro activities at the global level. But, at a place, the rainfall is much higher or much lower because of micro level conditions. So, we have to take care of both these two aspects.

Sir, before going into those things, let me first mention the immediate steps we have to take, which my other learned friends have already mentioned. We have to take care of our rural people, farmers, agricultural workers and other rural workers who are going to be seriously affected because of the drought. In certain States, the deficiency of rains so far is so high as 90 per cent, whereas in some other States, it is only about 20 per cent, and on an average, in the country as a whole, it is 43 per cent. Even in States like mine or Gujarat or West Bengal, from district to district, there are big variations in rainfall. So, we have to take all these things into consideration when we are planning to address the impact of drought. The Central Government and the State Governments have to give priority, this year, to protect our agriculture, like food grains, cereals, pulses, oilseeds, vegetables, fruits, and also fodder, which Shri Jairam

[Shri C.P. Narayanan]

Ramesh particularly mentioned. So, for drinking purposes and for irrigation purposes, we have to use the limited quantity of water available with us in a very planned and imaginative manner. Then only will we be able to overcome the drought that is affecting us. Now, that drought has come. In what way can we preserve the water? We have to see it to what extent we can make use of NREGA. That cannot be used in the same way in all the States. In semi-arid areas or in arid areas or in wet areas, in different parts of the country, if we apply the same norms, which Shri Jairam Ramesh's Department used to do and even our Planning Commission used to insist upon, then, it will not help. We have to put a stop to it, and allow States and even local Governments to make use of NREGA and other such measures in ways that are effective in particular situations and at particular places. Unless we do that, we may not be able to achieve much. We may spend crores of rupees, but not with efficiency and advantage we want no achieve.

Sir, the second thing is this. When we are introducing NREGA and other measures, we have to ensure that our agricultural production is not affected to a great extent because if it is affected, and if water is not available, then, all our plans to achieve high rates of GDP growth will be like writing in water. So, if we want to ensure that GDP grows, then, we have to ensure that agriculture grows and all those depending on agriculture grow and water is used in a prudent manner in various sectors, particularly in this year of drought.

Sir, I have to mention two more things. For the farmers, we have to make available seeds, fertilizers and other things which they need and also remunerative prices. In certain parts of our country, the sowing starts as early as in May, and in certain other parts, it goes up to as late as July or early August. So, for those farmers who have already sown and the seeds have been lost, the seeds, fertilizers and other pre-requisites have to be given at low rates or even free, if it is needed. So, the Government has to take care of that.

Secondly, to ensure work for agricultural labourers as well as the rural people who are engaged in other areas, the NREGA and other projects have to be effectively implemented. We have to see that usually with a drought prices will be increasing. *(Time-bell rings)* I will stop. In order to prevent that we have to ensure that black-marketing and hoardings are put down very effectively and public distribution is made effective and widespread. Finally, what I have to say is that in May our Meteorological Department said that this year we are going to have a normal rainfall. We have our monsoon first in Andaman, Assam and then in Kerala. In May, as per newspaper reports, the Meteorological Department was saying that we will have a normal rainfall. Only in the month of June, they came to know that it might get delayed *(Time-bell rings)* I will finish. So, our Meteorological Department should be equipped to give us a

reliable warning early enough, not in middle or late June but in the month of April or May. There are various methods available to do it. Science and technology has developed in order to help us. We have to avail of that knowledge. If our scientists and technologists do not have this scientific knowledge, they have to get it and use it. Otherwise, we will be giving this warning very late. That is to be avoided. Thank you.

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha): Thank you very much, Sir, for giving me the opportunity to say a few lines on this grave situation our country is now faced with. Sir, I want to bring to your notice that after 68 years of independence, our agriuclture is still mainly dependent on monsoon. If monsoon fails, the agriculture fails. The failure of agriculture affects food production. During the British time continuous failure of monsoon created famines when millions had died. In India that phenomenon is not completely eradicated. Nowadays climate change has become a regular phenomenon. This year there is 40 per cent deficit of rain in many parts of our country. There is drought in different parts of India. Odisha is one of those States. In Several districts of our State, *kisans* are in despair, so also the agricultural labourers. The fields are now dried. The seeds sown by the peasants in the fields are destroyed due to drought. If there is no rain in the coming months, there will be complete failure of crops. The farmers are already in distress. There are deaths of lakhs of farmers in our country. This figure will be multiplied if this situation continues. Knowing well that the climate is changing, the Centre and the State Governments have not taken necessary permanent preventive measures to face the shortage of rain. We are giving importance to industry. I am not against it. We must understand that without the development of agriculture, we cannot achieve development of other sectors of the country. We must spend more on irrigation including traditional irrigational systems in our rural areas. The Centre should help the States to build necessary preventive measures to solve the drought problem when it occurs at some intervals of four or five years.

The water tanks, which Prof. Ram Gopal Yadav and other friends have mentioned, were very much there before we achieved independence. That indigenous system of water harvesting and the canal system have destroyed in many parts of our country due to negligence of the Governments. As the climate is changing, in the coming years, we may have to face the problem of water shortage and rain shortfall. The State Governments and the Central Government should seriously think over it. Let us build up our irrigation system and other necessary systems. The forests are being destroyed. It is affecting the climate. It must be ensured taht more and more forests are grown in the country. Secondly, due to shortage of rainfall, the underground water level is depleting very fast. That should be prevented. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Your time is over. ...*(Interruptions)*... You will have to conclude it. ...*(Interruptions)*...

SHRI BAISHNAB PARIDA: We must increase the forest coverage. My State Government, under the leadership of Shri Naveen Patnaik, has taken a lot of measures to face the possible shortage of rain. The crops, in many of our districts, have destroyed. Therefore, our State Government is providing new seeds and loans to farmers. The irrigation system is being developed.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

We are trying to make more and more channels available for agriculture. Therefore, in view of the present situation, I would like to request the Central Government to provide necessary help to the State Governments so that they face this situation. If the shortfall or rains continues, it will affect the generation of electricity also. We, in our State, are already facing this problem. Therefore, I request the Central Government to assess the whole situation in the country and help the State Governments. Through the State Governments, the Central Government should provide necessary help to the farmers. A permanent mechanism should also be built up to face a drought-like situation in our country.

श्री शरद पवार (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, आज देश के सामने जो सूखे की परिस्थिति पैदा हुई है, इसकी चिंता पूरे देशवासियों को है। जयराम रमेश जी ने मानसून के बारे में जो स्थिति यहां दी, वह एक तरह की चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि जून महीने में जब मानसून की शुरुआत होती है, उन्हीं तीस दिनों में इस देश में माइनस 43 परसेंट मानसून है। 7 जून से 7 जुलाई तक हमने जो स्थिति देखी, इस काल में 42 प्रतिशत डेफेसिट है। इसका डायरेक्ट असर सोइंग ऑपरेशन पर, बुवाई पर होता है। मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। पिछले कई सालों के आंकड़े आपने देखे। जनरली इस महीने में कल की तारीख तक हमारे देश में 24 मिलियन हेक्टेयर में सोइंग ऑपरेशन का काम पूरा होता है। राज्य सरकार से जो इन्फॉर्मेशन मिली, इससे एक बात साफ हो गई कि इस साल as against 24 million, 17.5 million hectare में सोइंग आपरेशन पूरा हुआ है। यही परिस्थिति कंटिन्यु रहेगी, तो शायद धान की फसल पर, सीरियल्स पर,पल्सेज पर, ऑयलसीड्स पर कुछ बुरा असर होने की संभावना को हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।

इस समय जो सूखे परिस्थिति पैदा हुई है, वह परिस्थिति कई राज्यों में पैदा हुई है। अपने देश में कहीं न कहीं जिलों में या कहीं न कहीं राज्यों में हर साल सूखे की परिस्थिति पैदा होती है। मगर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है,उससे वैस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वैस्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नार्थ कर्णाटक, तेलंगाना और कुछ एरियाज़ में पानी की कमी की समस्या लोगों के सामने आई है। मेरे पास हर राज्य के जो रिज़र्वायर हैं, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आज पानी की स्थिति क्या है, इसकी इन्फॉरमेशन मेरे पास है। मेरे खुद के राज्य में क्या स्थिति है, उसको मैंने देखने का प्रयास किया है। इसको देखने के बाद एक बात स्पष्ट होती है कि जो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें कमी नहीं थी। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, वहां कुछ रीज़न्स हैं मराठवाड़ा रीज़न जिसे औरंगाबाद रीज़न बोलते हैं। Once upon a time it was a part of Nizam of Hyderabad. Then, Nagpur region. Once upon a time it was a part of Madhya Pradesh. Thirdly, Amravati region; it is also a part of Vidarbha. Then, Nasik region; it is also a part of Eastern Maharashtra. Then, Pune

regio; it comes under Western Maharashtra. वहां की क्या स्थिति दिखाई देती है। पूना रीज़न मेंजो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स है, in Pimpalgaon Joge which is one of the largest irrigation projects, live storage is zero per cent. Manikdoh which is one of the biggest irrigation projects, live storage if four per cent. Dimbhe which is one of the biggest irrigation projects, live storage is six per cent. Khadakwasla Varasgaon which is also one of the biggest projects, live storage is zero per cent. Chaskaman project, it is one per cent. Ghod project, it is zero per cent. Gunjwani project, it is ten per cent. Nira Devghar, it is two per cent. Bhatghar, it is three per cent. Veer, it is zero per cent. Bhima Ujani which is the third largest project in Maharashtra, it is zero per cent. तो सभी रीज़न्स के आंकड़े देखने के बाद एक बात सामने आ रही है कि आज रिज़र्वायर में पानी की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। अगर यही स्थिति कंटीन्यू रहेगी, बारिश में या मानसून मे कोई सुधार नहीं होगा, तो सबसे बड़ी समस्या ड्रिंकिंग वाटर की शुरू होने वाली है। इसलिए इस स्थिति पर हमें गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक आई.एम.डी. की रिपोर्ट है,उसमें उन्होंने जो कुछ बातें सामने रखी हैं, इससे शायद परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है, इस तरह की उनकी सूचना है। हमारे कुछ साथियों ने यहां पर आई.एम.डी. की रिपोर्ट के बारे में कहा और एक आशंका लोगों के मन में है, लेकिन मेरे कई सालों का अनुभव यह है कि आई.एम.डी. की जो रिपोर्ट है, वह सत्य से बहुत दूर नहीं होती, उसमें दो-चार परसेंट का इधर-उधर फर्क पड़ता है, मगर by and large उनकी रिपोर्ट में हमें एक अच्छी तरह की दिशा दिखाई देती है। आज भी वे यह कहना चाहते हैं कि इसमें सुधार होने की संभावना है। तो शायद परिस्थितियों में सुधार हो सकता है। यदि सुधार हो जाएगा, तो शायद परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। आज हमें कुछ न कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, हमें कुछ न कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है। जिन जिलों में यह परिस्थिति पैदा हुई है, मुझे विश्वास है कि कृषि मंत्रालय ने हर जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार किए होंगे। उन डिस्ट्रिक्ट प्लान में क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, शायद राज्य सरकार को विश्वास में लेकर उन्होंने इसकी तैयारी की होगी। परिस्थिति में थोड़ा बदलाव आएगा, तो क्या हम सेकन्ड टाइम की बुवाई कर सकते हैं, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। शायद इसके लिए बीज की ज्यादा आवश्यकता होगी। उसका स्टॉक हर क्षेत्र में कहां तक है? जहां कमी है, वहां हम दे सकते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ रबी में हमारी परिस्थिति में कोई बदलाव आएगा, मानसून में कोई सुधार आएगा, हम रबी का क्षेत्र कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी तैयारी भी अभी से करनी चाहिए। खरीफ में जो शॉर्टफॉल हो जाएगा, क्या हम इसकी भरपाई रबी में कर सकते हैं, या समर क्रॉप में कर सकते हैं, हमें इस पर ध्यान देना होगा और हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे देश में पिछले कई सालों से कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार के सहयोग से कई अच्छे कदम उठाए गए हैं। इससे हमारे देश का उत्पादन बढ़ा है। जहां तक अनाज की स्थिति है, मुझे विश्वास है कि हमारे सब भंडार भरे होंगे और आज देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। हम आज देश की जरूरत पूरी कर सकते हैं। हम दुनिया के देशों में अनाज भेजते हैं। आज इंटरनेशनल ग्रेन मार्किट में हिन्दुस्तान एक महत्व का देश बना है। इस साल दुनिया में हिन्दुस्तान चावल के एक्सपोर्ट में एक नम्बर का देश हो गया है और गेहूं के एक्सपोर्ट में भारत दूसरे नम्बर का देश बना है। दुनिया में चीनी के एक्सपोर्ट में भारत का दूसरा नम्बर है। कई ऐसे आइटम्स हैं, जिनमें हिन्दुस्तान के किसानों का योगदान बहुत है और राज्य सरकारों का भी सहयोग बहुत है। एक समय ऐसा भी था, जब देश के कुछ ही राज्यों में अनाज के उत्पादन की स्थिति हमेशा

[श्री शरद पवार]

अच्छी होती थी और कई राज्यों में अनाज के उत्पादन की स्थिति अच्छी नहीं होती थी। हम जब अनाज के उत्पादन के बारे में सोचते थे, तो हमेशा हमारे सामने पंजाब और हरियाणा का नाम आता था। यह बात सच है कि पंजाब का योगदान बहुत है, हरियाणा का योगदान बहुत है और वैस्टर्न यूपी का योगदान भी बहुत है तथा इसी प्रकार धान के क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश का भी योगदान बहुत है। स्थिति में जो बदलाव आया है, यह बदलाव अच्छा है कि कई नए राज्य अब हमारे सामने आए हैं, जो देश के भंडार में योगदान देने के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ खड़े रहने के किए तैयार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ एक जमाने में पिछड़ा हुआ स्टेट था। धान के उत्पादन में देश के भंडार में, राइस देने में छत्तीसगढ़ आज आगे आ गया है। छत्तीसगढ़ के साथ-साथ ओडिशा ने भी यह काम किया है, वेस्ट बंगाल ने यह काम किया है। हम हमेशा सोचते थे कि गेहूं का उत्पादन हमेशा पंजाब, हरियाणा और वैस्ट यूपी में होता है मगर आज मध्य प्रदेश ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और देश के भंडार में गेहूं की बढ़ोतरी करने में मध्य प्रदेश के किसानों और वहां की राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है, इसलिए परिस्थिति में बदलाव आ गया। कई राज्यों में अच्छा काम हुआ है, पर इन राज्यों में पानी की कमी से वहां के किसानों पर असर हुआ है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की जिम्मेदारी उनके लिए ज्यादा होगी जिन्होंने देश की भूख की समस्या हल करने में योगदान दिया, ऐसी परिस्थिति में वहां के किसानों की मदद करने लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा।

भारत ने दूसरा एक बहुत अच्छा काम किया है। हिंदुस्तान के किसानों और राज्य सरकारों ने भारत सरकार की नीति के माध्यम से एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम, बागवानी मिशन पिछले कई सालों से हाथ में लिया है। आज हिंदुस्तान होर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल के उत्पादन में दुनिया का दूसरे नंबर का देश बना है। जब कोई फसल एक साल में खराब होती है, तो किसानों को उसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। एक साल की फसल देखिए और दूसरी तरफ कोई बगीचा हो, चाहे अंगूर का हो, संतरे का हो, मौसमी, अमरूद या आम का हो, खराब मानसून होने से जब फसल का नुकसान होता है तो उस किसान को इसकी जबर्दस्त कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे याद है कि दो-तीन साल पहले जब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी, तब ये बगीचे बचाने के लिए एक स्पेशल कैम्पेन राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार की तरफ से चलाया गया था। मुझे लगता है कि जिन राज्यों ने होर्टिकल्चर का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, उन राज्यों में इसको बचाने के लिए अलग कदम उठाने की आवश्यकता है। उनको ज्यादा मदद देने के लिए हमें कुछ न कुछ कोशिश अवश्य करनी पड़ेगी। हम आज नहीं तो कल इस परिस्थिति से अवश्य बाहर निकलेंगे। हमें किसानों को अपने पैरों पर फिर से खड़ा करना है, इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। कई किसान ऐसे होंगें, जिन्होंने क्रॉप लोन के लिए बैंकों से या कॉपरेटिव सोसायटीज से कुछ सहायता ली होगी। उनका सोइंग ऑपरेशन पूरा हुआ। उन्होंने क्रॉप ऋण के लिए जो पैसे लिए थे, वे पैसे इसमें खत्म हो गए। लेकिन यदि फसल हाथ में नहीं आई, तो किसान की परिस्थिति खराब हो जाएगी, वह डिफाल्टर बनेगा और उसको नया कर्ज मिलने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। हमें नाबार्ड के माध्यम से सभी कॉपरेटिव बैंकों को अभी से डायरेक्शन्स देनी पड़ेंगी कि हम ऐसे किसानों का रीहैबलीटेशन करने के लिए किस तरह से कदम उठा सकते हैं, rescheduling of their loans के लिए किस तरह से कदम उठा सकते हैं। इसके साथ-साथ उनका जो इंट्रस्ट है, इसमें उनको क्या सुविधा दे सकते हैं, इसकी भी तैयारी करनी होगी। चाहे रिज़र्व बैंक हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सैंटर का कॉपरेटिव बैंक हो या नेशनलाइज्ड अदर्स बैंक्स हों, हमें सभी को सूचना देने की आवश्यकता है। आज परिस्थिति खराब है, लेकिन यदि कल बारिश की स्थिति में सुधार हो जाएगा तो इन किसानों को फिर से इसी क्षेत्र में जाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी।

जब पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तब उनका डिफाल्ट निकालने के लिए, उनके रीहैब्लीटेशन के लिए,रीशेड्यूलिंग के लिए कुछ न कुछ कदम अवश्य उठाने होंगे। हमें इस ओर जल्दी ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि यह जो स्थिति है, इसका सामना करना आसान बात है और हम मिलकर इसका सामना करने की तैयारी करेंगे। हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी मोटिवेट करने की तैयारी कर रखी है। हमने राज्य सरकारों को पूरी तरह से विश्वास में लिया है। भारत सरकार की इस परिस्थिति के लिए बड़ी गंभीर लोन नीति है। यदि हमने यह बात देशवासियों के सामने और इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के सामने रखी, किसानों का हौसला बढ़ाने पर ध्यान दिया, तो मुझे विश्वास है कि हम इस परिस्थिति से भी बाहर निकलेंगे।

राजनीति होती है, मगर जब देश के सामने, देश की मदद करने वाला, भूख की समस्या का समाधान करने वाला किसान संकट में होता है, तो मुझे लगता है कि हम बाकी राजनीतिक मतभेद दूर रखकर और साथ मिलकर इस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हमें इस पर ध्यान देना होगा। मुझे विश्वास है कि इस काम के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा उपयोगी कदम उठाने की तैयारी रहेगी और उनको इस सदन के सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा,मैं यही विश्वास रखता हूं। जो स्थिति आ गई है, हम इससे बाहर निकल सकते हें और इससे भी अच्छी परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। मैं कृषि मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने पचास साल पहले अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत की थी। मेरा क्षेत्र सूखे का क्षेत्र है। वहां हमेशा बारिश कम होती है। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज से बाहर आया, तब मैं इस क्षेत्र में काम करता था। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या सूखे की आ गई। वहां पानी पीने की समस्या हो गई। उस जमाने में यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चरल आर्गेनाइजेशन (एफएओ) की एक योजना थी कि ये जो सूखे में फंसे हुए लोग हैं, उनको बचाने के लिए वे मुफ्त में गेहूं दे देते थे। इस स्कीम का नाम था 'फूड फॉर हंगर'। मैंने उनसे बात की। एफएओ के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए मैं देश के बाहर भी गया। इटली में जाकर, जेनेवा में जाकर, रोम में जाकर मैंने उनके साथ बातचीत की। उनके सामने मैंने यह बात कही कि आप इस 'फूड फॉर हंगर' को बदलिए और 'फूड फॉर वर्क' की स्कीम शुरू करने के लिए कोशिश की गई। मैंने यह कहा कि इसमें आप सबसे ज्यादा ध्यान इस पर दीजिए कि आप जो मुफ्त फूड डिस्ट्रिब्यूट करते हैं, उसे मुफ्त मत दीजिए। जो लोगो पानी का संचय करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन करने के लिए गांवों में काम करते हैं, आप उनको अनाज दीजिए। उन्होंने ट्रायल बेसिस पर इसमें सहयोग देने की पहल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने 3 साल में 300 छोटे इरिगेशन टैंक्स बनाए। अगले 3 साल के बाद शायद मुझे पार्लियामेंट और असेम्बली में आने के 50 साल पूरे हो जाएंगे। ये 50 साल पूरे होने की यह परिस्थिति है कि इसमें मैंने सूखे के क्षेत्र में जो काम तब किया, उसकी एक राजनीतिक ताकत मुझे आज तक मिली है। इसलिए कृषि मंत्री जी और उनके साथियों के सामने आज जो एक गम्भीर समस्या है, इस समस्या को हल करने के लिए अगर वे ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, राज्य सरकारों को सहयोग देंगे, किसानों का हौसला बढ़ाएंगे, तो मुझे विश्वास है कि उनको भी अगले 30-40 साल तक कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। आप इस पर ध्यान दीजिए, इस काम में आपको हम सबका सहयोग मिलेगा।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you, Sir. After Mr. Sharad Pawar, it is difficult to speak on this subject. He is such an experienced person. Even then, Sir, I would like to make a few points. Last week, the new Finance Minister, Mr. Arun Jaitley, made a statement. He said, "Monsoon has just started, it is a late

[Shri D. Raja]

start and it is too early to create any panic." This is what he said. Of course, we should not create panic in the country. At the same time, we should be prepared to face any catastrophe, and drought is one such catastrophe that India is witnessing time and again. Sir, in a drought - like situation, the worst affected are *dalits,* tribals, small and marginal farmers and cattle. Now, what are the immediate steps the Government should take? One, Government should not take excuse of the situation for not controlling the price rise and inflation. Government should ensure the availability of food for the people and fodder for the cattle. Sir, today's Economic Survey– this Economic Survey is supplied to us today– talks about record production of foodgrains and oilseeds. Substantial progress in acreage and production is recorded for 2013-14. As per the third Advance Estimates, the acreage under foodgrains has increased to about 126.2 million hectares and to 28.2 million hectares under oilseeds. Record production of foodgrains at 264.4 million metric tronnes and oilseeds at 32.4 million metric tronnes is estimated. This is Economic Survey. I urge upon the Government, if that is so, the Government should procure foodgrains, oilseeds, etc., providing remunerative prices to our farmers. It is not enough on the part of the Government to talk about hoarding and black-marketing. The Government should take strong measures against hoarding and black-marketing.

Sir, in a situation, as it emerges, drinking water will become a problem not only in villages but even in urban centres. We will have to tackle this problem.

Then, people should have jobs in a drought situation, and there, I agree with my good friend, Shri Jairam Ramesh, that NREGA should be strengthened and, if possible, should be sustained at all levels. The previous Government did reduce the money spent on NREGA in the last Budget. In the new Budget, we hope the new Government is not going to reduce further the money spent on NREGA. In fact, I wish the new Government should enhance the money spent on NREGA so that the agricultural workers, rural masses will benefit.

Then, Sir, there is the question of loans to the farmers. In this regard, Mr. Shard Pawar has explained many issues. But, the National Commission on Farmers once suggested that the farmers should get loans at the rate of four per cent simple interest. Now, there is a demand that small and marginal farmers should get interest-free loans. In fact, the LDF Government in Kerala did make some attempts to provide interest-free loans to the paddy growers.

DR. PRABHAKAR KORE (Karnataka): Even in Karnataka, interest-free loans are provided.

SHRI D. RAJA: I appreciate that. If Karnataka has done it, it is welcome.

SHRI ISHWARLAL SHANKARLAL JAIN (Maharashtra): Even in Maharashtra, up to one lakh rupees, interest-free loan is provided.

SHRI D. RAJA: It is very good. Let us do it at the national level. That is what I am pleading. This is going to be serious issue.

Then, Sir, there is a very sensitive issue, that is, the inter-State water sharing. I don't want to call it a 'dispute'. I want to call it 'inter-State water sharing', for instance, how to share water between Tamil Nadu and Kerala, how to share water between Tamil Nadu and Karnataka. You know, Sir, what the Cauvery issue is. I am raising this issue. There are judicial verdicts. Despite that, what I am trying to say is that when we are confronting a situation like this, I think, the Centre should not lag behind in taking initiatives to settle the problems and helping the inter-State water sharing as early as possible.

Then, there are long-term issues on which many people spoke, for example, the impact of climatic change on India, the change in monsoon patterns and less rains. Even Mr. Jairam Ramesh was quoting Met Department's report regarding 42 or 43 per cent less rainfall. So, all these things are there and here comes the question of preservation and conservation of water bodies. India has the tradition of having water bodies like lakes, ponds, small and big rivers, but how we conserve and preserve our water bodies is very important. Even when the United Front Government was in power in 1996, the issue of preservation and conservation of water bodies was discussed. After that, we have had several Governments and there has been change of Governments. Why does this question still remain? We should address this question. We can also talk about rain water harvesting. But unless we protect water bodies, how can we do rain water harvesting? So, the Government will have to take long-term measures and also short-term immediate measures to tackle the challenges posed by the drought situation.

Finally, once again, I underline the fact that this emerging drought-like situation should not be used by the Government to justify the price rise and inflation which is really affecting the poor and toiling people. At the time of drought, if there is a price rise and inflation, agian, the poor people will be affected. So, the poor people need to be protected in a situation like this.

Sir, as the Economic Survey shows, there is a record production. Once again, I urge upon the Government to procure the foodgrains and make the same available to our poor toiling people, and, also try to store the fodder for our cattle. Sir, as far as India is concerned, cattle is our wealth.

When we talk of poor people, we will have to talk of cattle also and the farming community at large. I hope the Government is serious in this regard and

[Shri D. Raja]

it also understands the gravity of the situation. I also hope that the Government will take adequate measures to face the challenges which confront us in situations like this. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Thank you. Now, Shri Satyavrat Chaturvedi.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN) in the Chair.]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर हम पिछले चार-पांच सालों के आंकड़े देखें, तो देश के कृषि क्षेत्र ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बल दिया है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन में जो वृद्धि हुई, उसके कारण बहुत हद तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रख पाये हैं। आज हमारे सामने जो हालात हैं, उनमें यह खतरा पैदा हो गया है कि हमारी कृषि का वार्षिक उत्पादन दर जो पिछले वर्षों में बढ़ी, मेहनत करके बढ़ी, इस मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उसके ऊपर अगर कहीं विपरीत असर पड़ा, तो इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा।

आज भी जो हमारा औद्योगिक उत्पादन है, उसकी दर बहुत स्वस्थ नहीं है और कृषि के उत्पादन में 4.4 प्रतिशत से भी अधिक का उत्पादन हो रहा है। इस देश में करीब-करीब 60-70 फीसदी आबादी कृषि पर आधारित है, लोग या तो किसान हैं या किसानी से अथवा खेती से जुड़े हुए मजदूर हैं। अगर उनको इस संकट से बचाने के लिए ठोस उपाय नहीं किए गए, तो केवल किसानों के ऊपर बड़ा संकट नहीं आने वाला है, उन पर तो आएगा ही, बल्कि देश की समूची अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा संकट आ सकता है।

श्रीमान्, इस देश की लगभग 40 फीसदी जमीन सिंचित है, जिसको आश्वस्त इरिगेशन मिलता है, सिंचाई मिलती है। पर वह भी कब, जब बारिश सामान्य हो और हमारे बांधों में और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में पर्याप्त पानी भंडारण हो सके, तब तो वह सिंचाई वाला क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। लेकिन, मानसून के जो हालात आज दिख रहे हैं, अगर ये हालात नहीं सुधरे और यही जारी रहा, तो जो सिंचित क्षेत्र है, वह भी संकट में आ जाने वाला है तथा हमारी 60 फीसदी जमीन या हमारे खेत जो केवल मानसून पर आधारित हैं, उस पर निर्भर हैं, उनके ऊपर तो संकट सामने खड़ा है।

श्रीमान्, मैं इस बात को इसीलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं। मध्य प्रदेश के अन्दर इस खरीफ के मौसम में अगर सबसे बड़ी कोई पैदावार होती है, तो वह सोयाबीन है। पिछले वर्ष अत्यधिक बारिश के कारण पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की नष्ट हो गई। वहां आज इसके बीज ढूंढना भी मुश्किल है। मुझे अपने खेत के लिए बीज ढूंढने के लिए अपने आदमी को महाराष्ट्र भेजना पड़ा था। हम महाराष्ट्र से इसके बीज लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का बीज उपलब्ध नहीं है।

वहां पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। अतिवृष्टि के कारण पिछले वर्ष तो यह हाल हुआ और इस साल मध्य प्रदेश में जो मानसून की स्थिति है, इसमें मध्य प्रदेश अकेला नहीं है, कर्णाटक की हालत खराब है, तमिलनाडु के कुछ हिस्से में पानी बरसा है, तमिलनाडु के कुछ जिलों की हालत खराब है, केरल में पानी पर्याप्त नहीं है, आन्ध्र प्रदेश में पानी पर्याप्त नहीं है, गुजरात की बुरी हालत है, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा की हालत खराब है, गुजरात में माइनस 91 प्रतिशत डेफिसिट रेन है, यह अभी की हालत है, राजस्थान की हालत खराब है, उत्तर प्रदेश का जो वैस्टर्न हिस्सा है, इसके अंदर भी बारिश की आज की जो स्थिति है, वह पिछले सामान्य वर्षा के मुकाबले लगभग 60 से लेकर 80 फीसदी तक अलग-अलग क्षेत्रों में अपेक्षा से कम बारिश हुई है। अब यह स्थिति आज की है। बुआई हो नहीं रही है।

जब बारिश नहीं हुई है, तो बुआई कैसे होगी? अगर अगले 15 दिनों के अंदर स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं आया, तो फिर बुआई होगी ही नहीं। मैं एक किसान के अनुभव के आधार पर यह बताना चाहता हूं और कृषि मंत्री तो खुद किसानी से जुड़े हुए हैं, ये तो खुद इस बात को समझते हैं कि वैसे ही हम लेट हो गए हैं और अब तो लेट बुआई होगी, जिसका उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा ही, लेकिन अगर अगले 15 दिन बारिश नहीं हुई और हमको पानी नहीं मिल पाया, तो फिर बुआई होगी ही नहीं। बीज भले आप रखे रहें, लेकिन फिर किसान बो कर क्या करेगा? अगर यह स्थिति निर्मित हुई, तो हमारे सामने तिलहन और दलहन का संकट जो पहले से ही मौजूद है, चूंकि इस फसल में सबसे ज्यादा तिलहन और दलहन की फसलें उगाई जाती हैं और अगर उनकी उपज नहीं हो पाई, तो उसका संकट इस देश के ऊपर और पड़ने वाला है। तिलहन का इंतजाम तो आप बाहर से आयात करके कर लेंगे, लेकिन क्षमा कीजिए, दुनिया मे बहुत कम देश हैं, जहां पर दालें उगाई जाती हैं और इसलिए हमारे सामने यह संकट आने वाला है। केवल मलेशिया की तरफ साउथ-ईस्ट के कुछ देशों में और तुर्की में, जहां चने की दाल उगती है, केवल यहीं पर दाल मिलती है, बाकी आप पैसा लिए घूमते रहिए, दुनियां में और कहीं दाल पैदा ही नहीं की जाती है, तो आपको कहां से मिलेगी? अगर वह संकट बढ़ा, तो फिर कीमतों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना असंभव हो जाएगा, इसलिए आज ही हमको इस बात पर विचार करना होगा कि हम आने वाले समय के लिए क्या-क्या उपाय करें।

अब राज्य सरकारों की बड़ी तारीफ हुई। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से किसान की मेहनत के परिणाम स्वरूप और राज्य सरकार ने भी उसमें अपना योगदान किया है, दोनों ने मिल करके आज मध्य प्रदेश को गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थापित किया है। लेकिन, मध्य प्रदेश के मेरे मित्र यहां बैठे हुए हैं, इस तरफ भी हैं और उस तरफ भी हैं, पिछले वर्ष फसल का जो नुकसान हुआ और केन्द्र सरकार ने जो यहां से राहत की राशि भेजी, आज तक उन किसानों को राहत की राशि नहीं बांटी गई है। क्या यह सच नहीं है? किसान के साथ इतना बड़ा संकट हो, जहां केन्द्र सरकार से पैसा पहुंच जाए और राज्य में साल-साल भर तक वह राशि बांटी न जाए, अगर किसानों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? आज भी बुआई के समय पर बीज उपलब्ध नहीं हैं। फर्टीलाइजर के लिए सुपर फॉस्फेट मांगने गए, तिलहन और दलहन की फसलों के लिए सुपर फॉस्फेट की जरूरत होती है डीएपी की नहीं, डीएपी इन फसलों के लिए उतनी प्रभावकारी नहीं होती है, लेकिन आज आप किसी भी को-ऑपरेटिव सोसाइटी में चले जाइए, वहां आपको सुपर फॉस्फेट की खाद नहीं मिलेगी। ये सारी व्यवस्थाएं, जो सीजन के आने से पहले ही कर ली जानी चाहिए थीं, वे व्यवस्थाएं आज भी नहीं हो सकी हैं। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं और आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। आप कृपा करके हर राज्य से यह पूछें कि उनके पास कम अवधि की फसलों के बीज जो हैं, वे कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, क्योंकि अब आपको लंबी अवधि की फसलें बोने का समय ही नहीं मिलेगा। अगर आपको संकट से बचना है, तो अब आपको कम अवधि के बीज की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपने अभी तक व्यवस्था की या नहीं, कुछ पता नहीं। अभी हमारे एक मित्र, पाठक जी जो कह रहे थे, वह बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। एक बड़ा संकट आने वाला है, गांव-गांव में बड़ी भारी भारी तादाद में मवेशी हैं, इन मवेशियों के चारे का क्या होगा? अगर मवेशियों के चारे का प्रबंधन हमने अभी से नहीं किया, तो हम अपने पिछले वर्षों के अनुभव से देख चुके हैं, राजस्थान और गुजरात में जो दशा हुई थी, हमनें बहुत कोशिश की कि दूसरे राज्यों से हम ट्रेन से वहां चारा पहुंचा सकें, हमने रैक भी लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों की तादाद में मवेशी खाने और चारे के अभाव में मरे। यह संकट पैदा हो सकता है। इसके लिए आपको एक वैकल्पिक आपातकालनी योजना तैयार करनी होगी, अन्यथा यह संकट देश

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

के बहुत सारे राज्यों में मवेशियों के सामने खड़ा होगा और अगर मवेशियों पर संकट आया, तो आप सोच लीजिए कि दूध और बाकी चीज़ों कीमतों पर क्या असर पड़ने वाला है।

श्रीमान्, पीने के पानी के संकट का जिक्र हमारे अन्य साथियों ने किया है, इसलिए मैं उसे दोहराऊं, इसका कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में मौसम विभाग और मीडिया के माध्यम से हमारे सामने जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे एक ही दिशा में संकेत करते हैं कि पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्षों में सामान्य वर्षा के समय हमारे बांधों और तालाबों का जो जल-स्तर होता था, वह आज उससे ¼ है। पिछले वर्षों के इन्हीं महीनों की तुलना में आज यह स्तर ¼ है। यानी, पीने के पानी का संकट उत्पन्न होगा।

श्रीमान्, मुझे अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात का अनुरोध करना है। पहली बात यह कि किसानों की जो राहत राशि है, उसको अगर कहीं आप वितरण करना चाहते हैं या राहत-कार्य खोलना चाहते हैं, तो वहां आपको राज्य सरकारों को इस मामले में विश्वास में लेना पड़ेगा, क्योंकि केन्द्र सरकार यहां से सीधे तौर पर यह काम संचालित नहीं कर सकती, इसे राज्य सरकारों को ही संचालित करना होगा। अगर इसमें राज्य सरकारें सहयोग करेंगी, तो निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान में आपको सहायता मिल सकती है और अगर उनका सहयोग नहीं मिला तो फिर यह संकट और बड़ा हो जाएगा।

दूसरी बात, रोजगार के संकट पैदा होंगे। जब किसान के पास खेती नहीं होगी, तो उसको कहीं न कहीं से रोटी खाने के लिए काम चाहिए, रोजगार चाहिए। आपको राहत कार्य खोलने पड़ेंगे और ये राहत कार्य आपको कहां पर कितने खोलने पड़ेंगे, किन जिलों में सूखे का प्रभाव सबसे ज्यादा है, इसकी आइडेंटिफिकेशन का काम आपको अभी से शुरू करना होगा। हो सकता है और भगवान करे ऐसा हो जाए कि अगर आने वाले 10-15 दिनों के अंदर अच्छी बारिश हो जाए तो हम इस संकट की बात भूल जाएंगे, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो हमें तैयारी तो आज से करनी पड़ेगी। अगर आज से तैयारी नहीं हुई, तो ऐन मौके पर आपको फिर यह अवसर नहीं मिल पाएगा और आप उसे संभाल नहीं पाएंगे।

एक और पक्ष है, जिसकी तरफ मैं आपका विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा। यही वह मौका होता है जब इस देश के जमाखोर और मुनाफाखोर सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और जनता का शेषण करने की कोशिश करते हैं। इसमें छोटे-मोटे स्टॉकिस्ट्स का काम नहीं है, बल्कि बड़े-बड़े स्टॉकिस्ट्स गोदामों में अनाज और विभिन्न आवश्यक वस्तुएं भरकर जमाकर लेते हैं। आप कहते तो हैं कि जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपका यह कथन सत्य सिद्ध हो, पर अभी तक पिछले एक महीने में जो देखने में आया, उसतें मुझे कहीं छापेमारी होती नहीं दिखी, कहीं किसी बड़े स्टॉकिस्ट के ऊपर कार्रवाई होती नहीं दिखी और इन सब कारणों से आज भी बाजार में जो वायदा ट्रेडिंग चल रही है, वह आज भी फल-फूल रही है और वही सबसे बड़ा शोषण और महंगाई का कारण है। अगर सरकार ने उस पर अंकुश नहीं लगाया तो यह संकट और अधिक बढ़ जाने वाला है, घनीभूत हो जाने वाला है। अब संकोच थोड़ा-सा तोड़िए। चुनाव हो गया, अब वह पांच साल बाद आएगा, इसलिए उनसे जो लेना हो, वह आप बाद में ले लेना, फिलहाल इन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए वायदा ट्रेडिंग पर अंकुश लगाइए। ये ही ऐसे कुछ उपाय हैं जो किए जाने जरूरी हैं। बाकी शरद पवार जी ने आपको बहुत विस्तार से बताया है, वे कृषि मंत्री रहे हैं और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, उनसे मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि इसे राजनीति का विषय न बनाया जाए। हम सब मिलकर इस संकट से देश को उबारने में परस्पर

सहयोग की भूमिका निभाएंगे। अगर आप इस संकट से जूझने में ईमानदारी से कोशिश करना चाहें तो हम आपको अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। धन्यवाद, जय हिन्द।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Thank you. I would just like to make a small request. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): Sir, I have just one point. ...*(Interruptions)*... मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि जब सूखा पड़ता है तो सबसे बड़ी बात यह की जाती है कि किसानों का मालिया माफ कर दिया जाता है, जबकि मालिया माफ करना कुछ नहीं होता है। सो इस चीज को भी ध्यान में रखें कि उनके आंसू न पोंछे जाएं, मालिया माफ करके, उनको पूरी तरह से राहत दी जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay. Thank you. Now, around 12 Members have to speak. Kindly cooperate and stick to the time. The hon. Minister has to reply. Now, I call Shri Tarun Vijay.

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व भुपेन्द्र जी, माननीय शरद जी और सत्यव्रत जी ने अपने बहुत अच्छे विचार बड़ी संवेदना तथा भावना के साथ रखे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे आंकड़े दिए, राम गोपाल जी ने संवेदना के साथ बात रखी और अन्य माननीय सस्दयों ने इस प्रकार के आंकड़े भी दिए कि भारत के किसानों की स्थिति काफी सुधार भी रही है और वे काफी धनी भी हो रहे हैं और उनके अनेक कृषि उत्पादन भारत के बाहर निर्यात भी किए जा रहे हैं। ऐसा मैं देखता भी हूं, पर यह भी देखता हूं कि जब मैं लद्दाख के 18 हजार फीट के खरदुंगला दर्रे पर जाता हूं, तो वहां पर छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के किसान सड़क पर डामर बिछाने का काम कर रहे होते हैं, सड़क बनाने का काम करते होते हैं। ऋण पांच से ऋण बीस के तापमान में, क्योंकि वहां स्थानीय मजदूर कहीं से मिलते नहीं हैं। वे किसान अपनी धरती, अपनी जमीन छोड़कर मजदूरी करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर लद्दाख क्यों जाने पर मजबूर होता है? वह भी हिन्दुस्तान का किसान होता है। जब हम दुर्भिक्ष और अकाल की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है बुरा समय, दुष्काल, और यह बुरा समय जब आता है तो अधिकांशतः उन पर आता है जिनको हम किसान कहते हैं, गांव वाले कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं, देहाती कहते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत आंकड़े दिए गए हैं, मेरे तमाम आंकड़े हैं। सबसे बड़ी दुख की बात जो है वह यह है कि इस देश में किसान की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है। किसान होना बहुत प्रतिष्ठा तथा समाज में एक अच्छा बड़ा स्थान रखना होता था। अब यह बात मानी नहीं जाती। आप खेती करते हैं, दलहन-तिलहन उगाते हैं, आप गेहूं और जौ उगाते हैं यानी किसानी करते हैं तो उसका अर्थ अब सीधा-सीधा यह हो गया है आप गांव के हैं, देहाती हैं, कम पढ़े-लिखे हैं, कम शिष्टाचार वाले हैं। जितने भी हीनता के बोधक शब्द हैं, वे उस ग्रामीण किसान के साथ जोड़ दिए गए हैं। भारत के किसान अपना हताशा भरा चेहरा लेकर साधारण रूप से ही कहते हैं कि क्या करें साहब, किसान हैं, गरीब हैं। किसानी का अर्थ हो गया है पलायन, भुखमरी। किसानी का अर्थ हो गया है आत्महत्या। किसानी का अर्थ हो गया है कि जब कभी ऐसा दुर्भिक्ष या दुष्काल आए तो बड़ी संख्या में starvation deaths होना। कहना किसान आसान होता है कि भूख से होने वाली मौतें। मैं अभी पिछले हफ्ते राजस्थान में बांदीकुई गया था, वहां के कुछ किसान मुझे मिले, अपने लोग मिले। कहने लगे कि आप संसद में जब किसानों की गरीबी, दुर्दशा पर बात करते हैं तो संसद में आपको शानदार खाना सब्सिडी पर मिलता है, आप उसके आधे से कम खर्चे पर खाना खाते हैं और उसके बाद आप किसानों

[श्री तरुण विजय]

और गरीबों की दुर्दशा पर बोलते हैं। आप भी उनमें से एक हैं, जाकर बोलिए। लेकिन क्या किसी को महसूस होता है कि 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन खाना न मिले, पानी ठीक से न मिले और तब वह एक-एक सांस छोड़ता हुआ तड़पन के साथ भुखमरी का शिकार होते हुए प्राण छोड़ता है, तो वह starvation death कही जाती है। उस starvation death की वेदना, पीड़ा और उससे उपजने वाले आक्रोश, उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है यह देश आज कितनी संवेदना के साथ महसूस करता है, जिस देश ने इसी पिछली शताब्दी में तीस लाख लोगों को भूख से तड़प-तड़प कर मरते हुए देखा था और वह दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भिक्ष और बंगाल का सबसे बड़ा अकाल कहा गया था, यह हमारे भारतवर्ष में ही हुआ।

यह हमारे भारतवर्ष में ही हुआ। मेरे पास लोक सभा के रेफरेंस सेक्शन के दिए आंकड़े हैं, जो बताते हैं कि बिहार में उस अकाल की तुलना में बहुत कम 'स्टारवेशन डेथ्स' हुईं, बहुत कम भूख से तड़प-तड़प कर लोगों की मौतें हुईं। गत शती में 30 लाख लोग मरे थे और बिहार में वर्ष 1966-67 में केवल 2300 के करीब लोग स्टारवेशन डेथ यानी भुखमरी से मरे। महोदय, 2300 लोग भुखमरी से मरते है और हम कहते हैं कि सरकार ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया! यह किसी सरकार पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन इस देश में एक भी व्यक्ति की मौत भुखमरी से क्यों होनी चाहिए? एक भी किसान को परेशान, हताश होकर आत्म-हत्या करने को विवश क्यो होना चाहिए? यहां सरकार अच्छी योजनाएं बनाती है। महोदय, जैसे एक नेशनल रेनफेड एरिया आथॅरिटी बनी। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2007 में बुंदेलखंड के लिए 1005 करोड़ रुपए आवंटित किए गए ताकि जहां कम बारिश होती है,वहां पर लोग जलाशय बना सकें, वाटर बॉडीज बना सकें, सिंचाई के साधन तैयार कर सकें और वहां के किसानों को आकस्मिक समय में, जब अकाल आए, तो उस के लिए तैयार कर सकें। उपसभाध्यक्ष महोदय, वहां 1005 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन पांच सालों में उस में से केवल 179 करोड़ खर्च किए गए। इस के लिए कौन दोषी है? महोदय, बुंदेलखंड वह इलाका है, जहां के किसान 1857 की आजादी की लड़ाई में सब से आगे रहे थे। अंग्रेजों ने उस के लिए इस क्षेत्र के किसानों को सज़ा दी क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। वहां उस समय तमाम सरकारी योजनाएं वापस ले ली गयीं। उसके बाद वहां कोई विकास नहीं किया गया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी किसानों के क्षेत्र में, आजादी के बाद वर्ष 2007 की क्या स्थिति है? अब तो अंग्रेजों का नहीं हमारा राज है, लेकिन वहां उनके लिए भी खर्च नहीं किया गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, उस संगठन की अध्यक्षा का यह बयान है कि बुंदेलखंड में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में सबसे कम खर्च किया गया। यह भारत के उस किसान के क्षेत्र की स्थिति हम ने बना दी है, जिस के लिए हम कहें कि अगर भारत के शब्द जिंदा हैं, भारत के अक्षर जिंदा है, भारत की भाषा जिन्दा है, तो वह उस किसान के घर में जिंदा है। यहां शहर कंक्रीट के जंगल में तो भाषा विकृत हो रही है। अगर देश की वेशभूषा जिंदा है, तो किसान के गांव में जिंदा है, अगर देश की भोजन शैली जिंदा है, तो वह किसान के क्षेत्र में जिंदा है। अगर देश के त्यौहार जिंदा है, तो आधा-पेट भरे हमारे देश के किसान की वजह से जिंदा है, जो हमारे देश के रीति-रिवाज, परम्परा और त्यौहारों को उत्साह के साथ मनाता है जिसे शहर के लोग उस उत्साह से नहीं मानते हैं। लेकिन उस किसान के लिए हम ने क्या किया? हम ने यह किया कि आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में सब से ज्यादा ड्रॉप-आउट रेट है, तो वह किसान के बच्चों का है। अगर कहीं सब से कम अच्छे विद्यालय हैं, तो वह किसानों के गांवों में हैं। आज किसान के ग्रामीण क्षेत्र केवल पलायन, भुखमरी से मृत्यु, आत्म-हत्या व बच्चों व महिलाओं के शोषण के लिए जाने जाते हैं।

महोदय, मैं उत्तराखंड से आता हूं। हमारा समूचा किसानों का क्षेत्र, जो कि तिब्बत व चीन की सीमा से लगा हुआ है, आज खाली हो गया है। वहां से उनका पलायन हो गया है क्योंकि वहां पर

डॉक्टर्स नहीं हैं, संचार के साधन नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं और किसी तरह की आकस्मिक सेवाएं नहीं हैं। अगर आज हमारे उस गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र के लोग बीमार हो जाते हैं, तो वहां के लोगों को 65 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 22 किलोमीटर तक चारपाई पर मरीज को डालकर निकटतम अस्पताल तक लाने की मजबूरी होती है। महोदय, ये कौन लोग हैं? ये वही किसान हैं, जो खेती करते हैं और खेती करने के कारण सब से ज्यादा हमारी उपेक्षा का शिकार बनते हैं क्योंकि वहां यदि अधिक किया जाए तो उस का रिटर्न नहीं है, वहां से नेताओं को राजनीतिक फायदा नहीं होता है, अफसरों को वहां जाने में दिलचस्पी नहीं होती है। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कहां रहेगा? उन क्षेत्रों रहेगा, घनीभूत होता रहेगा, जहां पहले से सुविधाएं हैं। हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े नेता, भगवान की कृपा से वे बचे, हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हो गई, कहां गए? दिल्ली के एम्स (AIIMS) में आए। क्यों? क्योंकि हमारे क्षेत्र में अच्छे अस्पताल नहीं हैं। यहां किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां क्या है? नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, आतंकवाद है, इन्सर्जेंट एक्टिविटीज हैं। देश के जनजातीय लोग सबसे बड़े किसान होते हैं। देश में 98 प्रतिशत आतंकवाद, Sir, 98 per cent of terrorism, insurgency and violent activities are concentrated only in areas habitated by 8 per cent of tribal farmers. Why? जो 8 प्रतिशत भारत के जनजातीय लोग किसान हैं, उनके क्षेत्र में हिंदुस्तान का समूचा 98 प्रतिशत आतंकवाद, विद्रोही गतिविधियां और हिंसक गतिविधियां हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को हम अपने समान प्रतिष्ठा का नागरिक नहीं मानते। उनके क्षेत्र में क्या करते हैं? हम मॉल्स बनाएंगे, हम बड़े-बड़े सिनेप्लेक्सेस बनाएंगे, हम बड़े-बड़े कंक्रीट के जंगल बनाएंगे। उनकी जमीन लेकर हम उनको पैसा देते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को बरबाद कर देते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस परिस्थिति में हम सभी को राजनीति से ऊपर उठ कर एक बात तय करनी चाहिए कि इस देश में शहर के विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर वे लोग गांव में वापस जाकर खेती करने में अपनी ज्यादा प्रतिष्ठा समझें। हमारे लिए जलाशयों की स्थिति, वाटर बॉडीज की स्थिति, नहरों की स्थिति उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जितने हवाई अड्डे बनाने या जितने बड़-बड़े भवन या हाईवेज़ बनाने में है। जब तक देश में विकास का केन्द्र बिन्दु किसान और खेती नहीं बनेगा, तब तक हमारी ये तमाम चर्चाएं और तमाम सब्सिडी का खाना खाकर यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करना निरर्थक ही साबित होगा। धन्यवाद।

SHRI AHAMED HASSAN (West Begal): Mr. Vice-Chairman, Sir, as we all know, a drought like situation has developed in many provinces of our country. The prediction is that we are facing a below average monsoon this year. Common people in rural areas are already suffering. As a result there is every possibility that production of food crops will suffer to a great extent. Naturally, water and power sectors also will be affected. Cashing on this situation, hoarding of essential food grains has already started. Prices are rising at a rapied speed. Our agricultre in Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana and Odisha has severely affected. Farmers could not undertake farming in lakhs of hectares of farmland in many provinces. In this situation, we want the Government to take adequate measures to fight this situation. Common people and our farmers should not suffer. I would like to mention a few measures which the Government should take to tackle the situation. Firstly, proper seed subsidy should be given to the farmers of drought-affected areas. Crop loan should be

[Shri Ahamed Hassan]

given to the farmers and the help should reach the affected areas and proper hands. Hoarding and price rise should be controlld and checked very strictly. सर, ड्राउट-लाइक सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, वे हैं गाबादी पशु, बंगला भाषा में उन्हें "गाबादी पशु" बोलते हैं, the cattle. हमारा जो लास्ट एक्सपीरिएंस है, उसमें हमने देखा कि किस तरह से कैटल सफर करते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है और किस तरह से वे मरते हैं, very helplessly. तो हम चाहते हैं कि अभी जब एक ड्राउट-लाइक सिचुएशन डेवलप हुई है, we should mae proper arrangements for cattle which are helping us in many ways. कई सांसदों ने यह कहा कि वाटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। So, there should be proper management for distribution of food and water, and this should be planned right now. अभी से उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। My State, West Bengal, also faces poor rainfall in the beginning of the season. But our Government's Agricultrure and Irrigation Management System has tackled the situation to a great extent. Our hon. Chief Minister, hon. Mamta Banerjee, has taken steps to control the price rise as well as hoardings. I want to tell you, Sir, one thing that when the new Government of TMC came into power in West Bengal, hon. Mamata Banerjee introduced a project. Its name in Bengali is 'जल धरो जल भरो' यानी 'collect rainwater and use it'. This project has been very much successful in West Bengal and it has helped our farmers, our villagers, in irrigation and many other things. I would suggest that a proper study should be made of this project of hon. Mamata Banerjee. 'जल धरो and जल भरो'। These are all short-term measures. I want to finish with one suggestion by way of a long-term measure. I Deforestation in our country is going on at a rapid pace. We should put a check to these things. arrange for planting of more trees and take care of our *paryavaran.* In that way, think, in future, we can tackle this kind of drought situation effectively. Thank you very much.

श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो ड्राउट पर चर्चा हो रही है, मुझसे पहले बोलने वाले हमारे बहुत ही काबिल और महान सज्जनों ने इससें बहुत से फिगर्स दे दिए हैं। आई.एम.डी. की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी कंट्री में अभी तक 81 परसेंट ड्राउट है। इसके मुताबिक जो हमारे फूडग्रेन्स हैं, इस बात की भी संभावना है कि वे पिछले साल के मुकाबले इस साल कम होंगे। मैं इस पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे पहले कई सदस्य बोल चुके हैं। मैं सिर्फ थोड़े टाइम में आपको सजेशन देना चाहता हूं कि अब तुरंत हमें क्या करना चाहिए। एक तो लांग टर्म पॉलिसी है कि जब बार-बार, दो-तीन साल के बाद ड्राउट का सर्कल आता है, तो उससे कैसे हमें किसान को बचाना है, देश को बचाना है, लेकिन अब जो ड्राउट आ चुका है, इससे किसान और देश को कैसे बचाना है? तो मैं आपके ज़रिए गवर्नमेंट को सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले फार्मर को ड्राउट का जो कम्पन्सेशन देना है, वह बाद में नहीं, अभी दीजिए ताकि अगर उसे इरिगेशन की जरूरत हो, डीजल की जरूरत हो, पावर की जरूरत हो और सीड की जरूरत हो, तो उसके लिए वह उसे खर्च कर सके। दूसरी चीज़ यह है कि उसको अब जो मुआवज़ा देंगे, अगले दिनों में बारिश हो जाएगी, तब वह उसके काम आएगा। तो मेरा पहला प्वाइंट यह है कि ड्राउट का जो कम्पन्सेशन देना है, वह स्टेट्स को अभी देना चाहिए ताकि स्टेट्स उसको किसानों में बांट सके। दूसरा यह है कि उन्होंने जो पहले लोन लिया था, उसको लांग टर्म पॉलिसी में चेंज करना चाहिए, थ्री ईयर और फाइव ईयर में। और तीसरा है कि लोन पर जो इंटरेस्ट है, वह माफ होना चाहिए क्योंकि ड्राउट आ गया, ऐसी

स्थिति में किसान का कोई कसूर नहीं है। इस प्रकार ये जो इमिजिएट मेज़र्स हैं, वे सरकार को लेने चाहिए और आने वाले समय में उन्हें कैसे बचाना है, यह देखना जरूरी है। हम लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री का 40 परसेंट रकबा इरीगेटेड है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग पंजाब को सबसे अच्छा कहते हैं। सब देश के लोगों में, दुनिया में यह कही जाती है, लेकिन पंजाब में जो कैनाल वॉटर है, वह केवल 17 परसेंट है और 83 परसेंट ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए एक तो किसान अपना सरमाया खत्म कर रहा है, नैचुरल रिर्सोसेज़ को खत्म कर रहा है और दूसरी ओर उसे पॉवर और डीज़ल ज्यादा बरतना पड़ेगा। इसलिए चाहे मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, यूपी का पार्ट हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, जहां भी नीचे से किसान पानी निकालता है, वहां पर गवर्नमेंट को उसे कम्पनसेट करना चाहिए क्योंकि देश में अनाज की जो कमी आ रही है, उसको वह किसान ही पूरा करेगा। आप देखिए कि आगे आने वाले समय में जो हमारी आबादी है, वह कितनी इन्क्रीज़ हो रही है। सन् 2050 में हमारी आबादी जहां चली जाएगी, उसके लिए अब से डबल अनाज की जरूरत हमें पड़ेगी। आज लैंड खत्म हो रही है, इरिगेशन के साधन ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर है, वह डिप्लीट हो रहा है, कैनाल वाटर भी डाउन आ रहा है। हमारी 85 परसेंट रवायत जो है, आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 24 परसेंट है। पिछले साल वह 29 परसेंट थी। जो लाइव स्टोरेज थी,वह भी डाउन आ गयी है। जो हमारे डैम हैं, उनमें भी पानी कम आ रहा है। जो सदर्न पार्ट है, वे हर समय आइस पर निर्भर नहीं करते। हमारी जो हिमालयन रेंज है, वहां आइस कम हो रही है। इसलिए जो होल ऑफ कंट्री है, उसमें फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम आ रही है। उसको कैसे बचाना है, यह लांग टर्म पॉलिसी है। सर, टाइम कम है, नहीं तो मैं उसके बारे में भी सजेस्ट करना चाहता था कि आज देश का क्या हाल हो रहा है। जो वॉटर के रिर्सोसेज़ हैं, वे कितने डिप्लीट हो रहे हैं। आज प्रॉब्लम है यह कि जो सबसे अच्छा राज्य है, पंजाब, जिसको पांच-आब, land of five rivers कहा जाता था, वहां पर पीने का पानी नहीं हैं। आज वहां एक इंच धरती में भी जो ग्राउंड वॉटर है, वह पीने के काबिल नहीं है, हम सारा आरओ का वॉटर बरत रहे हैं या कैनाल वॉटर जो आता है, उसको आरओ के जरिए बरतते हैं। आज वह भी पॉल्यूट हो चुका है। इसलिए आज जो हालात हैं,ऐसे हालात में ड्राउट को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा किसान है, उस पर हम सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। सर, यहां मैं यह फिगर भी देना चाहता हूं कि पंजाब के बारे में एक भुलेखा है कि पंजाब के लोग बहुत अमीर हैं। 44 परसेंट जो हमारा किसान है, उसके पास सिर्फ 2 एकड़ लैंड है। इसीलिए यह प्रॉब्लम आ रही है कि कोई ईरान जा रहा है, कोई इराक जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। कौन अपना घर छोड़कर जाता है? जब प्रॉब्लम आती है, रोटी की प्रॉब्लम आती है, तब लोग अपना घर छोड़ते हैं। इसलिए यह जो दो एकड़, चार एकड़ वाले फार्मर्स हैं, वे कहां से खाएंगे? जब इस तरह से ड्राउट आएगा तो वे किसान कहां से बिजली बरतेंगे, कहां से पानी बरतेंगे? लेकिन वे बरतेंगे, क्योंकि हमारा किसान घरवाली के गहने बेचकर भी क्रॉप को सिरे चढ़ाता है। दूसरी ओर हम क्या कहते हैं कि जहां क्रॉप नहीं हुई, वहां तो मुआवजा दे दो, जहां हुई है, वहां इसकी जरूरत नहीं है। पहले हमारे साथ जो इस तरह का व्यवहार होता रहा है, वह विदकरा होता रहा है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को यह सजेशन देना चाहता हूं कि जिन स्टेट्स में, जो किसान इस ड्राउट के समय में ज्यादा फसल पैदा करेगा, उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि वह भी देश के लिए पैदा कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। अगर वहां भी अनाज नहीं होगा और दूसरी जगह सूखा पड़ जाएगा तो दोनों तरफ प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा मेजर प्वाइंट यह है कि ड्राउट में केवल फूड ग्रेन ही नहीं, चारे की भी प्रॉब्लम आएगी। पहले पंजाब में हमारे यहां चारा और दूध बेचना गलत माना जाता था हमारे यहां दूध बेचने को ऐसा समझते थे जैसे पुत्त को बेच दिया। दूध बेच दिया यानी पुत्त को बेच दिया-अब वह भी बिकने लग गया।

[श्री बलविंदर सिंह भुंडर]

गरीबी के कारण किसान स्मॉल फार्मर हो गया, दो एकड़ में आ गया। इसी प्रकार कभी भी हमारा किसान चारा नहीं बेचता था, वह दूसरे को दे देता था। वह कहता था कि चारा नहीं बेचेंगे, यह तो पाप है। जहां पहले राजस्थान तक हमारा चारा जाता था, अब हमारा चारा वे वहां बरतने लग गए, जहां बिजली पैदा करने लग गए हैं। इसलिए वह प्रॉब्लम भी आ गयी है। अब कंट्री में चारे की भी प्रॉब्लम आएगी। मैं कहना चाहता हूं कि पहले वह यहां से कम्पनसेट हो जाता था। अब उन स्टेट्स के लिए, सदर्न स्टेट्स के लिए यह प्रॉब्लम आएगी। इसके बारे में भी पहले से सोचना चाहिए। इसी तरह से अगर किसान का कैटल चला गया, तो उसका सब कुछ चला गया। वह कैटल और खेती दोनों पर ही निर्भर है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से विनती करूंगा और यह सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए पहले अरेंजमेंट्स के लिए इनके पास सारे फिगर्स हैं, उसके लिए मैं आपका समय नहीं लूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सूखे के संकट पर आज दिन भर बहुत चर्चा हुई है और चर्चा का सार यही है कि जिन प्रदेशों में आज सूखे की स्थिति बन चुकी है, जहां वर्षा औसत से बहुत कम हुई है, उन प्रदेशों में आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, उस पर हमें आज से ही विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इस बात के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं कि महाराष्ट्र में जहां 134.70 लाख हैक्टेयर जमीन खेती की है, वहां मात्र 8.43 लाख हैक्टेयर में ही बुवाई हुई है। गुजरात में जहां पर 86.8 लाख हैक्टेयर जमीन खेती की है, वहां मात्र 12.8 लाख हैक्टेयर में ही बुवाई हुई है। गुजरात की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कम से कम 203 गांव भीषण सूखे की चपेट में हैं। कच्छ और सौराष्ट्र का वाटर लेवल बहुत ही नीचे जा चुका है। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल की केवल 10 प्रतिशत बुवाई हुई है, हालांकि राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपये की राशि "फार्म स्कीम" के अंतर्गत किसानों को उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। अगर हम एक-एक प्रांत की स्थिति को देखें, माननीय कृषि मंत्री जी आपको तो मालूम है, राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में 67 परसेंट और वैस्टर्न पार्ट में 52 परसेंट सूखे की स्थिति है, sowing has covered only 10 per cent of the total targeted area of 1.56 lakh hectares. इसके मात्र 10 प्रतिशत में ही अभी धान की बुवाई हुई है। पंजाब और हरियाणा सिंचित प्रदेश कहलाये जाते हैं, वहां पर भी खरीफ फसल की बुवाई पिछले साल की तुलना में इस बार भी कम हुई है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास इसकी पूरी जानकारी होगी। ओडिशा की भी ऐसी ही स्थिति है। ओडिशा धान का उत्पादन करने वाला बहुत बड़ा प्रदेश रहा है। वहां पर भी सूखे का संकट है। छत्तीसगढ़ में, Kharif crop has been planted in 40 pe cent of the total targeted area. So far, the State has received only 1/3rd of rainfall. छत्तीसगढ़ में केवल 40 परसेंट खरीफ फसल की बुवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जो योजना बनाई है, उस पर काम चल रहा है। पश्चिमी बंगाल में, jute cultivation suffered due to heat spell in April-May and delay in rain. पानी की कमी के कारण जूट का जितना cultivation होता था, वह भारी गर्मी के कारण बहुत कम हुआ है।

अरुणाचल प्रदेश में जो सूखे की स्थिति है, उसके अनुसार वहां पर मात्र deficit of 25 per cent so far. About Karnataka, Karnataka is the most affected, where about 19.5 lakh hectares of land has been hit by drought-like conditions. Kerala, which is not a major producings State, the rainfall deficit has been to the tune of 31 per cent. In Tamil Nadu,

the rainfall so far has been normal. In Andhra Pradesh and Telangana, the rainfall deficit is about 60 per cent, so far. The State Governments have drawn up contingency plans.

देश के इन राज्यों की यह स्थिति आज के अनुसार है, लेकिन मेटरालोजिकल डिपार्टमेंट ने इस बात की आशा जगाई है और कहा है कि हमें उम्मीद है कि जुलाई और अगस्त में काफी अच्छी वर्षा होगी और आज देश के अन्य राज्यों में जो सूखे की स्थिति है, वह कम होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट और लगेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार हरेक राज्य सरकार को इस बात का निर्देश दे कि वह कंटिंजेंसी प्लान बनाए। कंटिंजेंसी प्लान अर्थात् लोगों को बराबर मजदूरी मिले। मजदूरी के साथ उनको अच्छे काम भी मिलें। चाहे सिंचाई के क्षेत्र का काम हो, चाहे सड़क बनाने का काम हो या डैम बनाने का काम हो, इन कामों में मजदूरों को काम मिलने की काफी संभावना हो सकती है। जब सूखा पड़ता है, तो होता यह है कि उस प्रदेश से लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं, वहां से दूसरे प्रदेश में जाने की स्थिति पैदा होती है। मुझे विश्वास है कि आप राज्य सरकारों को समुचित निर्देश देंगे और जो खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होगा, उस संकट से भी लोगों का उबारने की जरूरत है। मेरा अनुरोध है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर माननीय कृषि मंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे और इसके अनुसार हर राज्य सरकार को निर्देश देंगे, ताकि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में इस कंटिंजेंसी प्लान के अंतर्गत जहां जरूरत हो, वहां पर केन्द्र सरकार को भी आर्थिक मदद देनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): महोदय, मैं समझता हूं कि आज सदन में जो चर्चा हुई है, एक बहुत सार्थक चर्चा हुई है। सभी सदस्यों ने अपने-अपने एक्सपीरिएंस के हिसाब से माननीय मंत्री को जो सजेशन्स दिए हैं, इनका एक सार्थक रिजल्ट आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं अपनी बात अपने पंजाब प्रदेश से शुरू करना चाहता हूं। जब भी देश में ऐसी कोई ऐसी स्थिति आई है, तो पंजाब ने हमेशा यह कोशिश की है कि किसान सूखे से बच जाए। इसके लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई है कि किसान के लिए फ्री बिजली हो। इस योजना का हमारे ऊपर खर्चा भी पड़ रहा है। जब ड्राउट की स्थिति आती है, तो पंजाब का किसान सरकार की मदद से अपना ट्यूबवैल चला कर, अपनी फसल बोने का काम करता है। इसमें किसान को यह मुश्किल आती है कि जब बारिश नहीं होती, तो जमीन का पानी नीचे चले जाने के कारण, उसको ट्यूबवैल को और नीचे करना पड़ता है। इसमें जो खर्चा आता है, वह इसके वश की बात नहीं है। माननीय भुंडर साहब ने जो बात कही है, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय कृषि मत्री इस ओर ध्यान दें और जो सरकारें अपने किसान को इस ढंग से बचाने की कोशिश करती हैं, उनको कोई न कोई राहत जरूर दें। अगर सूखा पड़ता है तो एक बड़ी विचित्र सिचुएशन पैदा हो जाती है। जो किसान लोगों का पेट भरता है, उसी किसान को सूखा पड़ने की वजह से मांगने का काम करना पड़ता है। जब सूखा पड़ता है तो बाहरी प्रदेशों से जो बाहरी प्रदेशों से जो लेबर आनी होती है, उस लेबर का आना बंद हो जाता है। जैसे पंजाब का किसान है, वह पैदावार करने के लिए तैयार है, अपने सोर्स बरतने के लिए भी तैयार है, लेकिन जब सूखे का वातावरण बनता है, तो बाहर से लेबर न आने की वजह से उसके लिए दुविधा खड़ी हो जाती है। सर, यह साइकल है कि चारा नहीं होगा तो दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा, तो दूध से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी भी कमी हो जाएगी, जिसका सीधा संपर्क महंगाई से हो जाता है। मैं समझता हूं कि सूखा एक ऐसी समस्या है, जिसके कारण देश की इकॉनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसी योजनाएं बननी चाहिए कि जिन प्रदेशों में, जहां पर बार-बार सूखा पड़ता है, सरकार उनको अंकित करके, रैक्टिफाई करके उनकी क्या मदद कर सकती है, इसके बारे में सोचे। फसल की कमी न हो, सूखा नह हो और किसान के ऊपर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार को एक बहुत बड़ी योजना बनानी पड़ेगी।

[श्री अविनाश राय खन्ना]

चेयरमैन सर, एक दूसरी बात जो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि जो नदियां, नालें या नहरें हैं, उनका समय पर रिपेयर न होना एक समस्या है। जब पानी आता है, तो कई बार रिपेयर न होने के कारण, जो पानी किसानों को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। मुझे सदन को बताते हुए इस बात की खुशी है कि जब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था, तो उसमें किसानों के मुद्दे को लेकर हमारी सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई थीं। मैं चाहूंगा कि इसके लिए सरकार जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको यूज करे। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो योजनाएं अनाउंस हुई हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी काम शुरू होगा। जैसे "एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर" योजना है, सरकार ने उस पर बहुत स्ट्रेस दिया है। इसके लिए सरकार ने एग्रो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूज करके किसान की मदद करने का जो फैसला लिया है, वह एक बहुत ही सराहनीय कदम है।

एक विषय, जो बार-बार आया है, वह यह है कि किसान के लिए पानी एक बहुत इम्पॉर्टेन्ट फैक्टर है। यह एक सच्चाई है। उसके लिए हमारी सरकार ने नेशनल लेवल पर "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई" का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार उस पर भी बहुत जल्दी काम शुरू करेगी।

एक नारा, जो हमने बार-बार दिया है, वह है "हर खेत को पानी"। मैं समझता हूं कि जितनी समस्याएं आज यहां डिस्कस हुई हैं, वे समस्याएं ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि किसान को समय पर पानी नहीं मिलता है। अगर परमात्मा खुश है और बारिश टाइम पर हो गई तो पानी मिल जाएगा, नहीं तो हमें जमीन या नहरों से पानी निकालकर उसके खेतों को देना पड़ेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार की हर खेत को पानी देने की जो कमिटमेंट है, उसके लिए बहुत जल्दी इन सभी योजनाओं पर काम होगा। इससे हमारे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। "पर ड्रॉप मोर क्रॉप", अर्थात् पानी की एक-एक बूंद बचाने का हमारा जो नारा है, योजना है, उसका फायदा हमारा किसान उठाएगा। माननीय कृषि मंत्री जी को इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमने जितनी योजनाएं सोची हैं और हाउस में जिस ढंग से आज यह चर्चा हुई है, वह उपयुक्त है।

सभी लोग इस बात पर सहमत होंगे कि हमारे किसान के लिए यह जो ड्राउट की सिचुएशन है, यह एक ऐसी बीमारी है, जिसके इलाज के लिए सरकार को शायद बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। हमें इन योजनाओं को जल्दी और समय पर लागू करने के बारे में भी सोचना होगा ताकि किसान को उसका बेनिफिट समय पर मिले।

(**उपसभापति महोदय** पीठासीन हुए)

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसा कि मैंने पंजाब का उदाहरण दिया है कि हम बिजली फ्री देकर अपने किसान को इस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करते हैं, तो पंजाब जैसे ही कुछ अन्य राज्य भी हैं, जहां पर किसान को फ्री बिजली दी जाती है। मैं समझता हूं कि उस स्थिति में उन राज्यों की ओर किसान की मदद करना एक बहुत ही जरूरी कदम होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर निवेदन करूंगा कि जो योजनाएं हमने सोची हैं और लोगों से कही हैं, आप उनके ऊपर जल्दी से जल्दी काम शुरू करके किसान को पूरा लाभ दें। मैं इस विश्वास के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

SHRI Y.S. CHOWDARY (Andhra Pradesh): Thank you very much, Sir. Across the country we have this problem of drought because of the failure of the monsoon. But I would particularly like to talk abot Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh the rainfall is

almost only 60 per cent. It is what that has been declared so far. Crops like paddy, groundnut and many others have been sown in less than 25 per cent area. As everyone know, Southwest monsoon is very crucial because 60 per cent of the cultivable land is rain-fed across the country. The drought situation in all the 13 districts of Andhra Pradesh is looming large with a deficit rainfall which has been recorded in all these districts. The predictions of weathermen for July and August are by no means encouraging. It is already too much delayed. There seems to be no hope for the *Kharif* crop unless the monsoon becomes vigorous in July and August. But it looks unlikely. The water levels in all the reservoirs are going down alarmingly and the Nagarjunasagar is almost touching the dead storage point. There is no remedy for that. The position in the Krishna delta to which water is released form Prakasam barrage at Vijayawada is quite hopeless this year. Only 6 tmc ft. water has been allocated so far to the delta for dringking water purposes. To make the matters worse the water level in the Godavari delta also is drastically reduced in this year, as a result both the East and West Godavari districts are likely to face a huge water shortage. I, therefore, request the Government to kindly draw up the contingency plans to save crops and provide adequate financial assistance to the State of Andhra Pradesh which is already facing a huge financial problem. As it cascaded in the past, except in 81 *mandals* of Andhra Pradesh, all were reported to be as drought affected areas. There is huge pendency at the SLBC level. Requests have been made for re-scheduling of farmers loans. We request that it should also be expedited. A total of 13,754 and 11,772 suicides were reported in 2012 and 2013 respectively which is also very alarming. According to the NCRB report, the instances of farmers' suicide have been continuing in the State of Andhra Pradesh. Therefore, I request the Government of India to lay special emphasis on resolving these issues, Sir. In the past for whatever reasons, there was a huge neglect of farming and agricultural community. So, I request once again that at least the new Government, the NDA Government takes special interest to help farmers. I am very hopeful that the NDA Government would do so. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much, Chowdary*ji*, It is very interesting to listen to you speaking in a calm and good atmosphere. ...*(Interruptions)*...

SHRI Y.S. CHOWDARY: I am a changed person, Sir, 'new Chowdary'. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you. Dr. K.P. Ramalingam.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): He is an Unattached Member. ...*(Interruptions)*... Does he represent DMK (K), DMK (S), DMK (A) or DMK (R), DMK (Ramalingam)? I want to know it. ...*(Interruptions)*... DMK (R) means DMK (Ramalingam). I seek a clarification on this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He may give a clarification. ...*(Interruptions)*...

5.00 P.M.

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Today I am speaking as a Rajya Sabha Member. ...*(Interruptions)*... Mr. Deputy Chairman, Sir, in 1972 the Irrigation Commission had identified 67 districts as drought prone. In 1976 the National Commission for Agriculture identified 74 districts. Now the Minister is giving a statement outside in newspapers that this year we are going to have 500 districts under drought. This is not a new thing. In the 18th century, our country faced drought for 9 years; in the 19th century, for 12 years; and, in the 20th century, for 11 years. So, it is a continuous process. Today, in this House, I want to speak from the core of my heart. So, I want to speak in Tamil.

*People's representatives, both in this August House and in the legislative assemblies of States, participate in the discussion about drought. This is an usual phenomena. My Hon'ble Colleagues Mr. Jayaram Ramesh, and Mr. Sharad Pawar, the former Union Minister of Agriculture, discussed many points here. Their objectives and thoughts are good. The people in the incumbent Government also have good objectives. But in order to implement all these good objectives, the Ministry of Agriculture has to be given due importance. I such importance is given to the Ministry of Agriculture, the portfolio of agricultural Ministry should have been under the chairmanship of Prime Minister. Or else, Mr. Rajnath Singh, the Minister of Home Affairs, should take additional charge of the Ministry of Agriculture. Or else, Mr. Arun Jaitley, the Minister of Finance, should take additional charge of the Ministry of Agriculture.

In Tirukkural, the great lierature of Tamil, it is said,

Who ploughing eat their food, they truly live :

The rest to others bend subservient, eating what they give (Couplet No. 1033)

It means, 'they alone live who live by agriculture; all others are living a cringing, dependent life.'

But today, none is following the peasants. Instead, the peasants are running after others for their survival. We are in a position to depend on the Prime Minister and the Finance Minister for all the schemes. I have already mentioned in this House that there should be an exclusive budget for agriculture, as is done in the case of Railways. When a Government initiates an exclusive budget for agricultre, only then will agriculture flourish.

If the Government is rreally concerned about the development of agriculture, there has to be exclusive budget for agriculture. We pay attention to protect heritage sites. We pay attention to protect temples. It is mentioned about the protection of Rameshwaram temple. Importance is given to the protection of temples as it is believed that culture is preserved in temples.

*English translation of the original speech made in Tamil.

But, had they protected agriculture? Had they protected the water bodies of India? Had they protected the lakes? Many schemes were planned for full utilization of all water bodies of India. Had they been implemented? It they have implemented those schemes, the rivers would have been interlinked. Last year, Mr. P. Chidambaram was the Minister of Finance. When he presented the budget last year, I told that it was not impossible to interlink rivers. When it is possible to give Samsung and iphone mobiles phone sets in the hands of ordinary labourers, it is possible to interlink rivers also. It is possible to protect the farmers. I raise the same issue now. If we do not pay proper attention to agriculture, the same situation will continue after ten years also. Otherwise, some other person will raise the same issue in this House after ten years also.

Ours is an agricultural country. Our Governments, whether it is the Central Government or the State Governments, should initiate many schemes for protection of agriculture. In the budget, 80% of the amount should be allocated to agriculture continuously for five years. Only then will the problems be solved. If other professions are forgotten by the professionals, we can manage. But, if farmers forget agriculture, what will we do? Who can provide food to hundred crore people of India? None can provide. There is no such country in the world to provide food to all Indians. It is our farmers who can provide food to India. It is your responsibility to protect the farmers. We have to formulate long term plan. We should have an exclusive budget for agriculture. That is the measure to solve all problems with respect to agriculture. With these words, I conclude my speech. Thank you.

DR. V. MAITREYAN: Sir, I did not get the answer for my question. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Pardon.

DR. V. MAITREYAN: The display board mentions Party's name.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:As far as our record goes, it is like that. It is for them to give the intimation if there is a change. Now, Shri Madhusudan Mistry.

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात)ः उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया है।

सर,अभी तक मैं कम-से-कम पांच से छः अकाल देख चुका हूं। उनमें मैंने काफी काम भी किया है, खास कर के अकाल राहत के जो काम हैं, उनमें मजदूरों को पूरा पैसा मिले, उस पैसे में कोई घपला न हो और काम चालू हो। गुजरात के जो डेज़र्ट के इलाके हैं, जो मेरी पुरानी कांस्टीचुएंसी के इलाके हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : One second. It is already five o'clock. We will complete it today. So, may be, we will sit for one hour more. Do you agree?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

DR. V. MAITREYAN: We can finish it today and the reply can be the next day.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Minister is here, he can reply also. ...*(Interruptions)*... No, that is up to the Minister. But, anyhow, we will complete it. We will sit. Okay. Thank you.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : गुजरात-राजस्थान, गुजरात-मध्य प्रदेश, गुजरात-महाराष्ट्र और गुजरात से लगे हुए दूसरे राज्यों के आदिवासी इलाकों के अन्दर अकाल में किसानों की क्या स्थिति होती है, उस तक ही मैं अपनी बात सीमित रखूंगा और सरकार से विनती करूंगा कि क्या-क्या स्टेप्स उसे लेने चाहिए।

सर, मेरी सबसे पहली बात यह है कि चूंकि हिली रीजन में नीचे के इलाके में डैम बांधे जाते हैं और इस इलाके में इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, इसकी वजह से अगर वहां के किसान अपनी फसल बारिश में नहीं उगा सकते, तो वहां पूरी स्टार्वेशन की स्थिति होती है और उनकी परचेज़िंग पॉवर बहुत ही कम हो जाती है। मैं तरुण विजय जी का भाषण सुन रहा था। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शायद अभी वे बिज़ी हैं। **...(व्यवधान)...** मैं कह रहा हूं कि मैं आपका भाषण सुन रहा था और मैं आपके साथ सहमत हूं। मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है कि आपकी पार्टी का जिन राज्यों में शासन है, जैसे-गुजरात,मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड वगैरह, कहीं उन राज्यों में स्टार्वेशन डेथ न हो। इसके लिए वहां एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत पूरे-पूरे काम चलाए जाएं, लोगों को पूरी-पूरी तनख्वाह मिल जाए और उनकी परचेजिंग पॉवर बरकरार रखी जाए, जिससे वे धान खरीद सकें और वहां भूखमरी की स्थिति पैदा न हो। अगर कहीं कोई आदमी भूख से मर भी जाए, तो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में ऐसा न आए कि यह आदमी भूख से नहीं मरा है बल्कि यह दूसरी किसी बाबत से मरा है, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक भी स्टार्वेशन डेथ मान ली जाए तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है। इससे बाइ एण्ड लार्ज किसी भी स्टेट में जो स्टार्वेशन डेथ होती है, उसका पोस्टमॉर्टम के बाद कभी सर्टिफाई नहीं किया जाता है कि यह डेथ स्टार्वेशन से हुई है। उसका सबसे अच्छा नजरिया यही है कि इसके लिए काम शुरू किया जाए, काम बडे पैमाने पर हो, उनको पूरे पैसे मिलें और उनकी परचेजिंग पॉवर वैसी की वैसी ही रहे। उनको और भी ज्यादा रिलीफ देने के लिए मेरी आपसे विनती है कि जिन राज्यों ने यह सोच कर फूड सेक्यूरिटी ऐक्ट पर अमल नहीं किया है कि केन्द्र की यूपीए सरकार यह योजना लाई है और अगर हम इस पर अमल करेंगे, तो लोग शायद कांग्रेस को वोट दे देंगे, इसलिए इस पर अमल चुनाव के बाद किया जाए, मेरी आपसे विनती है, क्योंकि अब आप सत्ता में आ गए हैं, कि जिन राज्यों ने इस पर अमल नहीं किया है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप जरा इन राज्यों में इस पर अमल करवाइए, जिससे वहां लोगों को एक रुपए किलो मोटा अनाज, दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल मिल सके, जिससे उनका जो माल-न्यूट्रिशन का लेवल है, वह और न बढ़े, बल्कि उसी लेवल पर बना रहे, क्योंकि इन इलाकों में उनकी सेहत के ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। यह मैंने सालों से देखा है, क्योंकि न्यूट्रिशन के मामले में आपके जो क्राइटिरियाज हैं, वे इस प्रकार के हैं कि उनको जितनी तनख्वाह या जितना पैसा रोजमर्रा पर मिलता है, उनसे उनकी पूरी फैमली का गुजारा नहीं होता है और वे क्रॉनिक स्टार्वेशन की स्थिति में आ जाते हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री तरुण विजय: भुख का कोई प्रदेश नहीं, भूख की कोई राजनीति नहीं, जहां भी भूख है, हम और आप मिलकर उसका समाधान करने का काम करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, मेरी तो इनसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वे अपना influence उन सरकारों के ऊपर करें और इस पर अमल करवाएं।

सर, दूसरी बात यह है कि इस पूरे इलाके में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत दिक्कत है। इसके लिए या तो आप उन इलाकों में नहरों से पानी पहुंचाइए या फिर पानी के लिए कोई दूसरी व्यवस्था कीजिए। हमारे यहां गुजरात मॉडल में ऐसा हुआ कि अभी तक सबसे ज्यादा पानी टैंकरों से पहुंचाया गया है। आज भी बहुत इलाकों में,जैसे सौराष्ट्र इलाके में, कच्छ इलाके में, नॉर्थ गुजरात में, राजस्थान के बाड़मेर, सांचोड़ जिलों से सटे जो गुजरात के इलाके हैं, वहां पर टैंकरों के द्वारा पानी पहुंचाया जाता हैं।

मेरी सरकार से और भी विनती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे राज्य से आते हैं और उन्होंने अभी नर्मदा की हाइट बढ़ाई है, लेकिन नर्मदा का पानी मेन कैनाल्स के अंदर ही है, चूंकि उन कैनाल्स की tributaries खेतों तक नहीं गई है, इसलिए नर्मदा की कैनाल्स तो भरी होती हैं, नदी की तरह बड़े-बड़े कैनाल्स हैं,लेकिन उनका पानी खेतों तक नहीं पहुच पाता है। अहमदाबाद में जो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है, उसके अंदर पानी डाला जाता है, लेकिन उस पानी को खेतों तक नहीं लाया जा सकता है, क्योकि इतने सालों के बावजूद गुजरात की सरकार और केन्द्र सरकार की वजह से,जो tributaries खेतों तक पानी ले जाने के लिए बनानी चाहिए थीं, वे नहीं बनीं और इसकी वजह से नॉर्थ गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र के बहुत सारे इलाके पीने के पानी और खेतों की सिंचाई से वंचित हैं।

सर, हमारे इलाके में agriculture sowing अभी बिल्कुल नहीं हुई है। नॉर्थ गुजरात में तो आज की तारीख तक बारिश नहीं हुई है, इसके अंतर्गत साबरकांटा का इलाका आता है, बनासकांटा का इलाका आता है, पाटन का इलाका आता है, कच्छ का इलाका आता है, राजस्थान का सांचोड़ का इलाका आता है, मेरे ख्याल से बाड़मेर का इलाका, झालोर का इलाका, ये सब जो उदयपुर का पूरा रीजन है, उसके अंदर शायद ही कहीं पर बारिश हुई है। इसकी वजह से वहां मकई की जो मुख्य फसल है, उसकी बहुत शॉर्टेज होने वाली है। इसकी वजह से परिस्थिति और भी खराब होने वाली है।

सर, हमारे यहां आदिवासियों में ऐसी मान्यता है कि अगर बारिश नहीं होती है, तो बारिश को गांव के बनिए ने बांध कर रखा है और इसकी वजह से उनके ऊपर हमले होते हैं और वहां जिनकी दुकान वगैरह होती है, वे लोग सब छोड़ कर दूसरी जगह चले जाते हैं। चूंकि मान्यता यह है कि ये बारिश को छोड़ते नहीं हैं और बारिश को बांध कर रखते हैं, इसकी वजह से लॉ एण्ड ऑर्डर की सिच्युएशन खड़ी होती है। **(समय की घंटी)**।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now please conclude.

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वह इस सिचुएशन के अंदर और भी वलनरेबल है, क्योंकि वहां इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। उसे पूरे 365 दिन यह फैसिलिटी न मिले, लेकिन कम से कम 180 या 200 दिन उसे इरिगेशन की सहूलियत तो मिलनी चाहिए। एमएनआरईजीए का काम इन राज्यों में जहां चालू होना चाहिए था, वहां अभी तक चालू नहीं हो पाया है और इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर वहां से लोगों का पलायन बड़े शहरों में होता है, जहां पर उनका सबसे ज्यादा शोषण होता है। इसलिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मेरी विनती है कि आपका जो रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, उसके साथ-साथ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस पर

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

विचार किया जाए। अगर उन लोगों को वहीं पर काम दिया जाएगा और उन्हें पूरा पैसा दिया जाएगा, तो उनका पलायन रुक सकता है। उनके पास पैसे होने से और उनके यहां फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने से उनको अनाज सस्ता मिल सकेगा। इस वजह से वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या भी खड़ी नहीं होगी, उनके सामने मालन्यूट्रिशन की समस्या भी नहीं आएगी और वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट पर इस सिचुएशन के कारण जो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, वह भी नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। सन् 1987, 1988 और 1989 के अकाल के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हुई थी कि हमारे यहां राजकोट और सौराष्ट्र के अंदर लोगों को पानी पिलाने के लिए पानी की ट्रेन भेजनी पड़ी थी। **(समय की घंटी)**। Just a minute, Sir.

सर, एमएनआरईजीए के बारे में मेरी आपसे यह विनती है कि उसमें मिनिमम डेली वेज की राशि को और बढ़ाना चाहिए। अभी जो इसकी खामियां हैं, खासकर इसमें पैसे का जो प्रोसेस है, उसके अंदर प्रधान भी शामिल होता है, बीडीओ भी शामिल होता है और उसमें रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा-सा भी चेक लाएंगे, तो मैं मानता हूं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो इलाके हैं, खासकर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहां के लोगों को बहुत बड़ी राहत और सहूलियत मिलेगी।

अब मैं फॉडर की बात कहता हूं। मुझे पता नहीं कि इस बार शुगरकेन की क्रॉप कितनी हुई। जैसे, साउथ गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के नंदुरबार आदि इलाकों में शुगरकेन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। शुगरकेन से जूस निकालने के बाद जो भाग बच जाता है, उसको फॉडर के रूप में यूज़ किया जाता है और उसके माध्यम से मवेशियों को बचाने का काम किया जाता है। मेरी आपसे विनती है कि जहां-जहां पर शुगरकेन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, वहां पर उस भाग का स्टॉक अभी से रिज़र्व करके रखा जाए और जरूरतमंद इलाकों में उसे दिया जाए, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के डेजर्ट के इलाके तथा ट्राइबल इलाके के अंदर मवेशियों की सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इतना ही नहीं, रोज़मर्रा के काम तथा खेती में ये मवेशी ही उनके काम आते हैं, इसलिए इनको बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please conclude.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इसका अभी से रिज़र्व स्टॉक करके, राज्य सरकारों को सतर्क करके तथा उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाकर, जान-माल की जो क्षति होने वाली है, उससे बचा जाए। आपका शुक्रिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now Vishambhar Prasad Nishad; you have less than five minutes.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे सूखे एंव अल्प वृष्टि के बारे में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, आदरणीय प्रो. राम गोपल जी और नरेश अग्रवाल जी ने मुझे जो समय दिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। आजादी के 66 साल से अधिक बीतने के बाद भी हम लोग कृषि को बेस मान कर नहीं चल पाए हैं। जब तक खेती-किसानी की तरक्की नहीं होगी, तब तक देश तरक्की की तरफ नहीं जा सकता है। आज जिस तरह से

कम वर्षा के कारण पूरे देश में सूखे की स्थिति आ गई है, उससे पूरा देश चिंतित है। आज किसान भुखमरी की कगार पर आ गया है। मैं बुंदेलखंड से आता हूं। बुंदेलखंड में जमीनें फट रही हैं। वर्षा न होने के कारण जमीनों में दरारें पड़ रही हैं और किसान पलायन कर रहा है। किसान ने जो थोड़ी बहुत फसल उगाई थी, वह सारी की सारी सूख गई है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर किसान परेशान है, संकट की घड़ी में है। भारत सरकार को ऐसा उपाय करना चाहिए, चूंकि हमेशा बुंदेलखंड पर राजनीति होती है, बुंदेलखंड पर लोग चर्चा करते हैं कि वहां के लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। बातें काफी की गईं, लेकिन काम उतना नहीं हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में नहरों का पानी और राजकीय ट्यूबवैलों का पानी फ्री कर दिया है, जिससे किसानों को काफी राहत मिली है; लेकिन नदियों में पानी नहीं है। जब वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा। बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं- बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ललितपुर और जालौर में कभी पाला, कभी ओला तथा कभी सूखे से किसानों को जूझना पड़ता है। पांच साल में कम से कम दो बार, तीन बार किसानों को ऐसी आपदा से गुजरना पड़ता है। वहां जो किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं, भारत सरकार ने बैंकों के माध्यम से जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई थी, उसमें किसान की जमीन बंधक रख दी जाती है। महोदय, इससे उनके ऊपर इतना बोझ हो जाता है, जब 5 साल के अंदर दो-दो, तीन-तीन बार सूखा पड़ेगा, कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं फसल खराब होगी, तो किसान समय से कर्जा अदा नहीं कर पाता है, जिसके कारण किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है या किसान पलायन करता है। भारत सरकार को कोई ठोस उपाय करना चाहिए। वैसे भी हमारे देश में 60 परसेंट कृषि वर्षा पर आधारित है। बुंदेलखंड में तो 80 फीसदी कृषि वर्षा पर आधारित है। बुंदेलखंड में बड़ी मात्रा में दलहन, तिलहन होता है। माननीय कृषि मंत्री जी बुंदेलखंड के दलहन और तिलहन के ऊपर शोध कराएं,क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय विद्वान सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी तथा अच्छे सुझाव रखे, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। आजादी के इतने साल बीतने के बाद जो लोग सरकार में रहे हैं, उनको सोचना चाहिए था कि कृषि विश्वविद्यालय में बड़े-बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज देश में किसानों के ऊपर संकट है। हम चाहते हैं कि जो किसानों के क्रेडिट कार्ड बनते हैं, उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए। जो सूखा पीड़ित किसान हैं, उनके कर्जे माफ होने चाहिए। किसानों को सूखे से निबटने के लिए क्षतिपूर्ति, महगाई के अनुसार बढ़ाकर दी जानी चाहिए। रबी की बुआई के लिए भारत सरकार द्वारा निशुल्क खद और बीज का इंतजाम किया जाना चाहिए, मुफ्त डीजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, पूरे देश में 30 परसेंट वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिनों-दिन पेड़ काटे जा रहे हैं और जिस तरह से तेजी से पेड़ों का कटान हो रहा है, उससे वर्षा कम हो रही है और मानसून पर प्रभाव पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी बुंदेलखंड में 40 हजार हेक्टेयर भूमि ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई थी। अभी किसान एक पीड़ा से नहीं उबर पाया है और उसके लिए दूसरी मुसीबत तैयार हो गई है।

श्री उपसभापति: समाप्त कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: बुंदेलखंड में जल संचयन का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। वैसे तो हम लोग देख रहे हैं, आज पूरे देश में 540 जिलों में पानी की बड़ी समस्या है। प्रशांत महासागर में अलनिनो की स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि जो सम्पन्न देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, वे वहां एक से एक प्रयोग करते हैं। वहां गरम हवाओं से अलनिनो पैदा हो गया, वहां से अमेरिका को तो फायदा हुआ। हमारे कुछ साथियों ने वहां से चुनाव मेनेजमेंट, (प्रबंधन) लिया है, तो हमारे देश में एक के साथ एक

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

फ्री। उन्होंने मेनेजमेंट, प्रबंधन के साथ अलनिनो फ्री में दे दिया, इससे हमारे देश का नुकसान हो गया। ये तमाम समस्याएं हैं। हमको भी अपने देश में इसके कारण चाहे सूखा हो, बाढ़ हो या अन्य कोई चीज हो, इसके बारे में सोचना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Bhupinder Singh, you speak for five or six minutes only.

SHRI BHUPINDER SINGH (Odisha): Sir, this is my maiden speach.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then you don't speak today. Your party has no time.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, I will not take more than five or six minutes. महोदय, आज जो चर्चा चल रही है सदन में, आज सारे देश का किसान हमारी ओर नजर किए हुए है। वह उम्मीद कर रहा है कि इस सदन के माध्यम से आज उनको सरकार की तरफ से ऐसी कुछ पॉजिटिव बातें कही जाएंगी, जिनसे उसका मनोबल बढ़ेगा और आज रात कम से कम वह अच्छी तरह से सो सकेगा। महोदय, हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन वे पूछते हैं कि यहां किसान को कहां प्रधानता दी जाती है?

सर, मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स उठाना चाहता हूं। आज जो ऐसे इरेटिक मानसून की स्थिति बनी है, इस के लिए हमने पिछली दो सदियों में क्या व्यवस्था की है? हम उसी वक्त सोचते हैं, जब हमारे सामने सूखा, अकाल या फ्लड की सिचुएशन आती है या हमारे सामने फाइलिन साइक्लोन जैसी परिस्थिति पैदा होती है। आज मैं आप के माध्यम से पूरे सदन और सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इस पर सीरियसली विचार कीजिए कि आज ऐसी क्या मैथॉडोलॉजी है, जिस में इंसान को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है? मैं अपने देश के साइंटिस्ट्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने स्पेस तक में अपनी सफलता के झंडे फहराए हैं, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि हम आज की इरेटिक मानसून की स्थिति से निजात पा सकें? सर, आप देश और राज्य की बात छोड़ दें, आज यहां ऐसी भी स्थिति देखने में आती है, जहां पार्लियामेंट हाउस में बारिश हो रही है, लेकिन एनेक्सी में बारिश नहीं होती है। आज देश के लोग इस सदन से इस इरेटिक मानसून की स्थिति का जवाब चाहते हैं।

महोदय, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। मैं उड़ीसा से आया हूं। हमारे मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी ने पिछले दो सालों से कृषि के लिए एक स्पेशल सेपरेट बजट बनाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि यहां भी रेल बजट की तरह स्वतंत्र कृषि बजट आए।

सर, अगर इस देश में कोई दुखी है, तो वह किसान है। मैं इस सदन से देश के किसान को सैल्यूट करता हूं। आज हम, हमारे दादे-परदादे और किसानों के पैसों से बड़े लोग बने हैं। हम चाहे राज्य सभा में आएं, लोक सभा में आएं या वहां ऑफिसर्स गैलरी मे बैठें, यह सब उनकी देन है और हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। लेकिन वही किसान जब किसी ऑफिस में जाता है, तो उसे वहां कोई आदर नहीं मिलता, उसको पानी का गिलास तक नहीं मिलता है। वह वहां धोती पहनकर जाता है, इसलिए उसे कोई नहीं पूछता है। आज 21वीं सदी में इस बारे में कोई व्यवस्था अगर इस सदन से नहीं होगी, तो उसे अपना आदर कहां मिलेगा? महोदय, मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस इरेटिक रेनफाल के लिए कुछ व्यवस्था करे। Sir, I wish let there be no Third World War. आज मेरा

बच्चा भी मुझ से कहता है, मेरा पोता कहता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होगा, तो वह वाटर को लेकर होगा। महोदय, आज जो समस्या राज्यों के बीच चल ही है, इस मुद्दे पर हमें बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए और इस का जवाब हमें इस सदन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हम यहां से "मनरेगा" और बाकी योजनाओं के लिए पैसा देते हैं। अगर ड्राउट होगा तो लोगों को ठेका मिलेगा, लेकिन किसान पूछता है कि मुझे क्या मिला? वह पूछता है कि मैंने जो ब्लैक में खरीदकर फर्टिलाइज़र लगाया, सीड खरीदा, मुझे उससे क्या मिला? महोदय, अगर मेरी कार में थोड़ी सी टक्कर लग जाती है, तो इंश्योरेंस वाला हाथों-हाथ मुझे पैसे दे देता है, लेकिन आज किसान इंश्योरेंस के पैसे देता है, फिर भी क्रॉप इंश्योरेंस के लिए उस की सुनवाई नहीं होती। इस बारे में केन्द सरकार को सभी राज्यों के साथ मिलकर व्यवस्था करनी चाहिए। मेरी प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है। आज इस की आवश्यकता है। Let there be a uniform policy for agriculture and farmers in the whole country. ठीक है, आज पंजाब फ्री ऑफ कॉस्ट इलैक्ट्रिसिटी दे रहा है और कुछ राज्य भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलैक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। मेरा राज्य भी ऐसा करना चाहता है, लेकिन यह इलैक्ट्रिसिटी आएगी कहां से? आज उड़ीसा में बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जब बारिश ही नहीं होगी, रिज़र्वायर में पानी ही नहीं आएगा, तो इलैक्ट्रिसिटी कहां से बनेगी? हम प्रोजेक्ट्स बनाते जाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां इरिगेश्यान परसेंटेज 30 से 40 परसेंट पहुंच गया, लेकिन अगर वहां बारिश नहीं हुई, इंद्र देवता नहीं आए, तो उस प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते थे, तो यह नहीं पूछते थे कि क्या बीमारी है? वह कहता था कि यह दवाई खा लो, सिर दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन आज का किसान हमसे पूछता है कि आप हमें यह बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? पानी क्यों नहीं आ सकता है, जबकि आप स्पेस तक पहुंच सकते हैं?

श्री उपसभापति: हो गया। बस, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री भूपिंदर सिंह: सर, लास्ट में मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि let there be coordination Committee of the Ministers. It is not an issue of the Agriculture Ministry alone. It is involvement of many more ministries. यह जो सुझाव आया है, मिनिस्टर को बैठा कर इसके ऊपर विचार किया जाए, फार्मर्स का लोन पीरिएड एक्सटेंड किया जाए और इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए स्टेट को सपोर्ट किया जाए। साथ ही वाटर बॉडीज के थ्री आर (रिड्यूस, रियूज़ रिसाइकिल) जो गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिसी में हम दे रहे हैं तथा माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड चैक डैम, उन पर ध्यान दिया जाए। महोदय,उड़ीसा के लिए सरकार को स्वतंत्र होकर विचार करना चाहिए, क्योंकि वहां के फार्मर्स में, एग्रीकल्चरल एरियाज में haves and have nots का एक बहुत बड़ा गैप है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उड़ीसा के लिए आप स्वतंत्र रूप से विचार करें। धन्यवाद।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, हम आज सदन में खेती पर, पानी पर और सूखे पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत से स्पीकर्स ने अपनी-अपनी बात कही, राम गोपाल यादव जी ने इस चर्चा की शुरुआत की। एक बात तो स्पष्ट है कि इस देश के किसानों को प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, उनको कोई हिम्मत नहीं मिल रही है। जैसा कि भूपिंदर सिंह जी ने कहा कि जब कोई किसान सरकारी कार्यालय में धोती पहन कर जाता है, तो उसे कोई पानी तक नहीं पूछता। अब मुझे लगता है कि चूंकि हमारे कृषि मंत्री भी धोती पहनते हैं, तो उनको प्रतिष्ठा मिलेगी। आप हमारे किसानों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए अब जब धोती पहनने वाला किसान सरकारी कार्यालय में जाएगा, तो उसको कुर्सी मिलेगी।

श्री उपसभापति : आजकल किसान पैंट भी पहनते हैं।

श्री संजय राउत : जी हां। अब प्रतिष्ठा मिलेगी, जैसा कि भूपिंदर जी ने कहा कि धोती पहनने वाले को प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, जो किसान है।

उपसभापति महोदय, जहां तक कम बारिश की बात है, पूरे देश में कम बारिश है। यह बारिश महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, ओडिशा में है। आपने अब तक तो सूखा डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जो खतरे की घंटी है, क्योंकि कम बारिश से आर्थिक और सामाजिक चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। जीवन जीने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता है। आज मैं महाराष्ट्र में देखता हूं कि कई इलाके ऐसे हैं, जहां बूंद-बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, जैसे बीड है, जालना है, औरंगाबाद है, इनके समेत 15 जिलों में 7000 गांव और लाखों लोग ऐसे हैं, जो या तो बूंद-बूंद पानी के लिए भाग रहे हैं या गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। ये शहर कौन से हैं? मुंबई है, थाणे है, पुणे है। इन तीन-चार शहरों की तरफ गांव के लोग आ रहे हैं, जबकि इन शहरों में भी आज पानी की शॉर्टेज है। इन शहरों में जो पानी सप्लाई करने वाले तालाब हैं, जलाशय है, उनका पानी भी कम हो रहा है, क्योंकि वहां बारिश नहीं है और वहां की म्युनिसपल कॉरपोरेशन ने 20 या 25 परसेंट पानी की सप्लाई कम की है। मुम्बई के तालाब की स्थिति ऐसी है कि वहां सिर्फ एक महीने के पानी का स्टॉक बाकी है। अब लोग जब बाहर से आएंगे, तो उससे शहरों पर दबाव ज्यादा बढ़ेगा, जबकि मुम्बई वाले, पुणे वाले भी, थाणे वाले भी पानी के संकट से पहले ही जूझ रहे हैं। आज सुबह मैं महाराष्ट्र में विदर्भ से जानकारी ले रहा था। वहां बारिश में जो विलंब हुआ है, उसकी वजह से बुलडाना जिले में बुआई प्रभावित हुई है। इसका असर फसलों पर पड़ेगा,उत्पादन पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी तथा कीमतें प्रभावित होंगी। आज खेतों में काम नहीं है, इसलिए खेत के मजदूर भी खाली बैठे हैं। अब जुलाई खत्म होने को है, फिर भी तूर, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलों की बुवाई आज तक हमारे मराठवाड़ा विदर्भ में नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। बारिश तो कम है, लेकिन यह जो पानी का संकट है, यह एक मैन-मेड संकट है, इंसान की गलतियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। बारिश नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं तो खेती नहीं, अनाज नहीं, लेकिन यह बारिश का चक्र क्यों बदल गया है? यह क्लाइमेट चेंज, अन्न का संकट क्यों बढ़ गया है? हमने जंगल काटे हैं, हमने पहाड़ काटे हैं, हमने नदियों से खिलवाड़ किया है और हमने मुम्बई में भी देखा कि समुद्र में मिट्टी डालकर वहां बड़ी-बड़ी इमारतें, रेक्लमेशन करके टॉवर्स खड़े किए हैं, उस सबका ही परिणाम है कि आज प्रकृति ने हमसे बदला लिया है और बारिश कम हुई है। इसके परिणाम आज हम भुगत रहे हैं।

सर, जब हम पूरे देश के सिंचन की बात करते हैं, तो बहुत सालों से हमने इरिगेशन में, सिंचन में ज्यादा निवेश नहीं किया है। पानी का संकट क्यों आया? आप देखिए कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना से चौथी पंचवर्षीय योजना तक ही हमने जल संसाधन के विकास में निवेश किया है, उसके बाद सरकार ने इस नीति को पूर्णतः तिलांजलि दी है। अगर आप पिछले 18 वर्षों के बजट का अवलोकन करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप प्रति वर्ष योजना आयोग से संचार व्यवस्था के लिए 16,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक के निवेश का आवंटन करते हैं और सिंचाई के लिए सिर्फ 300 या 500 करोड़ का प्रावधान करते हैं। पानी के लिए हम कितनी राशि रखते हैं? भारत सरकार का बजट लगभग 20,55,000 करोड़ रुपए का है, उसमें कुल 1200 करोड़ रुपए की घोषणा हम जल संसाधन के लिए करते हैं। पिछले वर्ष 1275 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ था और उसमें से 430 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें से 50 परसेंट बाढ़ नियंत्रण में चला जाता है। अगर इस गति से हम जल संसाधन के विकास की योजना बनाएंगे, तो भारत के जल संसाधन विकास को 2000 साल लगेंगे। पवार साहब अभी यहां नहीं हैं, पवार साहब महाराष्ट्र की बात कह रहे थे कि क्या स्थिति है, क्या नहीं, लेकिन सिंचन का सबसे

ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सिर्फ 18 परसेंट इलाका सिंचित क्षेत्र में आता है और बाकी सारा इलाका बारिश पर निर्भर है। वह जो 18 परसेंट एरिया है, यह शुगरकेन का एरिया है और महाराष्ट्र देश का सेकंड लार्जेस्ट शुगरकेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। सर, शुगरकेन को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए बाकी क्रॉप्स को पानी मिलता नहीं है। वहां पानी का गलत इस्तेमाल होता है, राजनीतिक दबाव होता है, शुगरकेन के लिए पानी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए बाकी क्रॉप्स मर जाती हैं।

सर, महाराष्ट्र के संबंध एक-दो कड़वी बातें मैं यहां रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र में पिछले दस वर्षों में सिंचाई के लिए 70,000 करोड़ की राशि खर्च की गई, लेकिन उस 70,000 करोड़ का कितना प्रतिशत सिंचन में लगाया गया और उसमें से कितना पैसा सरकारी लोगोंकी जेबों में गया और कितनी सिंचाई हुई, इसके बारे में अगर शरद पवार साहब जानकारी देते, तो सदन को भी अच्छी जानकारी होती। 70,000 करोड़ खर्च करने के बाद कुल कितनी भूमि सिंचित हुई? सिर्फ एक परसेंट। महाराष्ट्र की सिर्फ एक परसेंट भूमि 70,000 करोड़ खर्च करने के बाद करने के बाद सिंचित हुई है और अब यहां की सरकार कहती है कि जो योजनाएं हमने उस वक्त शुरू की थीं, 70,000 करोड़ की शुरुआत की थी ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र)ः सर, ये जो आंकड़े दे रहे हैं, वे ठीक नहीं हैं।

श्री संजय राउतः आंकड़े एकदम ठीक हैं। ...**(व्यवधान)**... नहीं, नहीं, आंकड़े ठीक हैं, आप ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no time. ...*(Interruptions)*... Sanjay *ji,* please conclude. ...*(Interruptions)*... Mr. Husain Dalwai, there is no time. What are you doing? Please sit down. ...*(Interruptions)*... Mr. Sanjay Raut, please conclude. *(Time bell rings)* आप समाप्त कीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. समाप्त कीजिए।

श्री संजय राउतः मैं समाप्त करता हूं, मुझे दो मिनट और बोलना है। सर, महाराष्ट्र की बात है।

श्री उपसभापति: ठीक है, सभी स्टेट्स एक समान हैं।

श्री संजय राउतः सर, देश में 40 परसेंट कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है और बाकी 60 परसेंट जो खेती है, वह पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। जब हम सिंचन की बात करते हैं, तो हमारे देश में पूरी सिंचाई भगवान भरोसे है। खास करके जो हम अकाल की बात करते हैं, लांग टर्म ड्राउट प्रीवेंट करने के लिए सरकार के पास आज तक कोई योजना नहीं है। जब ऐसी बात आती है तब हम चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने देखा है कि सरकार की तरफ से 5-6 जिलों में आपात योजना बनाने की कोशिश चल रही है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो सूखाग्रस्त इलाके आपने टारगेट किए हैं, वहां के किसानों को पैकेज देना चाहिए, वहां के किसानों को बिजली मुफ्त देनी चाहिए, वहां के किसानों को पानी मुफ्त देना चाहिए, यह हमारी मांग है। हमारी सरकार विदेश से ब्लैक मनी वापस लाने की जो कोशिश कर रही है, उस ब्लैक मनी को हम वापस लाएंगे, पैसा आ जाएगा, उसे किसानों पर खर्च करेंगे, इस तरह के विचार और सोच तो हम रख ही सकते हैं। इसके अलावा जो सूखा-ग्रस्त इलाके के किसान हैं, उनके बच्चे आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका कॉलेज छूट गया है, उनके लिए अगर हम कुछ पैकेज दे सकते हैं तो हमें उस बारे में जरूर सोचना चाहिए। यह बात सिर्फ राजनीति करने से नहीं होगी। बारिश कम है, लेकिन सरकार का दिल बड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की दरियादिली किसानों की मदद करेगी और पानी के संकट से हम निकल जाएंगे। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, all parties have exhausted their time. The category of 'Others' also has exhausted its time. Yet, I have five names. If they agree to speak in three minutes each, I am ready to call them.

SHRI SANJIV KUMAR (Jharkhand): Sir, I am the only speaker from my party.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are in the category of 'Others.' ...*(Interruptions)*... I will call you. ...*(Interruptions)*... Your are in the category of 'Others.' ...*(Interruptions)*... Your name is not in the list of party. ...*(Interruptions)*... I have told you that I am ready to call you, but you have to speak in three minutes only. ...*(Interruptions)*... If you agree to it, then I will call you. ...*(Interruptions)*...Then I will not call you. ...*(Interruptions)*... Then I cannot call you. In the category of 'Others,' you are the fifth speaker. ...*(Interruptions)*... You could have given your name earlier. ...*(Interruptions)*... Don't argue with me. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANJIV KUMAR : Sir, I come from Jharkhand. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Every State is equal for me. ...*(Interruptions)*... Don't argue with me. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Then I cannot call you. I will give you three minutes each. On that condition I am calling. ...*(Interruptions)*... I have not called you. ...*(Interruptions)*... Chaudhary Munavver Saleem, you have only three minutes. I am telling you, you cannot take even one minute more. ...*(Interruptions)*...

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश)**:** एक मिनट तो आप ही ले लेते हैं।

†[**چودھری منور سلیم** : ایک منٹ تو آپ ہی لے لیتے ہیں۔]

श्री उपसभापति: ठीक है।

चौधरी मुनव्वर सलीम: माननीय उपसभापति महोदय, भारतवर्ष में सूखे की स्थिति को लेकर प्रो. राम गोपाल यादव जी ने जिस चर्चा को आरंभ किया है, यह चर्चा समाज के अंतिम आदमी का दर्द है। बहुत से विद्वान वक्ताओं के बयानात् यहां हुए। प्रोफेसर साहब का खुद का जो बयान था, उसमें उन्होंने अपने आप में समस्या भी बताई और उसके समाधान भी बताए। काश, मंत्री जी उस बात को समझ सकते। माननीय उपसभापति महोदय, सूखा और पानी दोनों एक-दूसरे के दुश्मन हैं। मैं सोचता हूं कि देशवासियों को कहीं न कहीं हमने पानी की अहमियत समझाने में कमी की है। आज साठ साल के अंदर हम देशवासियों को पानी की अहमियत नहीं समझा पाए हैं। महोदय,पानी जब आसमान से बरसता है तो रहमत होता है, ज़मीन पर बहता है तो ज़िदगी होता है, शंकर जी की जटाओं से निकलता है तो गंगाजल होता है, इस्माइल अलैहसलाम की एड़ियों से निकलता है तो आबे ज़मज़म होता है। सारी दुनिया में पानी का अपना एक महत्व है। पानी हमारी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरा नेता डा. लोहिया ने बरसों पहले कहा था कि अगर अगला कोई विश्व स्तर का युद्ध होगा तो वह पानी के सवाल पर होगा। जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जो तालाब हैं, जो कुंएं हैं, अगर हम उनका जीर्णोद्धार कर सकें तो हम पानी का स्तर बढ़ा देंगे। अगर हम पानी का स्तर बढ़ा देंगे तो चालीस फीसदी वह खेती, जो सिंचाई पर निर्भर है और साठ फीसदी, जो आसमानी रहमत के ऊपर और आसमानी बारिश पर निर्भर है, उसका समाधान हो जाएगा। यह बात प्रो. साहब ने अपनी तकरीर में कही थी। महोदय,

†[Transliteration in Urdu Script].

यह बहुत बड़ा विषय है। मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले किसानों से करोड़ों रुपए प्रीमियम के नाम पर ले लिए जाते हैं, मध्य प्रदेश से करोड़ों रुपए आते हैं, बिगर स्टेट से करोड़ों रुपए आते हैं और किसानों को बीमे की रकम नहीं दी जाती। इस देश में तबला-वादकों को बीमे की रकम मिल जाती है, गायक कलाकारों को बीमे की रकम मिल जाती है, साइकिल वालों को बीमे की रकम मिल जाती है, कार वालों को बीमे की रकम मिल जाती है।

लेकिन किसान को बीमे की रकम नहीं मिलती और उससे बीमे का प्रीमियम वसूल लिया जाता है। मैं सोचता हूं कि आज माननीय कृषि मंत्री जी ऐलान करेंगे कि जिन किसानों से प्रीमियम ले लिया गया है, उन्हें बीमे की रकम दी जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। अभी ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन सूखा सिर पर खड़ा है। लोग खरीफ की फसल बो नहीं पाये हैं, ज़माना निकल गया, अब अगली फसल की तैयारी है। प्रो. राम गोपाल जी ने ठीक ही कहा था कि सैलाब से एक फसल बर्बाद होती है और सूखे से किसान की दो फसलें बर्बाद होती हैं। मैं सोचता हूं कि देश के कमजोर किसान के बारे में जो बहुसंख्यक हैं, कृषि मंत्री जी एक क्रांतिकारी फैसला करेंगे। वे उनको लोन में सुविधाएं देंगे, उनके ब्याज को माफ करेंगे और छोटे किसानों के कर्ज़ माफ करेंगे, ताकि किसान अपनी आगे की जिंदगी गुजार सकें। आपने मुझ जैसे कम समझ आदमी को इस विषय पर बोलने का वक्त दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

چودھری منوّر سلیم (اتّر پردیش) : مانئے اپ سبھاپتی مہودے، بھارت-ورش میں سوکھے کی حالت کو لے کر پورفیسر رام گوپال یادو جی نے جس چرچا کو شروع کیا ہے، وہ چرچا سماج کے آخری آدمی کا درد ہے۔ بہت سے ودوان وکتاؤں کے بیانات یہاں ہوئے۔ پروفیسر صاحب کا خود کا جو بیان تھا، اس میں انہوں نے اپنے آپ میں سمسیہ بھی بتائی اور اس کے سمادھان بھی بتائے۔ کاش، منتری جی اس بات کو سمجھ سکتے۔

مانئے اپ سبھا پتی مہودے، سوکھا اور پانی دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ دیش واسیوں کو کہیں نہ کہیں ہم نے پانی کی اہمیت سمجھانے میں کمی کی ہے۔ آج ساٹھ سال کے اندر ہم دیش-واسیوں کی پانی کی اہمیت نہیں سمجھا پائے ہیں۔ مہودے، پانی جب آسمان سے برستا ہے رحمت ہوتا ہے، زمین پر بہتا ہے تو زندگی ہوتا ہے، شنکر جی کی جٹاؤں سے نکلتا ہے، تو گنگاجل ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلتا ہے تو آب زمزم ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں پانی کا اپنا ایک مہتّو ہے۔ پانی ہماری سرکار کی پراتھمکتا ہونی چاہئے۔ میرے نیتا ڈاکٹر لوہیا نے برسوں پہلے کہا تھا کہ اگر اگلا کوئی وشو-استر کا یدھ ہوگا تو وہ پانی کے سوال پر ہوگا۔ جو ہماری پراچین دھروہر ہے، جو تالاب ہیں، جو کنویں ہیں، اگر ہم ان کا جیرنودھار کر سکیں تو ہم پانی کا استر بڑھا دیں گے۔ اگر ہم پانی کا استر بڑھا دیں گے تو چالیس فیصد وہ کھیتی، جو سینچائی پر نربھر ہے اور ساٹھ فیصدی، جو اسمانی رحمت کے اوپر اور آسمانی بارش پر نربھر ہے، اس کا سمادھان ہو جائے گا۔ یہ بات پروفیسر صاحب نے اپنی تقریر میں کہی تھی۔

†[Transliteration in Urdu Script].

مہودے، یہ بہت بڑا وشئے ہے۔ میں سنکشیپ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کسانوں سے کروڑوں روپے پریمئم کے نام پر لے لئے جاتے ہیں، مدھیہ پردیش سے کروڑوں روپے آتے ہیں، بگر اسٹیٹ سے کروڑوں روپے آتے ہیں اور کسانوں کو بیمے کی رقم نہیں دی جاتی۔ اس دیش میں طبلہ وادکوں کو بیمے کی رقم مل جاتی ہے، گائک کلاکاروں کو بیمے کی رقم مل جاتی ہے، سائیکل والوں کو بیمے کی رقم مل جاتی ہے، کار والوں کو بیمے کی رقم مل جاتی ہے۔

لیکن کسانوں کو بیمے کی رقم نہیں ملتی اور ان سے بیمے کا پریمئم وصول لیا جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ آج مانئے کرشی منتری جی ایک اعلان کریں گے کہ جن کسانوں سے پریمئم لے لیا گیا ہے، انہیں بیمے کی رقم دی جائے، جس سے کسانوں کو راحت مل سکے۔ ابھی اعلان بھلے ہی نہیں ہوا ہو، لیکن سوکھا سر پر کھڑا ہے۔ لوگ خریف کی فصل بو نہیں پائے ہیں، زمانہ نکل گیا، اب اگلی فصل کی تیاری ہے۔ پروفیسر رام گوپال جی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ سیلاب سے ایک فصل برباد ہوتی ہے اور سوکھے سے کسان کی دو فصلیں برباد ہوتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ دیش کے کمزور کسانوں کے بارے میں جو بھوسنخیک ہیں، کرشی منتری جی ایک کرانتی-کاری فیصلہ کریں گے۔ وہ ان کو لون میں سویدھائیں دیں گے، ان کے بیاز کو معاف کریں گے اور چھوٹے کسانوں کے قرض معاف کریں گے، تاکہ کسان اپنی آگے کی زندگی گزار سکیں۔ آپ نے مجھ جیسے کم سمجھ آدمی کو اس وشئے پر بولنے کا وقت دیا اس کے لئے آپ کا دھنیواد۔

(ختم شد)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, Shrimati Rajani Patil. You have only three minutes.

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र): सर, पूरे सदन में सिर्फ एक ही महिला किसानों की तरफ से बोल रही हैं, तो आप दो मिनट का समय बढ़ा दीजिए।

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं। मैंने तीन मिनट का समय अनाउंस किया है।

श्रीमती रजनी पाटिल: सर, देश के विभिन्न भागों में अल्पवृष्टि, सुखे की विद्यमान परिस्थिति और किसानों की दुदर्शा पर नियम 176 के अधीन चर्चा कराने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। साधारणत: 7 जून से 7 जुलाई तक एक बारिश काल रहता है और खेतों में बुवाई का काम 100 फीसदी पूरा होता है। अभी तक सिर्फ 27 फीसदी बुवाई हो पाई है और अकाल के बादल मंडरा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में और खासकर महाराष्ट्र में अकाल की परिस्थिति पैदा हो गई है। सर, महाराष्ट्र में तो करीब दो-तीन साल से कभी अकाल पड़ा है, तो कभी अतिवृष्टि हुई है या कभी उसे ओले का सामना

करना पड़ा है, जिसकी वजह से किसानों की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है। अनाज और पानी दोनों की समस्या इस देश में पहले हुआ करती थी, जब 1972 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और अनाज की समस्या हो गई थी। हमें याद है, उस समय हम छोटे थे, तो Milo की रोटियां हमें खाने के लिए मिलती थीं और अमेरिका से Milo आया करता था और हम उसकी रोटियां खाते थे, लेकिन किसानों के प्रयत्नों से और कांग्रेस सरकार की गत कई वर्षों की कृषि नीतियों की वजह से दो कामों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है—एक तो अनाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और दूसरा मनरेगा, जो यूपीए-वन और यूपीए-टू ने शुरू किया है, उसमें गरीबों और किसानों को काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर भी, हमारे सामने दो प्रश्न उपस्थित होते हैं— एक चारे का प्रश्न और एक पीने के पानी का प्रश्न। सर, पानी के स्त्रोत जहां-जहां भी मिल रहे हैं, वहां पर फॉडर सीड देकर, फॉडर बैंक बनाने की व्यवस्था की जाए, इसके लिए मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करती हूं। फॉडर बैंक इसलिए बनाया जाए क्योंकि आने वाले काल में फॉडर की कमी होगी और उस समय जहां पर पानी के स्त्रोत हैं, वहां पर फॉडर सीड देकर अगर हमने फॉडर बनाया, तो जानवरों के लिए फॉडर कम नहीं पड़ेगा और इससे हमारा पशुधन भी बच जाएगा। दूसरी बात, जब मनरेगा का जिक्र हुआ है, तो मैं बताना चाहती हूं कि जो मनुष्य बल है, जो हम लोगों के हाथ को काम देते हैं, मनरेगा के तहत किसानों को काम देते हैं। अगर किसी भी प्राईवेट व्यक्ति ने या किसान ने अपने खेतों में सिंचाई के लिए वाटर सप्लाई या वाटर प्रिज़रवेशन के लिए कोई स्कीम दी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, जिसमें खुद किसान भी अपने हिस्से का योगदान दे सकता है। किसान को मदद देने की आवश्यकता है। अगर उसमें आप नियम डालेंगे कि वह सिर्फ दलित होना चाहिए, तो यह ठीक नहीं है। किसान-किसान होता है, इसलिए इस स्थिति में कोई भी फ़र्क नहीं करते हुए किसानों की मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए।

सर, बारिश से प्रभावित जो हमारे क्षेत्र हैं, उनके लिए कार्य-योजना बनाने की जरूरत है। उनके लिए खेत में तालाब बनाना आवश्यक है। दूसरी बात, मैं कृषि मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगी कि सूक्ष्म सिंचाई की ज्यादा जरूरत है, जिसको हम drip irrigation बोलते हैं। सर, महाराष्ट्र के बारे में बोला जाए, तो 250 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र को drip irrigation के लिए दिए जाते हैं, जबकि हमारी मांग एक हजार करोड़ रुपये की है। इसके लिए कृषि मंत्रालय को आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। सर, दो-तीन दिन से प्याज की महंगाई पर भी चर्चा हुई, लेकिन मैं यहां पर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि हमारी स्टेट में 40 लाख हैक्टेयर भूमि में से 20 लाख हैक्टेयर में अतिवृष्टि का खतरा हुआ और 20 लाख हैक्टेयर में ओले की वजह से हमारा नुकसान हो गया। **...(समय की घंटी)...** जिसमें 5 लाख हैक्टेयर प्याज था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

श्रीमती रजनी पाटिल : ओले की वजह से हमारा नुकसान हो गया जिसमें पांच लाख हेक्टेयर प्याज था। सर, एसेंशिएल कमोडिटीज एक्ट में प्याज को सम्मिलत करके एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: ओ.के. धन्यवाद।

श्रीमती रजनी पाटिल : सर, सरकार ने स्टोरेज के लिए जो बंधन रखा है, **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now please conclude. Please conclude.

श्रीमती रजनी पाटिलः उसके लिए अपने खेतों में जो स्टोरेज करने वाले किसान हैं, उनको भी दिक्कत हो जाएगी। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: ठीक है, ठीक है, बस।

श्रीमती रजनी पाटिलः मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो तीन सौ यू.एस.डी से **...(व्यवधान)...** पांच सौ यू.एस.डी करते हैं, उसके लिए किसानों को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: बस, बस। ओ.के.।

श्रीमती रजनी पाटिलः सर, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से एक ही सवाल पूछना चाहती हूं कि पूरी दुनिया में अगर फ्री ट्रेड की भाषा चल रहीं है, तो फिर किसानों के लिए ट्रेड़िग की पाबंदी क्यों लगाते हैं? **...(समय की घंटी)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you. That's all. Okay, please. धन्यवाद, धन्यवाद।

श्रीमती रजनी पाटिलः मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now please conclude. Please conclude.

श्रीमती रजनी पाटिलः वहां पर ज्यादातर गन्ना तोड़ने का काम करने वाले लोग रहते हैं। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, please. You made your point. Okay,

श्रीमती रजनी पाटिलः वे पूरे महाराष्ट्र से कर्णाटक जाते हैं, गोवा जाते हैं, **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: My dear sister, please. Okay, please.

श्रीमती रजनी पाटिलः हमें उन लोगों के लिए कोई स्पेशल स्किल डिवेलपमेंट मिशन **...(व्यवधान)...** शुगर फैक्ट्रीज के लिए करना होगा, उन लेबर्स के लिए करना होगा। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, please. please, please., आप बैठिए। धन्यवाद बैठिए।

श्रीमती रजनी पाटिलः सर, मैं एक इम्पॉर्टेन्ट बात कह रही हूं। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: ठीक है, Very important.

श्रीमती रजनी पाटिलः सर, मैं पूरे सदन में अकेली ऐसी महिला हूं, जो किसानों के संबंध में बोल रही हूं। **...(व्यवधान)...**

SHRI SHARAD PAWAR: Mr. Deputy Chairman, Sir, the hon. Lady Member comes from Beed district which is facing a tremendous drought. Please allow her.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am obliging you because of Shri Sharad Pawar's request.

श्रीमती रजनी पाटिलः सर, पवार साहब पूरे हिन्दुस्तान की परिस्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे हरेक गांव और डिस्ट्रिक्ट के बीच की स्थिति को वे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उनको

मालूम है कि इसके लिए बोलना कितना इम्पॉर्टेन्ट है। मेरा यह कहना है कि एक स्किल डिवेलपमेंट मिशन यहां पर होना चाहिए। सर, शुगर फैक्ट्रीज़ में जो हाल में दस प्रतिशत ethanol ब्लेंडिंग करने का निर्णय लिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसकी तामीली जल्दी होनी चाहिए। सर, कोजेनरेशन प्लांट जो है, वह कोजेनरेशन प्लांट शुगर फैक्ट्री को बढ़ाकर, उसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाना चाहिए, जिससे बिजली का संकट कम हो जाए।

सर, आज भी पॉम तेल और बाकी सब तेलों के लिए हम अन्य देशों पर निर्भर हैं। हमें उनसे इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसलिए ऑयल सीड्ज़ के लिए हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी, जिसके कारण हमारे देश में ऑयल का उत्पादन ज्यादा बढ़ सकता है।

सर, एक किसान परिवार से होते हुए, मैं लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं, जैसा कि पवार साहब ने अभी बताया, **...(समय की घंटी)...** महाराष्ट्र के मीडियम प्रोजेक्ट्स और मॉइनर व मेजर प्रोजेक्ट्स **...(व्यवधान)...** से भी कम पानी उपलब्ध है और उसके अभी पानी **...(व्यवधान)...** हमारे मुख्य मंत्री जी ने शुरू कर दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have limitations. The Minister has to reply and go to the Cabinet meeting. That is the problem.

श्रीमती रजनी पाटिलः हमारे क्षेत्र के लिए एक लांग टर्म सॉल्यूशन करना चाहिए। किसान के परिवार की लड़की होने के कारण मैं कृषि मंत्री जी दरख्वास्त करूंगी, जैसे पवार साहब के कार्यकाल में यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में डा. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हमें 73 हजार करोड़ रुपए की राहत दी गई थी, इसी तरह से एक अच्छी राहत किसानों को दी जाए, यही दरख्वास्त मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहती हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next Shri Sanjiv Kumar.

श्री संजीव कुमार: सर, मैं एक छोटे राज्य से हूं और छोटे **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sanjiv Kumar, you have less than four minutes.

श्री संजीव कुमार: सर, जो प्रॉब्लम है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं और प्रत्येक बार यही होता है कि मैं नोटिस देता हूं और सबसे लास्ट में नाम आता है तथा मुझे पहले ही वॉर्न कर दिया जाता है कि आपको **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You could have given your name first. It is your fault. ...*(Interruptions)*... For your fault don't blame us. You gave your name at the last. Now, how are you saying like this? No, you can't blame like that.

SHRI SANJIV KUMAR: The moment I entered the House I gave my name.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Before that other Members gave their names. You should know that. ...*(Interruptions)*... Okay, you speak. Speak only for less than four minutes.

श्री संजीव कुमार: सर, मुझसे पहले प्रो. राम गोपाल यादव, श्री जयराम रमेश और श्री शरद पवार जी ने अपने विचार रखे हैं। यह नेशनल पर्सपेक्टिव में था और मैं उनसे सहमत हूं। मैं झारखंड से

[श्री संजीव कुमार]

आता हूं और मैं एक किसान का बेटा हूं। मैं जानता हूं कि जब बारिश नहीं होती हैं, तो किसानों पर क्या बीतती है। सर, जो झारखंड को जानने वाले लोग हैं,वे जानते हैं कि मुख्यतः झारखंड में धान की खेती होती है। अभी तक की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार अभी धान की बुवाई नहीं हुई है। धान के साथ-साथ मकई की भी खेती होती है, जिसकी अभी बुवाई नहीं हुई है। झारखंड ही ऐसा स्टेट है,शायद इसमें उड़ीसा और एक-दो राज्य और होंगे, कोई भी ऐसा हाउसहोल्ड नहीं होगा, जहां पर इनके नौकर और दाई न हों। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि झारखंड कोयला, लोहा, तांबा और बॉक्साइट के चलते बहुत धनी राज्य है। शरद पवार साहब की तरफ से जो सुझाव रखे गए हैं कि सूखे से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएं, उन पर विचार करना होगा। हमें झारखंड के लिए कुछ और विशेष बातें सोचनी होंगी। झारखंड में जो पलायन अर्थात् डिसप्लेसमेंट होता है, उसको रोकने के लिए झारखंड के लिए जितने भी कानून बने हैं,उन पर ध्यान देना होगा। जो "लैंड एक्विजिशन रीहैबिलिटेशन एंड डिसप्लेसमेंट ऐक्ट, 2014" बना है, उस पर मैंने पार्लियामेंट में बताया था कि जो "माइन्स ऐक्ट है", "कोल बियरिंग एरियाज़ ऐक्ट" एंड "डीवीसी ऐक्ट" है, इनको इसमें एग्जम्प्ट किया गया है, इसलिए उसको स्क्रैप करना चाहिए। झारखंड के किसानों का जो लैंड एक्वायर किया जाए, उनको 1884 और 1945 के रेट से नहीं, बल्कि 2014 के रेट से उसका पैसा मिलना चाहिए।

सर, चुनाव के समय स्पेशल स्टेटस की बात कही गई थी। यह कहा गया था कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्ज़ा दिया जाएगा। मैं आज झारखंड की तरफ से सरकार से यह डिमांड करता हूं कि यह जो सूखे की स्थिति आई है, उससे निपटने के लिए आप अपना वादा पूरा कीजिए और झारखंड को विशेष राज्य का दर्ज़ा दीजिए।

मैं दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि झारखंड एक तरफ तो सुखाड़ की स्थिति से निपट रहा है और दूसरी तरफ झारखंड के साथ बराबर अन्याय हुआ है। जब नये राज्य बन रहे थे – बिहार से झारखंड, यू.पी. से उत्तारंचल और एम.पी. से छत्तीसगढ़ राज्य बने थे और पेंशन लाइबिलिटी फिक्स की जा रही थी, तो सिर्फ झारखंड के ही केस में पापुलेशन का रेश्यो नही बनाया गया, उसके लिए एम्पलॉयी का रेश्यो बनाया गया था। मैं यह डिमांड करता हूं कि जो अनलॉफुल लॉ इनेक्ट किया गया है, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि जब भी कोई नया स्टेट क्रिएट हुआ है, तो पेंशन लाइबिलिटी फिक्स करने के लिए आज तक पापुलेशन को आधार बनाया गया है, लेकिन सिर्फ झारखंड के केस में यह अन्याय हुआ है। इसलिए मैं नई सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि आपने झारखंड में जाकर जो बड़े-बड़े वादे किए थे, उनको पूरा करने के लिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पेंशन लाइबिलिटी...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: समाप्त कीजिए।

श्री संजीव कुमार: इस ऐक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत है।

श्री उपसभापति: श्री संजीव कुमार जी समाप्त कीजिए।

श्री संजीव कुमार: उपसभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आप भी झारखंड का विशेष ख़याल रखेंगे।

श्री उपसभापति: बहुत अच्छा, आपने चार मिनट में खत्म कर दिया। श्री हुसैन दलवई।

श्री हुसैन दलवई: उपसभापति जी, आईएमडी का ऐसा कहना है कि अगर 10 परसेंट से कम बारिश हो तो इसका मतलब यह समझना चाहिए कि वहां सूखा है। आज स्थिति है, उसमें उनका कहना है कि यह जो पूरा सीज़न है, उसमें 15 परसेंट से भी कम बारिश होने की संभावना है। यह एक बड़ी दिक्कत है, संकट है। इसका मतलब है कि इस देश में 81 परसेंट सूखा हो जाएगा और देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी तरह से सोचना बहुत जरूरी है। जब शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे, तो उस समय कृषि का उत्पादन साढ़े चार परसेंट तक बढ़ गया था और बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई थी। पहली बार इतना अच्छा हो गया था, लेकिन अभी हमारे सामने यह संकट पैदा हो गया है। मुझे मालूम नहीं है कि इस साल क्या आफत आएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने कहा है कि इस देश में 85 बड़े जलाशय हैं और उनमें से 52 जलाशय पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हैं। उनमें से भी महाराष्ट्र मे सबसे ज्यादा जलाशय हैं। महाराष्ट्र में अभी की स्थिति यह है कि वहां केवल 26 परसेंट बारिश हो रही है। मेरा कहना यह है कि पानी बचाओ मुहिम शुरू करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को अगुवाई करना बहुत जरूरी है। हमें तालाबों ओर कुओं के स्त्रोत बढाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए।

मनरेगा, महाराष्ट्र में एक रोजगार निर्माण योजना थी, जिसका उपयोग फलों के बाग बढ़ाने के लिए किया गया था। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। यह भी करना चाहिए और इसका उपयोग सूखा दूर करने के लिए भी जितना हो सके,उतना करना चाहिए। फिर किसानों को अभी जो कर्ज दिया जाता है, मेरे ख्याल से वह कर्ज बिना ब्याज के देना चाहिए और उसे माफ भी करना चाहिए। इसका कारण यह है कि बड़ी इंडस्ट्री का कर्ज इस तरह से माफ किया जाता है। किसान बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज को नहीं डुबाता है, जबकि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स कर्ज डुबाने का काम करते हैं। इस बात को ध्यान में रख कर उनको इस तरह की राहत देनी चाहिए।

समंदर में जो पानी जाता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं कोयना नगर से आया हूं। वहां कोयना बांध का पूरा का पूरा पानी समंदर में जाता है। कहीं-न-कहीं उस पानी को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। पानी का इस्तेमाल बार-बार होना चाहिए, इसलिए रिसाइक्लिंग ऑफ वाटर की स्कीम बनाना बहुत जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन के बारे में मेरी बहन ने कहा। जब बड़े पैमाने पर ड्रिप इरिगेशन होगा, तो मेरे ख्याल से सूखा बहुत कम हो जाएगा। महाराष्ट्र की हालत ऐसी है कि जहां बड़े पैमाने पर गन्ना होता है, वहीं बाजू के ताल्लुक में सूखा होता है। अगर कम पानी में गन्ना होगा, तो मेरे ख्याल से वहां का अकाल दूर हो जाएगा।

कृषि विश्वविद्यालय के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। वहां बड़े पैमाने पर रिसर्च होती है। मैं कोंकण से आता हूं। कोंकण कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च की है। वह रिसर्च लोगो तक जाए, इसके लिए एक्सटेंशन सर्विस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए रिसर्च के लिए ज्यादा राशि देना भी बहुत जरूरी है। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री हुसैन दलवई: मैं जल्द खत्म कर रहा हूं। मैं यह कहूंगा कि आज महाराष्ट्र की स्थिति सबसे बुरी है। वहां तीन बार सूखा पड़ गया, ओले गिर गए और इसके बाद ज्यादा बारिश्या हो गई। इससे महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा नुकसान हो गया। ...**(समय की घंटी)**... इसलिए महाराष्ट्र के लिए ज्यादा राशि देना बहुत जरूरी है हर साल अकाल के ऊपर चर्चा करने के बजाय इसके कारण को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए। जय हिन्द, जय भारत।

6.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A.V. Swamy. Not present. Now, the Minister is to reply.

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): उपसभापति महोदय, मैं आज की इस चर्चा में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए सभी सम्माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं। सभी सदस्यों के द्वारा किसान की जो चिन्ता की गई, मैं इसकी भी प्रशंसा करता हूं। 25 से ज्यादा लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया है। आदरणीय शरद पवार जी के बताने के बाद न सरकार की ओर से कुछ बताने की जरूरत है, न विपक्ष की ओर से कुछ बताने की जरूरत है। जिस प्रकार से उन्होंने बातें रखी हैं और हम सबको भी पता है कि इस साल के अप्रैल में ही जो पूर्वानुमान था, उसमें 95 प्रतिशत वर्षा की सम्भावना बताई गई थी। मुझे कृषि मंत्री के नाते 26 मई को अवसर मिला था और 9 मई के पूर्वानुमान में बताया गया था कि 93 प्रतिशत वर्षा होने की सम्भावना है, तो हमने एक बैठक की थी और प्रेस को भी बताया था। उसी में 500 जिलों के लिए जो आकस्मिक प्लान है, मैंने इसकी जानकारी दी थी कि 500 जिलों के लिए यह तैयार हो चुका है। त्यागी जी, 500 जिलों में सूखा पड़ेगा, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने बताया कि मैंने कहा कि 500 जिलों में सूखा पड़ेगा। हमारे एक और मित्र ने भी इस बात की चर्चा की है कि कृषि मंत्री जी ने बताया कि बहुत सारे जिलों में इस बार सूखा पड़ेगा।

त्यागी जी, सूखे की घोषणा मैं नहीं कर सकता। यह बात उसमें नहीं लिखी हुई है, आप उसे ठीक से पढ़िए। सूखा किस क्षेत्र में होगा, किस जिले में होगा, इसकी घोषणा भारत सरकार या कृषि मंत्री नहीं किया करते हैं, इसकी घोषणा जिला एवं क्षेत्रवार राज्यों के द्वारा होती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र जिस राज्य के अंतर्गत आता है, वह राज्य यह कहता है कि हम अपने क्षेत्र में सूखे की घोषणा करते हैं। उसके बाद आगे की सहायता के जो प्रावधान हैं, जो नियम हैं, उनके आधार पर हम कार्यवाही किया करते हैं।

पहले यह बताया गया था कि जून महीने में 93% वर्षा होगी, फिर यह बताया गया कि 7 जुलाई के बाद अच्छी वर्षा होगी। हां, प्रेस ने इसमें एक काम जरूर किया है कि उसमें अलग-अलग स्थानों के लिए वर्षा के अलग-अलग आंकड़े बताए गए हैं कि उत्तर-पश्चिम भारत में 85%, मध्य भारत में 94%, दक्षिण प्रायद्वीप में 93% और पूर्वोत्तर भारत में 99% वर्षा का अनुमान है।

उत्तर-पश्चिम भारत में वर्षा के आंकड़े 85% हैं, यानी वहां कम वर्षा का अनुमान है, लेकिन इसके साथ मौसम विभाग ने यह भी बताया था कि 7 जुलाई के बाद अच्छी वर्षा होगी। अब मीडिया का कमाल तो आप और हम जानते ही हैं। उत्तर-पश्चिम भारत में कम वर्षा होगी, इस पर तो मीडिया में काफी चर्चा हुई, लेकिन 7 जुलाई के बाद अच्छी वर्षा होगी, इसका जिक्र चर्चा में नहीं किया गया। अखबार ने भी उसी मीडिया से न्यूज लेकर छापी थी।

500 जिलों के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार की गई है। यह योजना, हम मंत्री बने, उतने ही दिनों में तैयार हो गई हो, ऐसी बात नहीं है, पिछली सरकार यह काम पहले से ही कर रही थी। सूखे का जो मामला है, यह किसी पार्टी विशेष का मामला नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि अधिकतर सदस्यों ने, लगभग सभी सदस्यों ने पार्टी लाइन से अलग हट कर बात कही है। अगर हमारे एक माननीय सदस्या को छोड़ दिया जाए, तो किसी ने भी इस पर राजनीतिक आधार पर चर्चा नहीं की है। मौसम विभाग यह बात कहता है कि अब जुलाई में अच्छी वर्षा की संभावना है।

हम भी गांव में रहते हैं। जून से वहां बुआई शुरू होती है, यह बात ठीक है। लेकिन बचपन से हम खेतों में यह देखते आए हैं कि क्लाइमेट चेंज के बावजूद भी यदि जुलाई में अच्छी वर्षा हो जाती है, तो उसकी भरपाई हो जाती है। यह बात ठीक है कि अभी जो आंकड़े आए हैं, उनके मुताबिक मानसून में देरी और उसकी धीमी चाल के कारण धान, तिलहन, दलहन और कपास की फसलों की बुआई में देरी हो सकती है, किन्तु खरीफ की बुआई के सम्बन्ध में मानसून की आगे की जो प्रगति है, वह मददगार सिद्ध हो सकती है।

सम्माननीय शरद पवार जी ने कहा कि मानसून का जो ऐलान किया जाता है, हमें उसी के सहारे आगे चलना चाहिए, उस पर अविश्वास करके हम आगे आने वाले भविष्य का सही निर्माण नहीं कर सकते हैं। मौसम विभाग जो आंकड़े देता है, उसी के आधार पर हम आगे चलते हैं। उनके, द्वारा दिए गए जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार भी अगर जुलाई में अच्छी वर्षा होती है, तो सूखे की नौबत नहीं आएगी। किसान को बिल्कुल निर्भीक हो कर के रहने की जरूरत है, साथ ही हम लोग भी भयमुक्त रह कर ही इसका मुकाबला कर सकते हैं।

अगर फिर भी पूरी वर्षा नहीं होती है, ऐसी परिस्थिति में **...(व्यवधान)...** हमें क्या करना है, यही बात मैं बताने जा रहा हूं, आपको सुनने का धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। 9 जून के बाद 500 जिलों के लिए आकस्मिक प्लान बनाए गए थे। लगभग 550 ऐसे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनके लिए आकस्मिक प्लान तैयार किए गए हैं। ये आकस्मिक प्लान दो साल से बन रहे हैं, पिछली सरकार भी इनको बनाने में लगी हुई थी। इस आकस्मिक प्लान में सिर्फ सूखे की योजना ही नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखिए। यदि रूरल एरिया में आकस्मिक प्लान के अंतर्गत 550 जिले हैं,उनमें से किन्हीं जिलों में बाढ़ भी आने वाली है। दोनों तरह के जिलों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्लान बनाए जाते हैं।

सूखे की घोषणा केन्द्र सरकार नहीं कर सकती है, उसकी घोषणा राज्यों के द्वारा होती है। इस घोषणा के पहले ही राज्यों को उचित सलाह दी गई, जिसके लिए यहां से जाकर हमारे पदाधिकारियों ने राज्यों के साथ बैठक की। लगभग 12 राज्यों के अन्दर हमारे पदाधिकारी गए और वहां जाकर उन्होंने बैठकें कीं। साथ ही 17-18 जून को दिल्ली में सभी राज्यों के अधिकारियों को बुलाकर भी इस पर बैठक की गई कि आगे हमें क्या-क्या करना है। एक तरफ इन सभी राज्यों में जाकर बैठकें हुईं और दूसरी तरफ उनके पदाधिकारियों को यहां बुला कर बैठक करवाई गई। इस प्रकार पहले ही इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारी तैयारी इतनी है कि जिस स्पीड से सूखा आएगा,उससे डेढ़ गुना ज्यादा स्पीड से हमारी योजना के माध्यम से उसका शमन करने का कार्य किया जाएगा। बहुत सारे सवाल उठे हैं। अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग भी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि उनकी थोड़ी चर्चा करूं। सरकार सूखे से आने वाली आपदा का सामना करने में बिल्कुल सक्षम है। हम न सिर्फ उस चुनौती का सामना करेंगे, बल्कि सबके सहयोग से उस पर विजय भी प्राप्त करेंगे। सरकार का मतलब सिर्फ भारत सरकार नहीं, बल्कि राज्यों की सरकारें भी हैं। दोनों ने मिल कर 2009 का सामना किया है। इसके पहले भी जो संकट आए हैं, उनका सामना किया है तथा इस बार और तेज़ी से हम उसका सामना करेंगे।

सम्माननीय राम गोपाल जी ने दीर्घकालीन उपायों की चर्चा की थी। अब वास्तव में दीर्घकालीन उपाय होने चाहिए, क्योंकि सूखे की आपदा हो या कोई भी अन्य आपदा हो, वह कह कर नहीं आती है। वह तो किसी भी समय आ सकती है। इसके लिए पिछली सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाईं। आगे की सरकार भी इसको बहुत गति देने वाली है। हम सब को यह विचार करना है कि यदि किसी राज्य को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत एक साल के अन्दर 800 करोड़ रुपए गए हैं, तो वह 400

[श्री राधा मोहन सिंह]

करोड़ रुपए लौटाता है। किसी खास इलाके में 2009 में अगर 1000 करोड़ रुपये का पैकेज जाता है तो वह 150 करोड़ रुपये ही खर्च करता है। मतलब, इसके लिए राज्य और केन्द्र सरकार दोनों को मिलकर ठीक से मॉनिटरिंग करनी है। प्लानिंग तो बनी हुई है, लेकिन सवाल पैसे और प्लानिंग से ज्यादा बने हुए प्लान के क्रियान्वयन का है और मैं समझता हूं कि उसमें तेज़ी लाना दीर्घकालीन समस्याओं के समाधान का सबसे बड़ा उपाय है।

मनरेगा की चर्चा हो रही थी। मैंने 9-10 जून को राज्यों को जो पत्र भेजा है, जो पी.आई.बी. ने दिया है, उसमें भी हमने सुझाव दिया है कि मनरेगा के लोगों को किस प्रकार से सूखे का सामना करने में लगाना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को 15.05.2014 और 16.06.2014 को दो-दो पत्र दिए हैं कि सूखा शमन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के धन का उपयोग करने के लिए एक सलाह जारी की गयी है। अब इसके बावजूद भी अगर किसी को इसके सम्बन्ध में भ्रम होता है, तो यह उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। देश में इस बारे में भ्रम नहीं है और सरकार में भी इस बारे में भ्रम नहीं है। मैं सब लोगों को आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि सरकार ने दो-दो बार ऐसा पत्र भेजा है।

चारे के सम्बन्ध में बहुत चर्चा हुई। हमारे पास आंकड़े आए हैं कि पजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह सम्भावना है कि हम अतिरिक्त चारे का भी उत्पादन कर सकते हैं। हमारे देश में कृषि क्षेत्र में काफी काम हुआ है। जब हम कहते हैं कि जून में धान बोना चाहिए, परन्तु सूखा पड़ गया, अब तो बड़ी दिक्कत होगी,लेकिन एक समय था कि 160 दिनों में तैयार होने वाले धान का बीज भी हमारे पास था, लेकिन अब तो हमारे पास ऐसा बीज है कि यह 120 दिनों में भी तैयार होगा। तो उसी प्रकार से, चारे के सम्बन्ध में एक तो हमारा जो आकलन रहा है, सप्ताह में एक दिन उसकी मॉनिटरिंग भी हम कर रहे हैं। उसका जो शॉर्ट ड्यूरेशन सीड है, वह भी हमारे पास तैयार है। इसके साथ ही, हमारे यहां न सिर्फ चारा बल्कि अगर अभी वह स्थिति आई तो धान, दलहन, तिलहन भी कम अवधि में पैदा हो सकता है। बागवानी के मामले में भी हमने एक योजना तैयार की है कि अगर किसी की बागवानी सूखती है तो फिर वह कैसे सरवाइव करे हम उसके लिए भी अलग से क्या कर सकते हैं। हमने पशुओं के लिए दवाई और टीकाकरण की भी समीक्षा की है। अगर वैसी स्थिति अभी आती है तो उसका पर्याप्त भंडारण हमारे पास है।

पेयजल के सम्बन्ध में चर्चा हुई है। पेयजल के लिए हमने जिलावार आकस्मिक योजना की तैयारी भी की है, राज्य सरकारों के साथ बैठ कर। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 15 प्रतिशत राशि सभी राज्यों को आवंटित की गई है, जिससे यदि कहीं हैंड पम्प बन्द है या वह अधूरा है, चालू नहीं है, तो उसका रख-रखाव हो। आप सब को जानकर यह जरूर खुशी होगी कि सभी राज्यों के पास जो आपदा रिलीफ फंड है, उसके मद में भी अच्छी राशि मौजूद है। मैं उसका विवरण भी भेजूंगा, जिसमें 3 और 1 का अनुपात है और यदि कोई विशेष राज्य है तो वहां 9 और 1 का अनुपात है। इसी तरह से बिजली का भी संकट हो सकता है, उसके लिए भी हमने बिजली मंत्री के साथ बैठ कर, उनके अधिकारियों के साथ बैठ कर योजना बनाई है और उसका क्षेत्रवार आकलन किया है। विद्युत मंत्रालय ने कमजोर मानसून की स्थिति में उत्तरी क्षेत्र के लिए चार सौ मेगावाट तथा गंभीर सूखे के मामले में एक हजार मेगावाट की एक शमन योजना तैयार की है और दक्षिणी क्षेत्र में बिजली उत्पादन तीन हजार मेगावाट से बढ़ाने की शमन योजना तैयार कर दी है। इसलिए इसकी भी कमी नहीं होगी।

श्री भूपिंदर सिंह: पूर्वी भारत के लिए आपने क्या व्यवस्था की है?

श्री राधा मोहन सिंह: उत्तरी क्षेत्र में ही वह पूरा इलाका आ जाएगा। इसमें और भी कई प्रकार की बातें आई हैं। त्यागी जी ने चीनी मिलों की चर्चा की है। यह मेरा सीधा विषय नहीं हैं, लेकिन मैं वहां था। देखिए, जैसे भारत सरकार यहां से दाम तय करती है कि गन्ने की कीमत 210 प्रति क्विंटल है, अब यदि वाह-वाही लूटने के लिए, लोक-लुभावन नारे के लिए कोई राज्य सरकार कहती है कि हम गन्ने का मूल्य 260 रुपए प्रति क्विंटल देंगे या ढ़ाई सौ रुपए प्रति क्विंटल देंगे, तो उसका असर तो पड़ता है और आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में आठ हजार करोड़ रुपए किसानों के बकाया हैं। सरकार ने जो तय किया है, मैं समझता हूं कि पहले भी इसी प्रकार की योजना चलती रही होगी। ये जो पैसे मिल रहे है, वे मिल मालिकों को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि ये पैसे किसान के खाते में जाएंगे। इसमें इस तरह की कंडीशन है, इस तरह से इसमें किसान की चिंता की गई है, मिल मालिक की चिंता नहीं की गई है। निश्चित रूप से इसको आप ध्यान में रखिए। जो गन्ना उत्पादक किसान हैं, उनकी क्या हालत है? कुल ग्यारह हजार करोड़ रुपए में से अकेले उत्तर प्रदेश में किसानों के आठ हजार करोड़ रुपए बकाया हैं, बाकी तीन हजार करोड़ रुपए देश भर के किसानों के बकाया हैं, इसलिए इसका सबसे ज्यादा लाभ आप ही के राज्य के किसान को मिलने वाला है।

मधुसूदन मिस्त्री जी शायद नहीं बैठे हैं, वे जब बोल रहे थे, तो एक पार्टी की जिन-जिन राज्यों में सरकार है, वहां क्या-क्या होना चाहिए, यह बोल रहे थे। मतलब वे अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे थे कि इन राज्यों में ये सब काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए पहले ये सब काम कीजिए। इन मुद्दों का सूखे से कोई संबंध नहीं है। मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि आप जिनकी ओर इशारा कर रहे थे, इस देश में जिस समय कृषि विकास दर चार प्रतिशत से नीचे थी, उस राज्य की कृषि विकास दर ग्यारह प्रतिशत थी। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि यहां जो भारत सरकार है, उसके आंकड़े कई वर्षों से इस बात को बोल रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, वही व्यक्ति आज देश का नेतृत्व कर रहा है और उस व्यक्ति ने साफ-साफ कहा है कि यदि राजनीति भी करनी होगी, तो पांचवां वर्ष है चुनाव का, उस समय उसकी चिंता करेंगे। आज हम पूरे देश की चिंता करेंगे, देश के किसानों की चिंता करेंगे और गांव की चिंता करेंगे। इस सरकार की प्राथमिकता गांव और किसान हैं। नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में मैं, कृषि मंत्री, एक औजार के रूप में हूं। मैं एक औजार हूं और एक मजबूत औजार के रूप में, नरेन्द्र मोदी, जो इस देश के प्रधान मंत्री हैं, उनका जो सपना है गांव और किसान को मजबूत करने का, हम उस सपने को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। चाहिए आप सबका सहयोग, आप सबका स्नेह, राजनीति से ऊपर उठ कर। किसान की जब चर्चा हो, तब राजनीति मत कीजिए। मैं तो इस भाव से सरकार में काम करता हूं कि यह सरकार है, यह देश की सरकार है, यह किसी पार्टी की सरकार नहीं है, इस भाव से काम करता हूं। आप मेरे भाव को बदलने की कोशिश मत कीजिए और आप भी वैसा ही भाव बनाइए। इसी विनती के साथ हम राज्य और भारत की सरकार मिल कर इस देश के किसानों को समृद्ध बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे, ऐसा हम सब लोग संकल्प लें।

MATTER RAISED IN RESPECT OF MAKING PAYMENTS TO SUGARCANE FARMERS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Members can lay the Special Mentions on the Table. ...*(Interruptions)*...

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): सर, मुझे कृषि मंत्री जी से एक सवाल पूछना है। ...**(व्यवधान)**...